

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16)

भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उसके अन्तर्गत बने नियम एवं संशोधन वनों, वनोपज के अभिवहन, इमारती लकड़ी और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से सम्बद्ध विविध के समेकन के लिए अधिनियम। वनोपजों के अभिवहन और इमारती लकड़ियों और अन्य वनोपज पर उद्ग्रहणीय शुल्क से (सम्बद्ध) विविध का समेकन करना समीचीन है। अतः एतत् नियम निलिखत रूप में वह अधिनियमत किया जाता है-

सार संमह : तात्पर्य - इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पूर्व भारत में भारतीय वन विधान 1878 प्रभावशाली था। इस अधिनियम के बनने के उपरान्त इसके चार संशोधनों, जो 1890, 1901, 1918 एवं 1919 में हुए, का एकीकरण किया गया है। विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों का प्रकाशन भारतीय राजपत्र 1926 खण्ड 5 पृष्ठ 165 में दिया गया है।

मध्य प्रदेश शासन के विविध तथा विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना ब. 12023-XX-I-अ (वि. सं. 74) दिनांक 12 जून, 1974 द्वारा "दी इण्डियन फारेस्ट एक्ट" का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (बर्मांक 19, वर्ष 1963) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रकाशित हिन्दी पाठ म. प्र. राजपत्र भाग 4 (ख) दिनांक 28-5-76 पृष्ठ सं. 441 आदि पर सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया गया है।

अध्याय 1

प्रारम्भिक

धारा 1 - संक्षिप्त नाम विवः तार - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "भारतीय वन अधिनियम, 1927" है।

(2) इसका विवः तार उन राज्य क्षेत्रों को छोड़कर, जो प्रथम नवम्बर, 1956 के ठीक पूर्व भाग 'ख' (Part B) राज्यों में समाविष्ट थे सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उन राज्य क्षेत्रों को लागू है, जो प्रथम नवम्बर 1956 के ठीक पूर्व बिहार, बम्बई, कुर्ग, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पिश्चमी बंगाल में समाविष्ट थे। कोई भी राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम को, पूर्ण राज्य में या उसके किसी विंशत भाग में, जिस पर इसका विवःतार है, पर वहाँ यह प्रवर्तन (Force) में नहीं है, प्रवर्तन में ला सकेगी।

टिप्पणी - मध्य प्रदेश विधान ब. 23, वर्ष 1958 की धारा 3 द्वारा प्रोतिः थापित।

(क) धारा (1) के खण्ड (2) के अंत में निम्न प्रोतिः थापित :

• मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भारत एवं सिरोंज क्षेत्र छोड़कर

(ख) नवीन उपधारा (3) प्रोतिः थापित।

(3) इसका विवः तार मध्य प्रदेश राज्य के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल एवं सिरोंज क्षेत्र पर भी किया जाता है।

यह नियम भारत के संविधानीय परिवर्तन के फलः वरूप एडाप्टेशन लॉ आर्डर 1937, 1950, 1956 में सम्मिलित (Adapt) किया गया।

तदनुसार यह अधिनियम मध्य प्रदेश की रियासतों में दिनांक 25 फरवरी, 1973 से प्रभावशील हुआ।

[G.S.R. 42 (E) दिनांक 1 फरवरी, 1973] धारा 2 - इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो : (1) "पशु" के अन्तर्गत हाथी, ऊँट, भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, खः सी पशु, टट्टू, बछेड़े, बछेड़ियाँ, खच्चर, गधे, सुअर, भेड़ें, भेड़ियाँ, मेमने, बकियाँ, और बकियों के मेमने हैं।

(2) "वन अधिकारी" (Forest Officer) "वन अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभूत है जिसे राज्य सरकार या राज्य सरकार से सशक्त अधिकारी द्वारा किये गये इस अधिनियम के, सब या किसी, प्रयोजन को पूरा करने के लिये, अथवा इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन वन अधिकारी द्वारा किये जाने के लिये आपेक्षित कोई बात करने के लिए नियुक्त करे।

टिप्पणी

वन अधिकारी को वन-भूमि के अतिरिक्त को ऐसी अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर देने या तत् संबंध में समझौता करने का अधिकार नहीं है। (रतनसंह राजपूत वगैः वि. म. प्र. राज्य वगे 2012 (3) म. प्र. लॉ. ज. 173 खंडपीठ, म. प्र.)

(3) "वन अपराध" (Forest Offence) से इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभूत है।

टिप्पणी

"कृत्ता" एवं "कुच" वन उपज की परिभाषा अंतर्गत सिद्ध है। (म. प्र. राज्य वि. सेल्स एजोन् सीज 2005 (1) विविध भाः वर 163 (सु. को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 बि. लॉ. ज. 1832 = 2004 = सु. को. के (बि. 1313)।

(4) "वनोपज" के अन्तर्गत निम्न लिखित वस्तुएँ :

(क) निम्न वस्तुएँ भले ही वन में पाई जावे, वन से लाई गई हों या नहीं यथा

अथार्त् इमारती लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कुचुक, खैर, लकड़ी का तेल, राल (resin), शैलक (Shellac), गोंद, प्राकृतिक वाणिर्श, छाल, लाख, महुआ फूल, महुआ बीज, तेन्तू पत्ता, कुथ (Kuth) और हरार, बहेड़ा, आँवला (myrobalans) हैं।

(ख) निम्न लिखित जब वन में पाई जावे अथवा वन से लाई जावे तब :

- (i) वृक्ष और पत्ते, फूल एवं फल और वृक्षों के इससे पूर्व अविणर्त सब अन्य भाग एवं उपज,
(ii) वे पौधे जो वृक्ष नहीं हैं और जैसे पौधों के सब भाग व उपज या घांस, बेलें नरकुल, काई सहित,

1. म.र. राज् य संशोधन िनयम ब. 9 वर्ष 1965 द्वारा जोड़ा गया।

2. भारतीय वन (म.र. संशोधन) अधि. 1989 (1 वर्ष 1990) के द्वारा तेन् दू पत्ता म. र. (असाधारण) गजट दिनांक 10.1.90 को ूकाशित से जोड़ा गया)

(iii) वन पशु, पशु की खालें, हाथी दांत, सींग, हिड्डयाँ, रेशम, रेशम के कोए, शहद और मोम तथा पशुओं के सब अन्य भाग एवं उत्पादन,

(iv) पीट (peat) सतही मिट्टी (Surface soil), चट्टान (rock) एवं खनिज (minerals) जिसमें चूने के पत्थर, लेटराइट (लाल मुरूम), खनिज तेल और खानों (mines) एवं खदानों से ूपा त िमनरल आईल एवं तेलीय पदार्थ सम्मिलित हैं।

1(4-क) "ः वामी" के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति के बारे में ूतिपाल् य अधिकरण आता है जो ऐसे अधिकरण के अधीक्षण या भार साधन में हैं।

(5) "नदी" के अन्तर्गत कोई सिरता (Stream) नहर (Canal), बीक या अन्य धारा (Channel) है। चाहे ूाकृतिक अथवा बिऽम (Artificial) हो।

(6) "इमारती लकड़ी" के अन्तर्गत वृक्ष आते हैं जो िगर गये हों या िगराये गये हों और समः त लकड़ी, जो िकसी ूयोजन के िलये काटी गई हो (Cut up), फैशन की गई हो (Fashioned) या खोखली की गई हो (Hollowed) या न की गई हो।

(7) "वृक्ष" के अन्तर्गत ताड़, बाँस, टूँठ, झाड़ी, और बेंत ूजाति सम्मिलित हैं।

नोट : (1) इस अधिनियम में 'वन' शब्द की परिभाषा नहीं दी है। ूथम बार 'वन' शब्द की व् याख् या खण् डपीठ नागपुर (A.I.R. Nagpur), लआ मण इच् छाराम िव. वन मण् डलाधिकारी, रायगढ़ के ूकरण में परिभाषित की गई है जो िनम्न है :

'वन' ऐसे भूखण् ड जो वृक्षों एवं छोटे वृक्षों आच् छादित हों, या ऐसा वृक्षों वाला भूखण् ड, जो वन ूाणी िशकार के िलये हो, या िबना काँत की जंगली जमीन हो।

नोट : (2) वन अधिकारी (Forest Officer) भारतीय दण् ड ूबिया संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक (Public Servant) है।

नोट : (3) नमर्दा िकास ूाधिकरण में कार्यरत अधिकारी समक्ष वन अधिकारी हैं।

नोट : (4) चन्दन तेल वन उपज है। खुशबू इन् टरूइज एवं अन्य (सर्वोच् च न् यायालय िव. केरल सरकार (28.5.93))

1. भारतीय वन संशोधन अधिनियम (3) वर्ष 1933 के अन्तर्गत ूति संः थापित

2. म.र. शासन वन िवभाग की अधिसूचना ब. ष-5-खख-84 दस-3 के अन्तर्गत नमर्दा घाटी िकास ूाधिकरण के वन संरक्षक, वन मण् डलाधिकारी, सहायक वन संरक्षक, वन क्षेऽपाल, उपवन क्षेऽपाल, वनरक्षक को समक्ष क्षेऽीय वन अधिकारी िनयुक् त िक्या।

अध् याय 2

आरिक्षत वनों के सम्बन्ध में

धारा 3 - वनों को आरिक्षत करने की शिक्त - राज् य सरकार ऐसी िकसी वन भूमि या पड़त भूमि (Wasteland) जो सरकार की सम्पत्ति है या जिस पर सरकार के सम्पत्ति के अधिकार हैं, या जिसकी वनोपज की पूरी अथवा िकसी भाग की सरकार हकदार है, इसमें इसके पँचात् उपबिन्धत रीति से आरिक्षत वन बना सकेगी।

टिप्पणी - इस धारा में वन भूमि तथा पड़त भूमि शामिल है, चाहे वह िकसी के कब्जे में हो, लेकिन अन्य भूमि तभी इसके अन्तर्गत आवेगी जब वह िकसी के मालिकाना, कब्जे में हो (1980 All LJ NOC 77)।

धारा 4 - राज् य सरकार द्वारा अधिसूचना - जब िकसी भूमि को आरिक्षत वन (Reserved Forest) बनाने का िनँचय कर िलया गया हो तब राज् य सरकार राजपऽ में िनम्न आशय की अधिसूचना जारी करेगी -

(क) यह घोषणा करने वाली िक यह िविनिश्चित िक्या गया है िक ऐसी भूमि को आरिक्षत बनाया जावेगा। (ख) ऐसी भूमि की िःथित एवं सीमा को यथा-सम्भव िविनिर्द् ट करने वाली।

(ग) ऐसी सीमाओं में समािवं ट िकसी भूमि में, या भूमि पर या िकसी वन उपज में या वन उपज पर िकसी व् यिक्त या व् यिक्तियों के अधिकारों के दावों की जाँच एवं

अवधारण करने के िलये और उनके सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही करने के िलये जैसी इस अध् याय में उपबिन्धत है, अधिकारी जिससे इसमें या इसके पँचात् "वन व् यवः थापन अधिकारी" (Forest Settlement Officer) कहा गया है को िनयुक् त करने वाली।

ः पं टीकरण

- (1) खण्ड (ख) के लिये यह पर्याप्त होगा कि वन की सीमाये मागोर् निदयों पुलों या अन्य सुविदित एवं सहज समझी जाने वाली सीमाओं से विणर्त की जावें।
- (2) उपधारा 1 के खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतः ऐसा व्यक्ति होगा जिसने वन विभाग के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य वन पद (Forest Officer) नहीं धारण कर रखा हो।
- (3) इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को, इस नियम के अधीन अधिकतम तीन तक अधिकारी वन व्यवस्थापन अधिकारी का कर्तव्य पालन करने हेतु नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी जिसमें अधिकतम एक अधिकारी "वन अधिकारी" भी हो सकता है।

धारा 5 - अधिकारों के लोद्भूत होने का वर्जन - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त, ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में, या भूमि पर, कोई अधिकार, उत्तराधिकार के जिरये या सरकार द्वारा या ऐसे व्यक्ति या उसकी ओर से जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, जबकि अधिसूचना निकाली गई थी, लिखित रूप में दिये गये अनुदान या की गई संविदा के अधीन विजर्त होने के सिवाय, अजर्त न होगा, न ही राज्य शासन द्वारा बनाये नियमों के अतिरिक्त ऐसी भूमि में कृषि या अन्य लिये कटाई, वनों की सफाई की जा सकेगी।

टिप्पणी धारा 5 : धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये नियमों के अतिरिक्त उक्त वन में लकड़ी कटाई अथवा वनों की सफाई धारा 26 (1) के अन्तर्गत वन अपराध (Forest Offence) है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो।

धारा 6 - वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा उद्घोषणा - धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना लूकाशित होने के उपरान्त वन व्यवस्थापन अधिकारी सम्बन्धित भूमि के आस-पास बसे समुदायों में, जिनकी भाषा में, निम्न उद्घोषणा लूकाशित करावेगा -

- (क) लूकाशित वन की स्थिति एवं सीमाओं को यथा सम्भव विनिर्दिष्ट करने वाली।
- (ख) ऐसे वन के आरक्षण होने पर एवं उसके पतन होने वाले परिणामों तथा उपबन्धों की व्याख्या एवं जानकारी देने वाली सूचना।
- (ग) ऐसी घोषणा करने की तारीख से कम से कम तीन माह की अवधि नियत करने वाली तथा धारा 4 या 5 में विणर्त किसी अधिकार का दावा करने वाले हर व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाली कि वह वन व्यवस्थापन अधिकारी के समक्ष ऐसे अधिकार के स्वरूप का, और उसके सम्बन्ध में दावाकर्ता अधिकार के परिमाण और विशिष्टियों का विनिर्दिष्ट करने वाली लिखित सूचना ऐसी कालाविधि में लूकाशित करे या उपस्थित होकर कथन करे।

टिप्पणी (1) : यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी ने पड़त भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का आक्षेप निरस्त कर दिया है तथा कलेक्टर ने वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन अपील निरस्त कर दी है और ऐसी निरस्त अपील के विरुद्ध कोई निगरानी नहीं लूकाशित की गई हो तो व्यवहार न्यायालयों (Civil Courts) को उस भूमि का मुआवजा दिलाने का अधिकार नहीं है (देखें महालआमी बैंक लि. वि. बंगाल लूकाशित (ए. आई. आर. 1942 कलकत्ता पृष्ठ 371)।

टिप्पणी (2) उपधारा (ग) : के अन्तर्गत केवल वे ही व्यक्ति अधिकार का दावा लूकाशित कर सकते हैं जिनका उस भूमि पर सूचना लूकाशन की तिथि को अधिकार था। धारा 4 के अन्तर्गत सूचना लूकाशन के उपरान्त (Assignee) इस धारा के अन्तर्गत दावा लूकाशित करने का हक नहीं है। इस परिस्थिति में Limitation Act की धारा 5 का भी लाभ नहीं मिलेगा। (1981, All LJ NOC 23)

धारा 7. वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा जाँच - वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन दिये गये अधिकार के दावे से सम्बन्धित दावों की सुविधाजनक ढंग से जाँच करेगा इसके अतिरिक्त, उन अधिकारों की, जो धारा 4 एवं 5 में विणर्त हैं, या शासकीय अभिलेखों में उपलब्ध हैं अथवा जिनकी जानकारी ऐसे व्यक्तियों के कथनों से जिन हैं अधिकारों का ज्ञान है, लेकिन धारा 6 के अन्तर्गत दावा लूकाशित नहीं हुआ है परन्तु उनसे लूकाशित कर उनकी भी जाँच सुविधाजनक ढंग से जाँच करेगा।

धारा 8. वन व्यवस्थापन अधिकारी की शक्तियाँ - ऐसी जाँच के लिये वन व्यवस्थापन अधिकारी निम्न शक्तियों का उपयोग कर सकेगा - अर्थात् -

- (क) किसी भूमि पर, जहाँ वन या इस लिये अपने द्वारा लूकाशित किसी अधिकारी को, लूकाशित करने से पूर्व जाँच करने (To Survey), सीमांकन करने (Demarcate) या उसका नक्शा बनाने की शक्ति और
- (ख) दावों के विचारण में सिविल न्यायालयों की शक्तियाँ।

धारा 9. अधिकारों का निवारण - वे अधिकार, जिनका दावा धारा 6 के अधीन नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व की जानकारी धारा 7 के अन्तर्गत की गई जाँच द्वारा नहीं मिली है, जब तक कि उन अधिकारों का दावा करने वाला व्यक्ति, वन व्यवस्थापन अधिकारी का समाधान कि धारा 6 के अधीन नियत कालाविधि के अन्दर ऐसा दावा न कर सकने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था, धारा 20 के अधीन अधिसूचना के लूकाशित होने के पूर्व नहीं कर देता, निवारित (extinct) हो जावेंगे।

नोट 1. यदि भूमि धारा 3 के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है, तब दावा करने वाले ने समयाविधि में दावा नहीं किया है तो भी उनके दावे निवारित नहीं होंगे। (उत्तर प्रदेश राज्य वि. महन्त अवधनाथ A.I.R. 1977, All.

धारा 10. ः थानान् तरी खेती (Shifting Cultivation) की पद्धति सम् बन् धी दावों का िनराकरण -

- (1) वन व् यवः थापन अधिकारी ः थानान् तरी खेती की पद्धति (Shifting Cultivation) से सम् बिन्धत दावे की अवः था में दावेदारों का कथन िलिपबद्ध करेगा िजनमें बाद का िववरण हो तथा उस िनयम या आदेश का िववरण ूाप् त करेगा, िजसके अन् तर्गत इस ूकार की खेती ूचिलत है, तथा यह कथन एवं िववरण अपनी राय सहित, िजसमें यह ः पं ट करेगा िक इस पद्धति की अनुमित दी जावे या पूर्णतः अथवा अंशतः ूितबिन्धत की जावे, राज् य सरकार को ूः तुत करेगा।
- (2) राज् य सरकार उस कथन एवं राय के ूाप् त होने पर, इस पद्धति को पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात या िनिषद्ध करने वाला आदेश दे सकेगी।
- (3) यदि ऐसी पद्धति पूर्णतः या अंशतः अनुज्ञात की जाती है तो वन व् यवः थापन अधिकारी :
 - (क) बन् दोबः त वाली भूमि की सीमायें इस ूकार बदल दें िक इस पद्धति की खेती हेतु उचित ूकार की, आवँ यक माSा (Sufficient extent), में तथा वािदियों के िलये सुविधाजनक ः थान की भूमि दावदारों के िलये अपविजर्त हो जावे, या
 - (ख) बन् दोबः त वाली भूमि के कितपय ूभागों का पृथक् से सीमांकन (Demarcation) कराकर और उसमें ऐसी शतोर के अधीन, जो िविहृत करे, ः थानान् तरी खेती की पद्धति के िलये दावेदारों को अनुज्ञा देकर उसके ूयोग का ूबन् ध कर सकेगा।
- (4) उपधारा 3 के अधीन िकये गये सब इन् तजाम राज् य सरकार की पूर्वर मन् जूरी के अधीन होंगे।(5) स् थानान् तरी पद्धति से खेती के सम् बन् ध में यह समझा जावेगा िक यह ऐसा िवशेषाधिकार है िजसे राज् य सरकार िनयिन्ऽत, िनबर्न्धित, और उत् सािदित कर सकती है।

धारा 11. ऐसी भूमि को अिजर्त करने की शिक्त िजस पर अधिकार का दावा िकिया गया है - वन व् यवः थापन अधिकारी िकसी भूमि से या पर ऐसे िकसी अधिकार िवषयक िकये गये दावे की दशा में, जो मागर् अधिकार, चराई अधिकार, वनोपज सम् बन् धी अधिकार या जल मागर् सम् बन् धी अधिकार से िभन् न है, उसे पूर्णतः या भागतः मन् जूर या खारिज करने वाला आदेश देगा।

- (2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या अंशतः मंजूर िकिया जाता है तो व् यवः थापन अधिकारी या तो :
 - (i) ऐसी भूमि को ूभावि वन की सीमाओं से अपविजर्त (exclude) करेगा या -
 - (ii) ऐसे अधिकारों के अभ् यपर्ण (surrender) के िलये ः वामी से करार (Agreement) करेगा।(iii) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894का1) द्वारा उपबिन्धत रीति से ऐसी भूमि को अिजर्त करने की कायर्वाही करेगा।
- (3) ऐसी भूमि को इस ूकार अिजर्त करने के िलए :
 - (क) वन व् यवः थापन अधिकारी की बावत यह समझा जावेगा िक वह भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894का1) के अधीन कायर्वाही करने वाला कलेक् टर है।
 - (ख) दावेदार के बारे में यह समझा जावेगा िक वह उक् त अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसार उसके समक्ष हािजर होने वाला िहतबद्ध व् यिक्त है।
 - (ग) इस अधिनियम की पूर्ववर्तीर् धाराओं के उपबन् धों के बारे में यह समझा जावेगा िक उनका अनुपालन हो चुका है, और
 - (घ) दावेदार की सम् मित से, या न् यायालय दोनों पक्षकारों की सम् मित से भूमि के रूप में या भागतः भूमि और भागतः धन के रूप में ूितकर कलेक् टर के अधिकार अनुसार अधिनिर्णर्त कर सकेगा।

धारा 12. चराई या वन उपज पर के दावों के अधिकारों के सम् बन् ध में आदेश- चराई या वन उपज पर अधिकारों से सम् बद्ध दावे की दशा में वन व् यवः थापन अधिकारी उन् हें पूर्णतः या अंशतः मंजूर या खारिज करने वाला आदेश पारित करेगा।

टिप् पणी - (धारा 12) माननीय उच् च न् यायालय ने म. ू. बीकली नोट्स 1978, पाटर् 1, बर्मांक 342) हरार् व् यापारी संघ िव. म. ू. राज् य में यह िनणर्ण ूदान िकिया है िक राज् य शासन को यह अधिकार ूाप् त है िक वह धारा 12 के अन् तर्गत वनोपज का िनवर्तर्न िकसी भी रीति से कर सकता है।

धारा 13. वन व् यवः थापन अधिकारी द्वारा तैयार िकये जाने वाले अभिलेख- वन व् यवः थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय िनम् निलिखत को यथासाध् य अभिलिखत करेगा -

- (क) अधिकार का दावा करने वाले व् यिक्त का नाम, उसके िपता का नाम, जाति, िनवास, उपजीविका, और

(ख)उन सब खेतों या खेतों के समूहों (यदि कोई हों) का नाम, िंथित और क्षेऽफल तथा उन सब भवनों के (यदि कोई हों) नाम और िंथित, िजनके िवषय में अधिकारों का दावा िकिया है।

धारा 14. जहां दावा मंजूर िकिया गया है वहां अभिलेख- यदि वन व् यवः थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन िकसी दावे को पूर्णतः या अंशतः मंजूर कर लेता है, तो वह उन पशुओं की संख् या और िववरण, िजन् हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह ऋतु िजसके दौरान ऐसा चराना अनुज्ञप् त है, उस इमारती लकड़ी और अन् य उपज का पिरमाण िजसे वह

समय-समय पर लेने या पूरा करने के लिये अधिकृत है, और ऐसी अन्य विविधियाँ जैसी उस मामले में अपेक्षित हों, विनिर्दिष्ट करके यह भी अभिलिखित करेगा कि कहाँ तक दावा इस प्रकार मंजूर किया गया है। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावाकृत अधिकारों के दूयोग द्वारा पूरा करने की इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज बेची जा सकेगी या नहीं।

धारा 15. मंजूर किये अधिकारों का दूयोग- वन व्यवस्थापन अधिकारी ऐसे अभिलेख तैयार करने के पक्ष अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार और जिस आरक्षित वन के सम्बन्ध में दावा किया गया है, उनको बनाये रखने का सम्यक ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये अधिकारों का निरन्तर दूयोग सुनिश्चित हो जावे।

(2) वन व्यवस्थापन अधिकारी इस दूयोजन के लिये :

(क) इस प्रकार आरक्षित किये जाने वाले वन खण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा पर्याप्त विस्तार वाला और युक्तियुक्त रूप में सुविधाजनक स्थान में स्थित वन खण्ड को ऐसे दावेदारों के दूयोजन के लिये उपविणर्त कर सकेगा, और इस प्रकार मंजूर किये विस्तार तक यथास्थित चराई या वन उपज का अधिकार प्रदान करने वाला आदेश पारित कर सकेगा।

(ख) दूः तावित वन की सीमाओं को इस प्रकार बदल सकेगा कि दावेदारों के दूयोजनों के लिये पर्याप्त विस्तार की और युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक स्थान की वन भूमि अपविजर्त (exclude) हो जावे।

(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थित, चराई या वन उपज के अधिकार ऐसे मंजूर किये विस्तार तक, आदेशित ऋतु में, तथा दूः तावित वन के ऐसे भागों के अन्दर, और ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये जावें, चालू रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।

धारा 16. अधिकारों का रूपान्तरण (Commutation)- यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी, आरक्षित वन को बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखकर धारा 15 के अन्दर ऐसे व्यवस्थापन करना असम्भव पाता है जिससे इस प्रकार मंजूर किये गये विस्तार तक उक्त अधिकारों का निरन्तर दूयोग सुनिश्चित हो जाता है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जिससे राज्य सरकार इस निमित्त बनावे, उसके बदले में ऐसे व्यक्तियों को धनराशि के संदाय द्वारा, या भूमि के अनुदान द्वारा, या किसी अन्य रीति से, जिसे ठीक समझता है, ऐसे अधिकारों रूपान्तरण कर सकेगा।

धारा 17. धारा 11 धारा 12 धारा 15 एवं धारा 16 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अपील - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त साधारणतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति, दावे पर धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की तारीख से तीन मास के अन्दर ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील राजः विभाग के कलेक्टर से अनमन्य पंक्ति के ऐसे अधिकारी के समक्ष कर सकेगा जिससे राज्य सरकार ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई के लिये राज्य-पक्ष में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे :

परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय, जिसे इसमें इसके पक्ष चाहे वन न्यायालय (Forest Court) कहा गया है, स्थापित कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी और जब यह न्यायालय स्थापित हो जावे तब वैसी सब अपीलें उसके समक्ष दूः तुत की जावेंगी।

नोट : (1) मध्य प्रदेश शासन ने अधिसूचना बर्मांक 1028-3769-10-64 जो मध्य प्रदेश राज्य पक्ष भाग 1 दिनांक 20-11-64 पृष्ठ 2765 में प्रकाशित है, धारा 17 के अधीन अपने क्षेत्रों में जिलाधक्ष (Collector) को अपील सुनने के लिये प्राधिकृत किया है।

टिप्पणी 1. (धारा 17) वन अधिनियम की धारा 17 के अधीन कलेक्टर को अपील सुनने हेतु अधिकृत किया है तो कलेक्टर "परसोना डिज़िगनेटा" (Persona Designeta) है देखें ए.आई.आर. 1967 इलाहाबाद 472, इलाहाबाद लॉ जनरल 1967।

यदि ऐसी अपील के अधिकार कलेक्टर को सौंपे गये हैं तो केवल कलेक्टर दूः वयं ही अपील सुन सकता है।

टिप्पणी 2. इस धारा के अन्तर्गत अपील करने हेतु वन अधिकारी (Forest Officer) को भी प्राधिकृत किया है और वही अपील मेमो पर हस्ताक्षर करेगा। ऐसा वह राज्य शासन की ओर से कर रहा है। (उ.प्र. शासन वि. डिंडिशकट जज, फैजाबाद एवं अन्य, AIR 1971, Allahabad 229)

धारा 18, धारा 17 के अधीन अपील (1) धारा 17 के अधीन हर अपील लिखित अजीर् द्वारा दी जायेगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जावेगी जो उसे सुनवाई के लिये सक्षम अधिकारी को भेज देगा।

(2) यदि अपील धारा 17 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी के समक्ष की जावे तो भू-राजः व से सम्बद्ध मामलों में अपील की सुनवाई के लिये विहित रीति से उसकी सुनवाई की जावेगी।

(3) यदि अपील वन न्यायालय (Forest Court) के समक्ष की जावे, तो न्यायालय, अपील की सुनवाई के लिये कोई दिन, तथा दूः तावित वन के आसपास ऐसा सुविधाजनक स्थान, नियत करेगा और इसकी सूचना पक्षकारों को देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।

(4) अपील पद, यथास्थित, ऐसे अधिकारी द्वारा, न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्य के बहुमत द्वारा पारित आदेश, केवल राज्य शासन के पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए अन्तिम होगा।

धारा 19, अधिवक्ता (Pleaders) - राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी, अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष हाजिर होने, अभिवचन करने (Plead) और अपनी ओर से कार्य करने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

धारा 20. वन: तांबित वन को "आरक्षित वन" (Reserved Forest) घोषित करने की अधिसूचना -

(1) जब किसी निम्नलिखित घटनाएँ घटित हो गई हों, अर्थात् -

(क) जबकि दावा करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत कालाविध समाप्त हो गई हो तथा धारा 6 एवं 9 के अधीन सब दावों का (यदि कोई हों) वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया हो।

(ख) यदि ऐसे दावे किये गये हों तो ऐसे दावों पर वन व्यवस्थापन अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा प्रसीमित कालाविध समाप्त हो गई हो और कालाविध में वन: तुल्य की गई सभी अपीलों का निपटारा अपील अधिकारी या न्यायालय ने कर दिया हो, और

(ग) जबकि वन: तांबित वन में सम्मिलित की जाने वाली सब भूमियाँ (यदि कोई हों) जिन्हें धारा 11 के अन्तर्गत वन व्यवस्थापन अधिकारी ने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (Land Acquisition Act, 1984) के अधीन अर्जित करने के लिये चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित की गई हो।

तब राज्य सरकार प्रसीमन सीमा-चिह्न हों के अनुसार या अन्यथा उस वन की जिसे आरक्षित किया जाता है, सीमाओं को परिनिश्चित रूप से विनिश्चित करने वाली अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से उसे आरक्षित वन घोषित करने वाली अधिसूचना "राजपट" में प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसा वन इस प्रकार नियम तारीख से आरक्षित वन (Reserved Forest) समझा जावेगा।

धारा 20-अ-वन भूमि या पड़त भूमि आरक्षित वन माने जावेंगे- इस अधिनियम या वर्तमान में प्रभावशील कोई अन्य अधिनियम में अन्तर्वर्तित किसी बात के होते हुए भी ऐसे भारतीय राज्य की सीमा के अन्तर्गत की वन भूमि (Forest Land) या पड़त भूमि (Waste Land) उन राज्यों के किसी एककृत राज्य (Integrated State) में विलय होने की तिथि से और अब उस राज्य का भाग होने से इस धारा में अन्य "संविलयित राज्य" के नाम से सम्बोधित किया जावेगा (Merger Territories) -

(i) संविलयन (Merger) की तिथि (1.11.56) के ठीक पूर्व उस समय प्रचलित किसी कानून, रीति-रिवाज (Custom), नियम, अधिनियम, आदेश या अधिसूचना के अधीन जिस भूमि को सम्बन्धित राज्य शासन के "आरक्षित वन" (Reserved Forest) के रूप में मान्यता दी हो, या (ii) किन्तु तिथि के ठीक पूर्व किसी शासकीय रिपोर्ट में समाविष्ट, या किसी कार्य आयोजन (Working Plan) के अनुसार या किसी रजिस्टर में अभिलिखित (Recorded in Register) या रजिस्टर के अनुसार मान्य और किन्तु तिथि के बाद भी जा उस रूप में मानी गई है।

1. मध्य प्रदेश अधिनियम ब. 9 वर्ष 1965 की धारा 20 (अ) द्वारा: थापित

इस अधिनियम के धारकों के लिये "आरक्षित वन" (Reserved Forest) माने जावेंगे।

(2) वन: ना: पद सीमा में प्रभावशील इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, आदेश या अधिसूचना के अभाव में किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के विपरीत होते हुए भी उपधारा (1) में विणर्त कोई विधान, रिवाज, नियम, विनियम, आदेश या अधिसूचना विधिवत् प्रभावशील उसी तरह माने जावेंगे जैसे कि वे नियम, आदेश, अधिसूचना इस नियम के अन्तर्गत ही बनाये गये हैं और वे तब तक प्रभावशील रहेंगे जब तक कि उन्हें निरस्त, परिवर्तन या सुधार विधिवत् न किया जावे।

(3) उल्लिखित कोई रिपोर्ट, कार्य आयोजना या पंजी या उसमें कोई विविष्ट के सम्बन्ध में विवाद, व्यवहार न्यायालय में प: तुल्य नहीं किया जा सकेगा, बशर्ते कि राज्य शासन यह प्रमाणित न कर दे कि किन्तु रिपोर्ट, कार्य योजना या पंजी, किन्तु शासक के प्राधिकार के अन्तर्गत संविलयन की तिथि के पूर्व तैयार किया गया है और उसके बाद राज्य शासन द्वारा उनके प्राधिकार के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है और अविरत एवं प्रचलित है।

(4) संविलयित राज्य सीमा में माम वन, संरक्षित वन या आरक्षित वन के अतिरिक्त अन्य कोई, किसी नाम से ज्ञात या: स्थानीय नाम से ज्ञात मान्यता प्राप्त वन इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित वन (Protected Forest) माने जावेंगे और उपधारा (2) एवं (3) के अन्तर्गत यथा आर्वं एक परिवर्तन सहित (Mutatis Mutandis) प्रभावित होंगे।

पं टीकरण 1. कार्य योजना (Working) से तात्पर्य कोई कार्य-योजना (Plan) प्रयोजना (Scheme), प्रोजेक्ट (Project), नक्शे (Maps), चिह्न (Drawings) एवं अभिन्यास (Layouts) से है जो वन के कार्य, या प्रबंध के दौरान कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये तैयार किये गये हों।

पं टीकरण 2. शासक (Ruler) से तात्पर्य संविलयन की तिथि से पूर्व दरबार शासन से है और: स्टेट गवर्नमेंट (State Government) से तात्पर्य किन्तु तिथि के बाद उत्तराधिकारी शासन से है।

०: पं टीकरण 3. एकीकृत राज् य से तात् पयर् भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (15) में भारतीय राज् य का जो अभिकथन है, वही अथर् होगा।

०: पं टीकरण 4. एकीकृत राज् य से तात् पयर् मध्य प्रदेश राज् य, राजः थान, मध्य भारत राज् य, विन्ध्य प्रदेश और भोपाल राज् य जो 1.11.56 के पूर्व विद्यमान थे, होगा।

नोट - आरक्षित वन में वन अपराध होने पर उसका न्यायालय में चालान करते समय "आरक्षित वन" प्रमाणित करने के लिए धारा 20 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना आवेक्यक होती है। (अब्दुल वहाव वि. राज् य, MPLJ 1963 SN 37)

[(1969) 35 Cut. LT पृष्ठ 343]

(1970)-36 Cut. LT 395

धारा 21. ऐसी अधि सूचना के अनुवाद का वन के आस-पास के मामों में प्रकाशन - ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तिथि के पूर्व, वन अधिकारी, इस अधिसूचना का ०: स्थानीय भाषा में अनुवाद कराकर वन के आसपास के हर नगर एवं गाँव में प्रकाशित करावेगा।

धारा 22. धारा 15 या 18 के अधीन किये गये प्रबंध का पुनरीक्षण करने की शक्ति - राज् य सरकार, धारा 15 या 18 के अधीन किये गये किसी प्रबंध का पुनरीक्षण धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन के पांच वर्ष के अन्तर कर सकेगी। धारा 15 या 18 के अधीन किसी आदेश को इस प्रयोजन के लिये विखण्डित (Resuned) या रूपान्तरित (Modify) कर सकेगी और निदेश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों में से कोई कार्यवाही ऐसी कार्यवाहियों में से किसी अन्य के बदले में की जावे या धारा 12 के अधीन मन्जूर किये गये अधिकारों का धारा 16 के अधीन रूपान्तरण (Commute) किया जावे।

धारा 23. आरक्षित वन में कोई अधिकार इसमें उपबिन्धित रीति के अनुसार अर्जित होने के सिवाय अर्जित नहीं होगा- आरक्षित वन में या उस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार, केवल उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा, जिसमें ऐसा अधिकार धारा 20 के अधीन जारी अधिसूचना के समय निहित था, या उसकी ओर से दिये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा के अधीन अर्जित किये जाने के सिवा, अर्जित नहीं होगा।

टिप्पणी

वन-भूमि के अतिरामकों को पट्टे पर देने की शक्ति राज् य शासन को नहीं है। वह इस संबंध में समझौता करने की शक्ति भी नहीं रखती है। (रतनसिंह राजपूत वगै. वि. म.प्र. राज्य वगै. 2012 (3) म.प्र.लॉ.ज.

173 (खण्ड पीठ, म.प्र.)।

धारा 24. बिना प्रकीर्णित अधिकारों का अन्य संबन्ध (Alienated) न किया जावेगा-धारा 23 में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसा कोई अधिकार जो धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखा गया है, राज् य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान द्वारा, विवय द्वारा, पट्टे बन्धक (Mortgage) या अन्यथा अन्य संबन्धित न किया जावेगा।

परन्तु जब कि ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या गृह से अनुलग्न (Appended) है तब वह ऐसी भूमि या गृह के साथ बेचा या अन्य संबन्धित किया जा सकता।

(2) ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में अभिप्राय कोई इमारती लकड़ी या वन उपज, उस मास तक के सिवाय जो धारा 14 के अधीन आदेश में मंजूर की गई हो, बेची या विनिमय नहीं की जा सकेगी।

धारा 25. आरक्षित वनों में के पथ एवं जल मार्गों को बन्द करने की शक्ति- वन अधिकारी, आरक्षित वन में किसी लोक या प्रायवेत मार्ग या जल मार्गों को राज् य सरकार अथवा उसके निमित्त तत्सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व प्रकीर्णित से बन्द कर सकेगा, परन्तु वह यह तभी कर सकेगा जबकि इस प्रकार बन्द किये मार्ग या जल मार्ग की बजाय ऐसा प्रकीर्णित ०: स्थानीय पथ या जल मार्ग जिसको राज् य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझती है, पहले से ही विद्यमान है या वन अधिकारी द्वारा उसके बदले में उपबिन्धित या सिन्निर्मित (Constructed) किया गया है।

टिप्पणी - धारा 25 वन विभाग द्वारा निम्नित वन मार्ग सार्वजनिक मार्ग नहीं है तथा वन विभाग ऐसे मार्गों के उपयोग को निन्निस्त कर सकता है। वन विभाग द्वारा वन मार्ग पर शक/बस के परिवहन हेतु शुल्क वसूल करना संविधान के आर्टिकल 265 के विपरीत नहीं है, बल्कि ऐसी सेवा देने के उपलब्ध य में हैं। (आनन्द शांस्पोटर् कं. प्रायवेत लि. वि. वन मण्डलाधिकारी - रायपुर (दिक्षण) वन मण्डल AIR 1959, Madhya Pradesh, 224)

धारा 26. ऐसे वनों में प्रतिषिद्ध कार्य- (1) कोई व्यक्ति जो -

(क) धारा 5 के अधीन प्रतिषिद्ध नई कटाई, सफाई करेगा या

(ख) आरक्षित वन में या उस क्षेत्र की भूमि में जिसके सम्बन्ध में राज् य सरकार द्वारा धारा 4 के अन्तर्गत आरक्षित वन बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है, आग लगावेगा, या राज् य सरकार द्वारा बनाये किसी नियमों का उल्लंघन करते हुए ऐसी रीति से आग जलावेगा या जलते छोड़ देगा जिससे ऐसे वन संकटापन्न हो जावे।

या जो आरक्षित वन में

(ग) ऐसी ऋतुओं में, के जिसवाय, जिन् हैं वन अधिकारी इस निमित्त त अधिसूचित करे, कोई व्यक्ति न तो आग जलावेगा, रखेगा या ले जावेगा।

(घ) पशुओं का अतिचार (Trespass) करेगा, या पशु चरायेगा या पशुओं के अतिचार करने की अनुमित (Permit) देगा।

(ङ) किसी वृक्ष की कटाई या उसे ले जाने में लापरवाही से वन को हाँन पहुँचाएगा।

(च) किसी वृक्ष को काटेगा (Fells), वृक्षके सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर गहरा घाव (Girdle) बनायेगा, छाँटेगा (पत्ती या डाल काटना) (Lopping), छेवेगा (गोंद आदि निकालने के उद्देश्य से घाव बनाना) (Tap), या उसे जलाएगा, या उसकी छाल उतारेगा या पित्तियाँ तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुँचाएगा। या किसी अन्य वन उपज को नुकसान पहुँचावेगा। (छ) पत्थर की खुदाई करेगा (Quarries), चूना अथवा लकड़ी की कोयला फूँकेगा (Burns) या किसी वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या विनिमार्ण की वृक्षों में वनोपज का संमहण या परिवहन करेगा।

(ज) खेती या अन्य योजना के लिये किसी आरक्षित वन की सफाई करता है, या तोड़ता है या काँत करता है या अन्य विधि से काँत करने का प्रयास करता है।

(झ) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उल्लंघन में शिकार खेलेगा, गोली चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल विषैला करेगा या पाश या जाल बिछाएगा, या

(ञ) ऐसे किसी क्षेत्र में जहाँ हाथी परिरक्षण नियम, 1879 (1879) का 6 प्रवृत्त नहीं है,

इस प्रकार बनाये गिन् ही नियमों के उल्लंघन में हाथियों का वध करेगा या उन पर पकड़ेगा। या वन को नुकसान पहुँचाने के कारण, ऐसे व्यक्ति को शिकार के अतिरिक्त जिसका संदाय किया जाना, जिससे दोष करने वाला न्यायालय निर्णय करे या ऐसी अवधि के कारावास से जो 1 (एक वर्ष) तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 2 (दो हजार) रूपया तक हो सकेगा या दोनों से निम्नलिखित किया जायेगा।

(2) इस धारा की बात के बावत यह न समझा जायेगा कि वह -

(क) वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा या राज्य सरकार द्वारा बनाये गये किसी नियम के अधीन किये गये कार्य, को या

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन चालू रखे गये या सरकार द्वारा या उसकी ओर से धारा (23) के अधीन किये गये अनुदान या की गई लिखित संविदा द्वारा दत्त किसी अधिकार के प्रयोग को प्रतिषेध करती है।

(3) जब किसी आरक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है तब (इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शांति लगाई गई है) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी भाग में चराई या वनोपज से सम्बन्धित सब अधिकारों का प्रयोग उतनी कालाविधि के लिये निजतनी वह ठीक समझती है, निम्नलिखित रहेगा।

1. म. प्र. अधिनियम ब. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

2. म. प्र. अधिनियम ब. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

टिप्पणी

आधुनिक सूचना अपराध को प्रभावित करने हेतु महत्वपूर्ण लेखक है। उसके लिखे जाने में विलम्ब बड़ा बाधापूर्ण सोच का जनक होता है। ऐसी परिस्थिति में दोष सिद्ध संभव नहीं होती है। (म. प्र. राज्य वि. जमादार 2004 (1) मिनसा 27 (म. प्र.))।

आरक्षित वन क्षेत्र में वहाँ की भूमि को खोदकर निकाला गया फलेग : टोन शक में रख दिया जाने के उपरान्त उसे उसी वन क्षेत्र की परिसीमा में निम्न उपरान्त शक के समय हरण की कार्यवाही वैध थी। (म. प्र. राज्य वि. शब् बीर खान, 2006 (2) म. प्र. लॉ. ज. 50 (म. प्र.))।

(1) धारा 26 (1) के अन्तर्गत अपराध में यहाँ प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरक्षित वन से लकड़ी काटी गई एवं ले जाई गई। यह सबूत करने का अभियोजन पक्ष का उत्तरदायित्व है। (AIR 1959, SC 147)

(2) वन भूमि से वृक्ष गिराना नहीं, ले जाना भी अपराध है।

(3) मध्य प्रदेश संशोधित 9, वर्ष 1965 काफी व्यापक है संशोधित प्रमाणन के अनुसार यह प्रमाणित करना काफी है कि अपराधी काँत करता है या काँत करने का प्रयास करता है चाले वह; वह व्यक्ति न हो जिसने सर्वप्रथम की थी। अपराधी की दलील कि वन भूमि पर पूर्व से की काँत होती आ रही है मानने योग्य नहीं है। अपराधी काँत करने का दोषी है।

(State Vs. Jaimal, 1974 MPLJ SN 117, AIR 1924 Nag. 190 Dist.)

(4) मध्य प्रदेश बीकली नोट्स 1983 ब. 379 कान्तिनलाल वि. म. प्र. शासन, में यह निर्णय प्रदान किया गया है कि धारा 26 (1) सहपिठत धारा 379 भा. द. वि. के अपराध में आरोप लगाने के लिये सारभूत कारण प्रथम दर्शनीय उपबन्ध है कि अभियुक्त के पास इस सम्बन्ध में कोई युक्तिसंगत : पं टीकरण या समाधान कारक उत्तर नहीं है कि उसने ताजी काटी गई काफी मात्रा में इमारती लकड़ी का

आधिपत्य कैसे प्राप्त किया है।

ऐसी स्थिति में माननीय उच्च-न्यायालय ने द.सं. 1973 की धारा 482 के अधीन आपराधिक आरोप को निरस्त करने का आदेश दिया: वीकार किया है।

(5) कोई व्यक्ति, उस वन भूमि में (जिसके आरक्षित करने के शासन की मंशा के अनुरूप धारा 4 के अन्तर्गत सूचना जारी कर दी है लेकिन धारा 6 अथवा 20 की कार्यवाही शेष है) का तब तक के लिये भूमि तोड़ता है, तब यह काफी है कि धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी हो गई है तथा धारा 20 के अन्तर्गत अधिसूचना आवँयक नहीं है। (1972 Cri L.J. 706)

(6) उपधारा (घ) के अन्तर्गत वन अपराध में लिप्त तपशु भी उसी प्रकार राजसात (Confiscation) के

योग्य है जिस प्रकार अवैध इमारती लकड़ी का परिवहन करते गाड़ी बैल AIR 1938 Nag. 385) (7) प्रत्येक वृक्ष को काटना अलग-अलग अपराध है कोई व्यक्ति जिसने वृक्ष काटेगा उसने अपराध करेगा।

(AIR 1918 All. 351)

धारा 27. यह घोषित करने की शक्ति कि वन आरक्षित वन नहीं रहा है - (1) राज्य सरकार राजपद में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन कोई आरक्षित वन या उसका भू-भाग, ऐसी अधिसूचना द्वारा नियम तारीख से, आरक्षित वन नहीं रह जावेगा।

(2) इस प्रकार उक्त तारीख से ऐसा वन या उसका भू-भाग आरक्षित वन नहीं रह जावेगा किन्तु उसमें वे अधिकार (यदि कोई हो) जो निवारित (extinguished) हो गये हों, ऐसा न रहने के परिणाम: वरूप पुनर्जीवित (Revive) नहीं हो जावेंगे।

अध्याय 3

माम वनों (Village Forest) के सम्बन्ध में

धारा 28. माम वनों का नियम - (1) राज्य सरकार किसी ऐसी भूमि के प्रति या उस पर, जो आरक्षित वन (Reserved Forest) कर दी गई है किसी माम समुदाय को शासन के अधिकार समनुदेशित कर सकेगी और समनुदेशन (Assignment) रद्द कर सकेगी। इस प्रकार समनुदेशित वन "माम वन" कहा जावेगा।

(2) जिस माम समुदाय (Village Community) को ऐसा समनुदेशन किया गया है, उस माम समुदाय के लिये इमारती लकड़ी, या अन्य वन उपज या चराई का उपबन्ध निम्न शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, उन्हें ऐसे वन के संरक्षण एवं सुधार के लिये, उनके कर्तव्यों को विहित करने वाले नियम राज्य सरकार माम वनों के उपबन्ध को विनियमित करने के लिये बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के वे सब उपबन्ध, जो आरक्षित वनों से सम्बद्ध हैं, वहाँ तक (जहाँ तक कि वे इस प्रकार बनाये नियमों से असंगत नहीं हैं) माम वनों को लागू होंगे।

अध्याय 4

संरक्षित वनों के सम्बन्ध में

धारा 29. संरक्षित वन - (1) राज्य सरकार राजपद में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगी कि इस अध्याय के उपबन्ध, किसी वन भूमि या पड़त भूमि (Waste Land) में जो आरक्षित वन नहीं है, परन्तु वह शासन की सम्पत्ति है या उस पर शासन का सम्पत्तिक अधिकार है, या कुछ या सम: त वन उपज जिसका शासन हकदार है, लागू होंगे। (2) इस अधिसूचना में सम्मिलित सम: त वन भूमि या पड़त भूमि को 'संरक्षित वन' कहा जावेगा। (3) ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जावेगी जब तक उस भूमि पर सरकार या प्रायवेत व्यक्तियों के अधिकारों के विरुद्ध और वि: तार की जाँच नहीं कर ली जाती और सर्वेक्षण या बन् दोब: त अभिलेख में या अन्य किसी ऐसी रीति से, जैसी राज्य सरकार पर्याप्त समझती है, उन्हें अभिलिखित नहीं कर लिया जाता, तथा ऐसे हर अभिलेख के बारे में यह उपधारणा (Presumed) की जावेगी कि वे सही (Correct) हैं जब तक कि प्र: तिकूल (Contrary) साबित न कर दिया जावे:

परन्तु यदि किसी वन भूमि या पड़त भूमि की बाबत राज्य सरकार, यह समझती है कि ऐसी जाँच एवं अभिलेख आवँयक है, किन्तु उनमें इतना समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकार खतरे में पड़ जावेंगे, तो राज्य सरकार ऐसी जाँच लिम्बत रहने तक ऐसी भूमि को संरक्षित वन घोषित कर सकेगी, किन्तु इससे किसी व्यक्ति या समुदाय के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे।

धारा 30. वृक्ष आदि को आरक्षित करने की अधिसूचना निकालने की शक्ति - राज्य सरकार राजपद में अधिसूचना द्वारा -

(क) संरक्षित वन के किन्हीं वृक्षों या वृक्षों के वर्ग (class of trees) को अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से आरक्षित घोषित कर सकेगी।

(ख) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर उस वन के किसी भाग को अधिकतम तीस वर्ष तक, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, बन्द कर सकेगी, तथा इस कालाविध में ऐसे प्रभाग पर प्रायवेत व्यक्तियों के अधिकार, ऐसी अवधि के दौरान निलिम्बत रहेंगे, परन्तु यह तभी होगा जब ऐसे वन का शेष भाग पर्याप्त हो तथा वह उस क्षेत्र के व्यक्तियों, निम्नलिम्बत हुए हैं, के प्रयोग के लिये पर्याप्त तथा युक्तियुक्त त: थान में हो, या

(ग) ऐसे वन की किसी भूमि में पत्थर निकालना (Quarrying of stones), चूने का भट्टा लगाना (Burn Lime) या कोयला बनाना (Burn Charcoal), वन उपज का संग्रहण कर विनिर्माण की रूढ़िबद्ध करने, या वन उपज का परिवहन करने (Removal) और वन में काँत करने, भवन बनाने या पशुओं को रोधने (Herding of Cattles) या अन्य कारण से वनों की सफाई करना और भूमि तोड़ना पूर्वोक्त नियत तारीख से रूढ़िबद्ध कर सकेगी।

धारा 31. अधिसूचना के अनुवाद का आस-पास के क्षेत्रों में प्रकाशन - कलेक्टर, धारा 30 के अनुतर्गत निकाली गई अधिसूचना का अःथानीय भाषा में अनुवाद कराकर संदिग्ध वन के आस-पास के रूढ़िबद्ध एक माम व नगर में सहज दृश्यःथान लगवायेगा।

धारा 32. संरक्षित वनों के बारे में नियम बनाने की शक्ति - राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के विनियमन के लिये नियम बना सकेगी, अर्थात्

(क) वृक्षों और इमारती लकड़ी की कटाई (Cutting) चिराई (Sawing), संपरिवर्त (Conversion), करना और हटाना (Removal) तथा संरक्षित वन की वनोपज का संग्रहण (Collection), विनिर्माण (Manufacture) या परिवहन (Removal)।

(ख) संरक्षित वन के समीप के नगरों एवं माम के निवासियों को अपने उपयोग के लिये वृक्ष, इमारती लकड़ी या वन उपज लेने हेतु अनुज्ञप्ति लेना (License) और ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियों का पेश और वापस किया जाना।

(ग) व्यापार के रूढ़िबद्धों के लिये वनों से वृक्षों, या इमारती लकड़ी को काटने (Felling) या हटाने (Removing) एवं अन्य वन उपज का परिवहन करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्तियाँ (License) प्रदान करना और ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी अनुज्ञप्तियाँ पेश और वापस किया जाना।

(घ) खण्ड (ख) एवं (ग) में विणर्त व्यक्तियों द्वारा जैसे वृक्षों को काटने अथवा इमारती लकड़ी या वन उपज संग्रहित करने एवं हटाने की अनुज्ञा के लिये, किये जाने वाले भुगतान (Payments) यदि कोई हों।

(ङ) ऐसे वृक्षों इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के बारे में किये जाने वाले अन्य भुगतान (Payment) और वेःथान जहाँ ऐसा संदाय किया जावेगा।

(च) ऐसे वनोपज को जो संरक्षित वन से बाहर जावे, जांच कराने के सम्बन्ध में।

(छ) ऐसे वनों में खेती या अन्य रूढ़िबद्ध के लिये भूमि की कटाई, सफाई और भूमि तोड़ना। (ज) ऐसे वनों में पड़ी इमारती लकड़ी एवं धारा (30) के अनुतर्गत आरक्षित वृक्षों की अग्न से सुरक्षा।

(झ) ऐसे वनों से घास कटाना एवं पशु चराना।

(ञ) ऐसे वनों में शिकार खेलना, गोली चलाना, मछली पकड़ना, जल विषैला करना, पाश या जाल बिछाना और ऐसे वनों के उन क्षेत्रों में जहाँ हाथी परिरक्षण अधिनियम, 1879 (1797 का 6) रूढ़िबद्ध वृत्त नहीं है, हाथियों को पकड़ना।

(ट) धारा (30) के अधीन वन के किसी बन्द रूढ़िबद्ध का संरक्षण और रूढ़िबद्ध और

(ठ) धारा (29) में निर्देशित अधिकारों का रूढ़िबद्ध।

टिप्पणी (1) - (1) मध्य प्रदेश शासन मोहलाइन पत्तों को ठेके पर दे सकता है तथा शासन को ऐसे पत्तों को घोष विवय के लिये विवश नहीं किया जा सकता (देखें 1965, एम.पी.एल.जे. टिप्पणी 129)।

टिप्पणी (2) - अधिकार शुल्क केवल उन पर लगाई जा सकती है जो संरक्षित वन से उपज लें। (सूरजदीन वि. शासन 1960 रा. नि. 39)।

धारा 33. धारा 30 की अधिसूचना या धारा 32 के अधीन बने नियमों के उल्लंघनों के लिये शक्तियाँ - (1) जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात् -

(क) धारा 30 के द्वारा आरक्षित किसी वृक्ष, वन या वनोपज को गिरायेगा (Fells), वृक्ष को सूखने के उद्देश्य से उसके चारों ओर घाव करेगा (Girdles), पत्ते या डाल छाटेगा (Lopping), गोंद आदि निकालने के लिये छेवेगा (Taps) या उसकी छाल या पत्ती निकालेगा (Strips off the Break or leaves) या अन्य प्रकार से वृक्ष को हानि पहुँचावेगा।

(ख) धारा 30 के अधीन वाले किसी रूढ़िबद्ध (Prohibition) के रूढ़िबद्ध (Contrary) पत्थर की खुदाई (Quarry) करेगा, या चूने का भट्टा लगावेगा (Burns Lime) या कोयला बनावेगा (Burns Charcoal) या किसी वन उपज का संग्रहण करेगा, और उससे कोई विनिर्माण रूढ़िबद्ध चलावेगा या किसी वनोपज को हटावेगा।

2(ग) किसी संरक्षित वन में धारा 30 के अधीन किसी रूढ़िबद्ध के रूढ़िबद्ध, किसी भूमि को खेती या अन्य रूढ़िबद्ध के लिये तोड़ेगा या साफ करेगा काँत करेगा या काँत करने का रूढ़िबद्ध न करेगा या अन्य विधि से काँत करेगा (Cultivate in any other manner),

(घ) ऐसे वन में आग लगावेगा या बिना युक्तियुक्त पूर्ण सावधानी बरते आग जलावेगा जिससे धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को, चाहे वह खड़ा हो, गिर गया हो, या गिराया गया हो, क्षति पहुँचे या धारा 30 (ख) के अधीन ऐसे बन्द किये क्षेत्र में फैल जावे।

1. म. रू. अधिनियम ब. 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

2. म. रू. अधिनियम ब. 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

(ड) ऐसे किसी वृक्ष या बन्दूक भाग के समीप में उसके द्वारा जलाई आग को जलती छोड़ देगा। (च)

किसी वृक्ष को इस प्रकार गिरावेगा या इमारती लकड़ी को इस प्रकार हटावेगा कि जिससे धारा

30 के अन्तर्गत आरक्षित वृक्ष को हानि पहुँचे।

(छ) इस प्रकार के वृक्ष को पशुओं के द्वारा हानि पहुँचावेगा।

(ज) धारा 32 के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का अतिक्रमण (Infringe) करेगा।

(1) वह उस अविध के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पन्निह हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जब किसी संरक्षित वन में जान-बूझकर या घोर उपेक्षा द्वारा आग लगाई जाती है, तब राज्य सरकार इस बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन कोई शांति लगाई गई है, निर्देश दे सकेगी, कि ऐसे वन में या उसके किसी भाग में चराई या वनोपज के किसी अधिकार का उपयोग उतनी अविध के लिये जितना राज्य सरकार ठीक समझती है, निलम्बित करेगा।

टिप्पणी - (1) यदि कोई व्यक्ति अनिधकृत रूप से संरक्षित वन में प्रवेश करे तो उस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 33, अथवा भा.द.वि. की धारा 447 के अधीन मामला चलेगा।

(2) बिमिनल लॉ जर्नल (Criminal Law Journal), 1983 पृष्ठ 64 पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णय किया है कि धारा 33 के वन अपराध में नरम रूख नहीं अपनाया चाहिए, इस धारा के अधीन कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।

इस निर्णय में भारतीय उच्च न्यायालय ने वन से सम्बन्धित अपराध पर वन अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई निम्न ठा से करने का बल दिया है।

(3) धारा 33 (1)(क) के अन्तर्गत अपराध जमानत योग्य (Cognizable Offence) है। और अपराधी को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

धारा 34. इस अध्याय की कोई बात कितपय मामलों में किये गये कार्यों का प्रतिषेध नहीं करेगी - इस अध्याय की कोई बात

की बावत यह नहीं समझा जावेगा कि ऐसे किसी कार्य का प्रतिषेध करती है जो वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा से या धारा 32 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है, जो धारा 29 के अधीन अभिलिखित किसी अधिकार के उपयोग में, या धारा 30 के अधीन बन्दूक किये गये किसी वन के भाग के विषय में, या किन्हीं उन अधिकारों के विषय में जिनका उपयोग धारा 33 के अधीन निलम्बित किया गया है, किये जाने के अलावा किया गया है।

134 अ. संरक्षित वन नहीं होने की घोषणा की शक्ति - राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसे संरक्षित वन या उसके भाग को "संरक्षित वन" न होने की अधिसूचना निर्गमित कर सकता है।

इस प्रकार नियत तिथि से संरक्षित वन या उसे भाग 'संरक्षित वन' नहीं रहेंगे किन्तु वे अधिकार, (यदि कोई हो) जो समाप्त हो गये हैं, संरक्षित वन की समाप्ति पर पुनः जीवित नहीं होंगे।

1. म. रू. अधिनियम ब. 9 वर्ष 1965 से धारा 34 (अ) जोड़ी गई।

अध्याय 5

जो वन और भूमियाँ सरकार की सम्पत्ति नहीं हैं उन पर नियंत्रण के सम्बन्ध में

धारा 35. विशेष योजनाओं के लिये वनों का संरक्षण - (1) राज्य सरकार राजपट में किसी अधिसूचना द्वारा किसी वन या पड़त भूमि (Waste land) में :

(क) खेती के लिये भूमि तोड़ना या साफ करना।

(ख) पशु चराना (या)

(ग) वनः पित (Vegetation) को जलाना या साफ करना।

(घ) पौधों या वृक्षों का काटना।

उस सूरत में विनियमित या प्रतिषेध कर सकेगी जिसमें कि ऐसा विनियमित या प्रतिषेध निम्नलिखित योजनाओं में से किसी एक के लिए आवश्यक होती है अर्थात्

(i) आंधी (Storms), तेज हवा (Winds), लुढ़कते पत्थर (Rolling Stones), बाढ़ (Floods), और हिमानी (Avalanches) से संरक्षण।

(ii) पहाड़ी भूभागों के शिखरों, ढलानों एवं घाटियों पर मृदा का पिररक्षण (Soil preservation), भूः खलन (Landslips) या खादर (Ravines) और बेगधारा (Torrents) के बनने से रोकना, या भूमि का कटाव (Soil erosion) या उस पर बालू, पत्थर, बजरी के जमाव से भूमि का संरक्षण।

(iii) झरना (Springs), नदियों, तालाबों में जलपूर्ति बनाये रखना।

(iv) मागोर्, पुलों, रेलों के संचार मार्ग एवं अन्य मागोर् का संरक्षण। (iv-a) वनों की हानि को रोकने एवं वनों के विकास एवं सुरक्षा के लिये।

(v) लोक ः वा: थ् य (Public Health) का पिररक्षण (Preservation)

(2) राज् य सरकार, िकसी ऐसे ूयोजन के िलये, ऐसे संकल् प कायर् (Works), जैसे वह ठीक समझती है, िकसी वन या पड़त भूमि पर अपने व् यय से बनवा सकेगी।

(3) जब तक िक ऐसे वन या भूमि के ः वामी को इस बात के समाहित करने वाली सूचना दे दी गई हो िक तुम ऐसी सूचना से िविनिदं ट, युक्तियुक् त कालाविध के अन् दर यह हेतुक दिशर्त करो, िक यथािंथित ऐसी अधिसूचना क् यों न िनकाली जावे या संकल् प (Work) क् यों न बनाया जावे और जब तक िक उन अपेक्षाओं की, यदि कोई हों, और िकसी साआ य की, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, सुनवाई उस अधिकारी द्वारा न की जा चुकी हो जो इस िनिमत् त सम्यक् रूप से िनयुक् त िकिया गया हो, और राज् य सरकार उस पर िवचार न कर चुकी हो, तब तक धारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना नहीं िनकाली जावेगी और न ही उपधारा (2) के अधीन कोई कायर् (Work) आरम् भ िकिया जावेगा।

धारा 36. वनों का ूबन् ध संभालने की शिक्त् - (1) 35 के अधीन िकसी िविनमय या ूतिषेध की अपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में या, उस धारा के अधीन होने वाले संकल् प (Work) के ूयोजनाथर्, राज्य सरकार ऐसे वन या भूमि के ः वामी को िलिखत सूचना के पँ चात् तथा उस सूचना पर उसके आक्षेपों की सुनवाई के पँ चात् उसे वन अधिकारी के िनयंण के अधीन कर सकेगी और घोषित कर सकेगी िक आरिक्त् वनों से सम् बन्ध इस अधिनियम के सब उपबन् ध या उसमें से कोई उपबन् ध इस भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के ूबन् ध से उत् पन् न होने वाले शुद्ध लाभ, यदि कोई हों, तो उक् त भूमि के ः वामी को िदये जावेंगे।

1. म. ू. अधिनियम ब. 26 वर्ष 1950 से (IV-a) जोड़ा गया।

2. म. ू. अधिनियम ब. 26 वर्ष 1950 द्वारा धारा 36 (3) जोड़ी गई।

1(3) शुद्ध लाभ की गणना करते समय वन के कायर् एवं ूबन् ध में कुल िकिये गये खर्च की गणना, गणना की िति थि तक तथा कायर् व ूबन्ध से ूाप् त कुल लाभ में समायोजित कर िनकाली जावेगी।

(4) उपधारा (3) के ूयोजन के िलये :

(अ) कुल आय की गणना में वनोपज के सम् बन् ध में वन अपराधों में की गई जिप्तयाँ (जो अपराध भूमि ः वामी ने नहीं िकिये हों) के राजसात् से ूाप् त कीमत होगी उसमें से सूचना देने वाले को कोई पारितोषिक िदया होगा वह घटाये जाने के बाद शेष राशि बचेगी, वह होगी।

(ब) कुल खर्च में िनम् न खर्च सिमिलत िकिये जावेंगे -

(i) कुल आय का 20 ूतिशत राज् य सरकार को पयर्वेक्षण व् यय (Supervision Charges) के रूप में देय होगा।

(ii) ऐसे वन के राज् य सरकार के ूबन् ध में आने की ितिथ के पँ चात् भूमि ः वामी द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत या कोई अजर्त्त लाभ।

(iii) वन ूबन् ध के सम् बन् ध में वन-िवभाग के कमर्चािरियों को िदये गये वेतन एवं अन् य भत् ते।(iv) ऐसे अन् य आकिःमक व् यय, जो वन अधिकारी द्वारा िकिये गये हों िजिनमें वन-उपज (Article) के संमहण, पिरवहन या िवबय का व् यय तथा वन-उपज के जप् त (forfeit), या राजसात् (Confiscate) का व् यय सिमिलत होगा।

धारा 37. कुछ अव: थाओं में वनों का ः वत् व हरण - (1) इस अध् याय के अधीन ऐसे िकसी मामले में िजसमें राज् य सरकार यह समझती है िक वन या भूमि को वन अधिकारी के िनयन् ऽण में रखने के बजाय उसे लोक ूयोजन के िलये अजर्त्त िकिया जावे, तब राज् य सरकार, भूमि अजर्त्त अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबन्धित रीति से उसे अजर्त्त करने के िलये कायर्वाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 में समािवं ट िकसी अधिसूचना की तारीख से अन् यून तीन वर्षोर् में या अनिधक बारह वर्ष के अन् दर िकसी भी समय भूमि ः वामी यह अपेक्षा कर सकेगा िक ऐसा वन या भूमि यदि लोक ूयोजन के िलये अजर्त्त की जाना आवँ यक हो तो राज् य सरकार ऐसे वन या भूमि को अजर्त्त कर लेगी।

धारा 38. ः वािमियों की ूाथर्ना पर वनों का संरक्षण - (1) िकसी भूमि का ः वामी, या उसके एक से अधिक ः वामी हैं, तो उनमें से कम से कम दो ितिहाई अंशों के ः वामी, इस दृष्टि से िक इस भूमि पर रोपण या संरक्षण िकिया जावे, कलेक् टर को अपनी इस इच् छा का िलिखत अभ् यावेदन कर सकेगा या कर सकेंगे िक -

(क) हमारी ओर से ऐसी भूमि का आरिक्त् त या संरिक्त् त वन के रूप में, वन अधिकारी द्वारा, ऐसे िनबर्न् धनों के अधीन जो पर: पर करार पाये जावें ूबन् ध िकिया जावे।

(ख) इस अधिनियम के सब उपबन् ध या कोई उपबन् ध (Provisions) ऐसी भूमि को लागू कर िदए जावें।

(2) दोनों में हर अव: था में, राज् य सरकार ऐसी भूमि को इस अधिनियम के ऐसे उपबन् ध राजपऽ में अधिसूचना द्वारा लागू कर सकेगी िजसे वह ऐसी भूमि की पिरिःथितियों में उचित समझते हों और जो आवेदकों द्वारा वांछित हो।

अध् याय 6

इमारती लकड़ी और अन् य वन-उपज पर शुल्क के संबंध में

धारा 39. इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज पर शुल्क आरोपित करने की शक्ति -

- (1) केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति से, ऐसे ःथानों में और ऐसी दरों पर, जैसी वह अधिसूचना द्वारा घोषित करें, उस सब इमारती लकड़ी या वन-उपज पर शुल्क उद्घात कर सकेगी -
 - (क) जो उन राज्यों के क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विव: तार है, उत्पन्न होते हैं, और जिसके विषय में सरकार को कोई अधिकार प्राप्त है, या
 - (ख) जो उन नियमों के क्षेत्रों में, जिन पर इस अधिनियम का विव: तार है, बाहर के किसी ःथान से लाया जाता है।
- (2) ऐसे हर मामले में, जिसमें ऐसे शुल्क की बाबत यह निन्दर् ट किया गया है कि वह मूल यानुसार उद्घात की जावे, केन्द्रीय सरकार वैसी ही अधिसूचना द्वारा, वह मूल य नियत कर सकेगी जिस पर ऐसा शुल्क निधारित होगा।
- (3) इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज पर जो शुल्क या उस समय, जब वह अधिनियम किसी राज्य क्षेत्र में वृत्त होता है, राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन उसमें उद्घात होते हैं, उन सबके बाबत यह समझा जावेगा कि वे इस अधिनियम में उपबन्धों के अधीन उद्घात होते हैं, और सम्पत्क रूप से उद्घात रहे हैं।
- (4) जब तक कि संसद (Parliament) द्वारा कृत: उपबन्ध नहीं किया जाता, राज्य सरकार इस धारा में किसी बात के होते हुए किसी भी शुल्क को लगातार उद्घात कर सकेगी, जिसे वह संविधान के प्रारम्भ के पूर्व इस धारा के उस समय वृत्त रूप में विविध पूर्णत: उद्घात करती थी। परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी शुल्क का उद्घात प्राधिकृत नहीं करती जो राज्य की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज और राज्य के बाहर के ःथान की समरूप इमारती लकड़ी या अन्य उपज के पूर्व किथत के पक्ष में विभेद करती है, या जो राज्य के बाहर किसी ःथान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के मामले में, किसी एक ःथान की इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के बीच विभेद करता है।

टिप्पणी - इस धारा के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार इमारती लकड़ी या वनोपज पर शुल्क लगा सकती है, चाहे वह इस अधिनियम के क्षेत्र में उत्पन्न की गई हो। (देखें AIR 1965, Madhya Pradesh 215)।

धारा 40. सीमा सम्बन्धी उपबन्ध, बयधन या ःवामित्व के सम्बन्ध में लागू नहीं होगा - इस अध्याय की किसी बात की बाबत यह समझा जावेगा कि वह उस राशि को, यदि कोई हो तो जो किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज पर बयधन या ःवामित्व के रूप में प्रभावर है, सीमित करती, भले ही ऐसी इमारती लकड़ी या उपज के अभिवहन के दौरान उस पर रीति से उद्घात होता है, जिसमें से शुल्क उद्घात होता है।

अध्याय - 7

अभिवहन के दौरान इमारती लकड़ी एवं वन उपज के निर्यात के संबंध में

धारा 41. वन उपज के अभिवहन (Transit) को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति :-

- (1) इमारती लकड़ी को बहाकर परिवहन करने के लिये विषय में, सब निदयाँ और उनके स्तरों का नियन्त्रण और थल या जल द्वारा अभिवहन में कोई इमारती लकड़ी और अन्य वन-उपज के अभिवहन करने के लिये राज्य सरकार को अधिकार है तथा वह इमारती लकड़ी या वनोपज के परिवहन के विनियमित (Regulate) करने संबंधी नियम बना सकेगी।
- (2) विशेषत: और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम :-
 - (क) उन मागों को विहित कर सके जिनके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज राज्य में आयात या राज्य से निर्यात या राज्य के अन्दर परिवहन की जा सकेगी।
 - (ख) ऐसे अधिकारी के पास बिना, जो उसे देने लिये सम्पत्क रूप से प्राधिकृत है, या ऐसे पास को प्रतिषेध कर सकेंगे।
 - (ग) ऐसे पासों को दिये जाने, पेश करने, या वापस करने के लिये तथा उसके लिये फीस के दिये जाने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।
 - (घ) अभिवहन में, इमारती लकड़ी या अन्य वनोपज को, जिसके विषय में यह विव: वास करने का कारण है कि उसकी कीमत के कारण या उसकी देय किसी शुल्क, फीस, या ःवामित्व या प्रभार के कारण कोई शुल्क सरकार को देय है, या जिस पर इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये चिह्न लगाना (Affix a mark) वांछनीय है, उसके बारे में रिपोर्ट देने, रोकने, उसका परीक्षण करने, (Examination) चिह्नित करने के लिये रोककर उपलब्ध कर सकने के नियम बना सकेंगे।
 - (ङ) उन डिपो (Depot) की ःथापना और विनियम के लिये जिनसे किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज व्यक्तियों द्वारा, जिनके भार-साधक में वह है, परीक्षा के लिये, या ऐसे धन के दिये जाने के लिये, या उस पर

चिह्नलगाने के लिये, ले जाई जावेगी तथा उन शतोर का, जिनके अधीन ऐसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे डिपो को लाई जावेगी, उनमें संमहीत की जावेगी, और उनसे हटाई जावेगी, उपलब्ध कर सकेंगे।

(च) इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के अभिवहन के लिये व्युक्त किसी नदी की धारा या तट को बन्द करना या बाधित करना या ऐसी किसी नदी में घास, शाखायें या पित्तियाँ फेंकना या ऐसा कोई कार्य करना जिससे ऐसी नदी का मार्ग बन्द या बाधित हो जावे, प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(छ) ऐसी नदी की धारा या किनारों की किसी बाधा के निवारण या हटाने के लिये उस व्यक्ति से, जिनके कार्यों की उपेक्षा के कारण यह आवें तक हुआ है, ऐसे निवारण या हटाने का खर्च वसूल करने के लिये उपबन्ध कर सकेंगे।

(ज) विनिर्दष्टः: थानीय सीमाओं के अन्दर, लकड़ी की चिराई मशीन के लिये गढ़वा बनाना, इमारती लकड़ी को संपरिवर्त (Convert) करना, काटना, जलाना, छिपाना (Concealing) या विनयर (Vineer) बनाना या लकड़ी पर लगे चिह्नों को परिवर्तित करना (Altering) या नये चिह्न लगाना (Effacing) या इमारती लकड़ी को चिह्नित करने वाले हथौड़े (Making Hammer) का अपने अधिपत्य में रखना या साथ ले जाना, पूर्णरूप से या शतोर के अधीन प्रतिषिद्ध कर सकेंगे।

(झ) इमारती लकड़ी के लिए संबंधी चिह्नों के योग और ऐसे चिह्नों के रिजःशीकरण को विनियमित कर सकेंगे। उस समय को विहित कर सकेंगे, जिनके लिये रिजःशीकरण भावी रहेगा, ऐसे चिह्नों की उन संख्या को सीमित कर सकेंगे, जो किसी व्यक्ति द्वारा रिजःशीकृत कराये जा सकेंगे तथा ऐसे रिजःशीकरण के लिये फीसों के उदाहरण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे।

(2) राज्य सरकार निर्देश दे सकेगी कि इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज के किसी विनिर्दष्ट वर्ग को या किसी विनिर्दष्टः: थानीय क्षेत्र को लागू नहीं होंगे।

धारा 41-क. कटम वृन्टियर के पार इमारती लकड़ी के परिवहन विषयक केन्द्रीय सरकार की शक्तियाँ - धारा 41 में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार उस मार्ग को विहित करने के लिए नियम बना सकेगी, जिसके द्वारा ही इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज ऐसे किन्हीं कटम वृन्टियर के पार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पिरनिश्चित है, आयात, निर्यात या राज्यक्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है या उनसे आयात-निर्यात या अन्तर्गत पिरवहन जा सकेगी और धारा 41 के अधीन बनाए गए कोई नियम, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहकर ही भावी होंगे।

अ॥ याय 8

बहती शई या अटकशई लकड़ी के संग्रहण के सम्बन्ध

ब३ ध म३

धारा 45 कितपय प्रकार कऽ इमारती लकड़ी, जब तक तक उसके बारे म३ तक साबित नहल होता, सरकार कऽ

स३ पि३समझी जावेगी और तदनुसार संग्रहित कऽ जावेगी -

(1) बहती शई (Adrift), तकनारे लगी (Beached), अटकशई (Stranded), या डूबी शई (Sunk) समस्त लकड़ी -

समस्त काष्ठ (Wood) या इमारती लकड़ी, जिस पर ऐसे चिह्न हल लगे हल तो धारा 41 के अधीन बनाये

नियमों के अनुसार रिजऽशीकृत नहल है, या जिनके चिह्न हल अलि या अ३ य कारण से मिट गये,

बदल गये या बिगड गये हल, और

ऐसे चिह्न म३ जो रा३ य सरकार विनिर्दष्ट करल, समस्त चिह्नित (unmarked) काष्ठ और इमारती लकड़ी।

जब तक कोई यि इस अ॥ याय म३ उपबिधत ष३ से अपना अधिकार और हमिस नहल कर दे,

शासकऽय संपि३ समझी जावेगी।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी, ठकसी वन अधिकारी या अ३ य ३ यि□ के ँलऱऱऱा, जो उसे धारा 51 के अधीन बनाये ठकसी िनयम के अ३ तगऱऱत संलऱहण करने का हकदार है, संलऱहित कऱ जावेगी और ऐसे िडप□ मऱ लाई जा सकऱगी िजसे वह अधिकारी बहती ऱई लकड़ी कऱऱऱाऱि के िलये अधिसूचित करऱ।

(3) रा३ य सरकार, राजपू मऱ अधिसूचना के ँलऱऱऱा, ठकसी लकड़ी के ठकसी वगऱऱ को इस धारा के उपबंढ□ से छूट दे सकेगी।

धारा 46. बहती ऱई इमारती लकड़ी के दावेदार□ को सूचना - धारा 45 के अ३ तगऱऱत संलऱहित इमारती लकड़ी कऱसमय-समय पर वन अधिकारी ँलऱऱऱा सूचना जारी कऱ जावेगी। सूचना मऱ इमारती लकड़ी का िववरण अ३ तऱवऱऱ ट होगा तथा इमारती लकड़ी पर दावा करने वाले ३ यि□ से अपेँऱा कऱ जावेगी ठक वह ऐसी सूचना कऱ तारीख से दो माह से अ३ यून अविध मऱ अपने दावे का िलिखत कथन ऱऱं तुत करऱ।

धारा 47. ऐसी इमारती लकड़ी पर ठकये गये दावे के बारे मऱऱऱऱा

(1) पूव□ त अनुसार, दावे का कथन ऱऱं तुत होने पर वन अधिकारी ऐसी जाँचकरने के पँ चात् िजसे वह ठीक समझता है, या तो दावे को र□ करने के कारण दशाऱऱते ऱए, दावे को र□ करेगा या दावेदार को इमारती लकड़ी का ऱदान कर सकेगा।

(2) यऱद एक से अधिक ३ यि□य□ऱऱऱा ऐसी इमारती लकड़ी पर दावा ठकया जाता है, वह वन अधिकारी ऐसे ३ यि□य□ को िसिवल ३ यायाल को िनदऱऱिशित करेगा, ३ यायालय से उसके िनराकरण(Disposal) सऱ ब३ धी आदेश होने तक अपने कऱ जे मऱ रख सकेगा।

(3) िजस ठकसी ३ यि□ का दावा इस धारा के अधीन खाऱरज ठकया जा चुका है, वह अपने ँलऱऱऱा दावाकृत इमारती लकड़ी का कऱ जा लेने के िलये खाऱरजी के तीन माह के अ३ दर, वाद संिँथत कर सकेगा, ठक३ तु कोई ३ यि□ऐसी खऱरजी, या ठकसी इमारती लकड़ी को रोककर रखे जाने, या हटाने, या इस धार के अधीन अ३ य ३ यि□को पऱरदान के कारण कोई हजाऱऱाना (Compensation) या कऱमत (Cost) सरकार से या वन-अधिकारी से वसूल नहऱ कर सकेगा।

(4) जब तक ठक ऐसी कोई इमारती लकड़ी पऱरदऱ त नहऱ कऱ गई है या उसके सऱ ब३ ध मऱ बाद संिँथत नहऱठकया गया है, तब तक ऐसी लकड़ी ठकसी िसिवल ३ यायालय, ऱऱिमिनल या राजँ व ३ यायालय के आदेश (Process) के अधीन नहऱ होगी।

धारा 48. िजसका दावा नहऱठकया, उस लकड़ी का ३ ययन (Disposal) - यऱद यथा-पूव□ त ऐसे कोई दावा ऱऱं तुत नहऱठकया जाता, या दावेदार धारा 46 के अधीन िनकाली सूचना ँलऱऱऱा िनयम कालाविध के अ३ दर दावा नहऱ करता है या उसके ँलऱऱऱा इस ऱकार दावा ठकये जाने पर उसका दावा खाऱरज ठकया गया हो या ऐसी इमारती लकड़ी का कऱ जा

लेने के लिये धारा 47 द्वारा नियम अपील कालाविध के अ३ दर बाद संशोधित करने का लोप करता है तो ऐसी इमारती लकड़ी का ठं वांमि० व सरकार मं३ निहित होगा या धारा 47 के अधीन अ३ य ३ यि३ को पहरद० त होने क३ िंथित मं३ ऐसे ३ यि३ मं३ ऐसी लकड़ी का ठं वांमि० व सब इ३ जाम३ (Encumbrances) से मु३ त होकर निहित होगा जि३ ह३ उसने सृ३ ट (Create) नह३कया है।

धारा 49. ऐसी लकड़ी को श३ नुकसान के लिये सरकार और उसके अधिकारी उ० तरदायी नह३ ह३गे - ढकसी हा३न या नुकसान के लिये, जो धारा 45 के अधीन सं३हीत ढकसी लकड़ी को श३ है, सरकार उ० तरदायी नह३ होगी और जब तक ढक कोई वन अधिकारी, ऐसी हा३न या नुकसान उपे३ा, िव३ेष या कपट से नह३ करता, तक तक वह ऐसी हा३न या नुकसान के लिये उ० तदायी नह३ होगा।

धारा 50. इमारती लकड़ी के पहरदान के पूव३ दावेदार द्वारा दी जाने वाली अदायगी - जब तक कोई ३ यि३, ऐसी रा३श जो, धारा 51 के अधीन बने ढकसी नियम के अधीन देय है, वन अधिकारी या अ३ य ३ यि३ को, जो उसे ३ा३ त करने का हकदार है, चुका नह३ देता, तब तक वह उपरो३ त इमारती लकड़ी का हकदार नह३ है।

ढट३ पणी

धारा 50. वन अधिका३रय३ द्वारा वन अपराध मं३ ज३ त वाहन को दां३डक ३करण के ल३बित रहते उ३ लंघन करने वाले वाहन को अंत३रम ३प से सुपुद३गी मं३ देने का आदेश पा३रत करने मं३ संब३धित मिज३ट सं३म है। (ढदलीप मीया िव. म.३. रा३ य 2012 (1) म.३.लॉ.ज. 137 (म.३.)।

धारा 51. नियम बनाने व शि३याँ िविहत करने क३ शि३

(1) रा३ य सरकार िन३ निलिखत बात३ का िविनयम करने के लिये नियम बना सकेगी : अथा३तः

(क) धारा 45 मं३ व३ण३त सब इमारती लकड़ी का उ३रण (Salving), सं३हण (Collection) या ३ ययन (Disposal)।

(ख) इमारती लकड़ी के उ३रण और सं३हण के िलए ३यु३ त नाव३ का ३योग व रिज३ं३ीकरण।

(ग) इमारती लकड़ी के उ३रण और सं३हण, ठं थाना३ तरण, भ३डारन काय३न के िलए रा३श का भुगतान।

(घ) ऐसी इमारती लकड़ी को िचि३हत करने के िलए ३योग मं३ आने वाले हथौड़े और अ३ य उपकरण३ का ३योग एवं रिज३ं३ीकरण।

(2) रा३ यशासन इस धारा के अधीन बने ढक३ ह३ नियम३ के उ३ लंघन के ३प मं३ शा३ंतय३ के ३प मं३ ऐसी अविध का कारावास जो 11 वष३ तक का हो सकेगा और अथ३ द३ड जो 2प३ं३ हजार ३पये तक या दोन३ िविहत कर सकेगी।

म.०. विधान ८. 1 वर्ष 2010-11 द्वारा संशोधित।

2. म.०. विधान ८. 25 वर्ष 1983-84 द्वारा संशोधित। म.०. राजपत्र (असाधारण) 8 दनांक 28.05.83 के पृष्ठ ८. 1635-45 पर प्रकाशित।

म.०. अधि. ८. 2998/दस/3/83 दनांक 24.10.83 के द्वारा विधान ८ मांक 25 वर्ष 83 दनांक 1.11.83 से प्रभावशील आ।

अनुयाय 9

शितियाँ और

प्रकया

धारा 52. अधहरणीय (Confiscation) स- पिड़ का अभिग्रहण और उसके लिये प्रकया - जब यह विव वास करने का कारण हो क कसी आरित वन और संरित वन या वन उपज के स- बध मथ कोई अपराध कया गया है तो वन उपज और सम त औजार नाव, यान, र सी, जंजीर या अ य कसी व तु को, िजनका प्रयोग ऐसे अपराध को करने मथ कया गया है, कसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहित कया जा सकेगा।

हट पणी

धारा 52. वन अधिनियम स.प. धारा 30 अधिव ता अधिनियम 1961- स- पिड़ के समपहरण क कायवाहियाँ -
(क) वन अपराध मथ अधिकृत अधिकारी के सम समपहरण कायवाहिय (Confiscation Proceedings) मथ अधिव ता क उपरिथित अनुये नह है।

(ख) समपहरण कायवाही मथ अधिकृत अधिकारी द्वारा सा य अभिलिखत करने हेतु कोई उपबंध विमान नह है। (कुलदीप शमा वि. म.०. रा य वग, 2012 (2) म.०. लॉ.ज. 453 (म.०.)).

यान क ज ती कायवाही आर भ करने के पूर्व एकमान पूर्ववत शत यह है क उसके द्वारा वन-अपराध घटत कया जाना आव यक है। (म.०. रा य वि. से, स एजे सीस 2005 (1) विविध भां वर 163 (सु.को.) = A.I.R. 2004 S.C. 2088 = 2004 ८. लॉ. ज. 1832 = 2004 सु.को. के (८.) 1313)।

(2) इस धारा के अधीन कसी स- पिड़ को ज त (Seize) करने वाला अधिकारी, ऐसी स- पिड़ पर यह उपदशत करने वाला चि ह लगावेगा क इसका इस प्रकार अभिग्रहण (Seizure) कया गया है और अभिग्रहीत स- पिड़ को यथाशी या तो सहायक वन-संरक के पद से अन न ंणी के कसी अधिकारी के, िजसे रा य सरकार ने अधिसूचित द्वारा इस िनिम त अधिकृत कया हो (जो इसमथ इसके प चात् "अधिकृत अधिकारी" (Authorised

Officer) के नाम से निर्दिष्ट है) के समीप पेश करेगा। जहाँ पहरणाम (Quantity), ऋपुंज (Bulk) या अ३ य वां तिवक (Genuine) कठुठनाई को ॥ यान मं रखते शए यह सा॥ य न हो ढक अभि॒रहीत स॒ पि॒ को ँ॒ाधिकृत अधिकारी के समीप पेश ढकया जावे, वहाँ वह अभि॒रहण (Seizure) के बाबत ढरपोट॒ाधिकृत अधिकारी को करेगा, या जहाँ अपराधी के वि॒वा॒ दा॒ि॒डक काय॒वाही (Criminal proceedings) तुर३ त आर॒ भ करने का मत होतो वह ऐसे अभि॒रहण क॒रपोट॒, उस अपराध का िजसके कारण अभि॒रहण ढकया गया है, विचारण करने क॒ अधिका॒रता रखने वाले मिजं॒ट को करेगा :

पर३ तु जब वह वन-उपज, िजसके बारे मं ऐसे अपराध ढकये जाने का वि॒ वास है, सरकार क॒ स॒ पि॒ है और अपराधी अ॒ात है तो य॒द अधिकारी, प॒रि॒थित के बारे मं॒रपोट॒ अपने पदीय व॒रु॒ ठ (Official Superior) को यथाश॒ य शी॒ दे देता है तो पया॒ात होगा।

(3) उपधारा (5) के अ॒ यधीन रहते शए जहाँ ँ॒ाधिकृत अधिकारी, यथा॒ि॒थित अभि॒रहीत स॒ पि॒ अपने समीप पेश ढकये जाने पर या अभि॒रहण के बारे मं॒रपोट॒ा॒ात होने पर यह समाधान हो जाता है ढक उसके बारे मं कोई वन अपराध ढकया गया है वह लिखत आदेश ॒ा॒ा और अभिलिखत ढकये जाने वाले कारण॒, से उस वन उपज को जो इस ँ॒कार अभि॒रहीत क॒ गई है, समं॒ त औजार॒, यान॒, नाव॒, रं॒ स॒, जंजीर॒ ढकसी अ३ य वं॒ तु सहित िजनका ँ॒योग ऐसे अपराध को करने के िलए ढकया गया है अधि॒त (Confiscate) कर सकेगा। अधि॒रण के आदेश क॒ एक ँ॒ित अवल॒ ब उस वन वृ॒ त सर॒क को भेजी जायेगी िजसमं॒इमारती लकड़ी या वनोपज अभि॒रहीत क॒ गई है।

(4) धारा (3) के अधीन ढकसी स॒ पि॒ को अधि॒रण करने वाला आदेश तब तक नह॒ढकया जायेगा जब तक ढक ँ॒ाधिकृत अधिकारी -

(क) स॒ पि॒ के अधि॒रण के िलये काय॒वाही ढकये जाने के बारे मं सूचना, उस अपराध का, िजसके कारण अभि॒रहण ढकया गया है, विचारण करने क॒ अधिका॒रता रखने वाले मिजं॒ट को वि॒हित ँ॒ाप मं नह॒देता।

3.

म.॒. अधि. ॒. 7 वष॒ा॒॒ा संशो॒धित 27.3.2010 से ँ॒भावशील।

(ख) उस ३ यि॒ को िजसक॒ स॒ पि॒ अभि॒रहीत क॒ गई है, या ढकसी ऐसे अ३ य ३ यि॒ को िजसके बारे मं॒ाधिकारी अधिकारी को यह ँ॒तीत होता हो ढक उसका ऐसी स॒ पि॒ मं कोई िहित है, लिखत सूचना नह॒ दे देता है।

(ग) ख॒ ड (ख) मं निर्दिष्ट है ३ यि॒ यि॒ को अधि॒रण के वि॒वा॒ अ॒ यावेदन, ऐसे समय के भीतर, जैसा ढक सूचना मं निर्दिष्ट है ढकया जावे, करने का अवसर नह॒ दे देता; और

(घ) अधिहरण करने वाले अधिकारी कऽ एवं तथा उस ३ यि□ या उन ३ यि□य□ कऽ िजसे या िज३ हथ खल्लु ड

(ख) के अधीन सूचना दी गई है, सुनवाई उस ंयोजन के िलये िनयत कऽ गई तारीख को नहल कर लेता।

(5) धारा (3) के अधीन ढक३ हल औजार□, यान□, नाव□, रं स□, जंजीर□, या अ३ य वं तु को अधिउत करने का आदेश नहलकया जावेगा, यढद उपधारा (4) के खल्लु ड मथ िविनंदभ्ण ट कोई ३ यि□, "ंाधिकृत अधिकारी" के समाधानंद ढप मथ यह साबित कर देता है ढक ढक३ हल ऐसे औजार□, यान□, नाव□, रं स□, जंजीर□ या अ३ य वं तु का ंयोग उसकऽ जानकारी या मौनानुकूलता के िबना या यथा िंथित उसके नौकर या अभिकताभ्ण (Agent) कऽ जानकारी या मौनानुकूलता ढक िबना ढकया गया था और यह ढक वन अपराध ढकये जाने के िलये पूव□□ त वं तु के ंयोग को रोकने के िलए समं त स यक् (Reasonable) और आवं यक पूवाभ्णवधािनयाँ (Precautions) बरती गई थी।

ढट७ पणी

वन अपराध मथंयु□ त वाहन को समपारण का आदेश पाहरत करने के पूवभ्ण यह ११ यान मथ रखा जाना चािहए ढक □ या यह ंमाणित होती है ढक उस अपराध मथंयु□ त वाहन को उसके ँ वामी कऽ जानकारी मथंयु□ त ढकया गया था। ऐसे िन्र कषभ्ण के अभाव मथ यान के समपारण का ओदश िवखंडित ढकया गया। (ंकाश राय िव. म.ं. रा३ य 2006(4) मिनसा 145 म.ं. = एवं देवकऽ नंदन शमाभ्ण िव. ंाधिकृत अधिकारी एवं अपर वन मंडलाधिकारी वगऱ. 2011 (3) म.ं. वी. नो. 132 (म.ं.))।

िवचारण ३ यायालय ःलःारा सभी आरोपिय□ को वन-अपराध□ मथ दोषमु□ त ढकया गया था तब उस अपराध मथंयु□ त वाहन के समपारण का आदेश िंथर रखे जाने यो□ य नहल था अतः उसे िवखंडित ढकया गया। (केशव ंसाद गु७ ता िव. म.ं.)

रा३ य वगै. 2013 (2) म.ं. लॉ.ज. 149 (म.ं.)।

वन-अपराध मथंयु□ त मशीन एवं ड८ पर□ को ठेकेदार ने ढकराये पर लेकर उसको जानकारी ढदए िबना उसका किथत वन-अपराध मथंयुयोग ढकया था। ँंकंतु अपीलाथ७ को बार-बार अवसर ढदए जाने के बावजूद उसने मूल पहरवहन करार ३ यायालय के समंंंं तुत नहलकया था अतः उसके अभवाक को िनरं त करने के ओदश कऽ पुिं कऽ गई। (रामे३ंपाल ःसंह िव. म.ं.)

रा३ य वगै. 2013 (2) म.ं. लॉ.ज. 226 (खंडपीठ म.ं.)।

इ३ दौर से कार मालिक ने उसके मामा को कार से भोपाल पशंचाने हेतु कार चालक को भेजा था। भोपाल से इ३ दौर वापिसी याा मथ कार चालक ने कुछ ३ यि□य□ को याा करने दी, जो अवैध ढप से चंदन कऽ लकड़ी ले जा रहे थे।

इस तः य का कार मािलक को िान नहल था। चूँक ज त कार का उपयोग कार पहरवहन ढकया गया था अतः कार के समपारण आदेश को िवखि डत ढकया गया। (देवकऱ नंदन िव. ःािधकृत अधिकारी 2012 (2) म.ः.लॉ.ज. 45 म.ः.)।

1(6) अभगृहीत स पिड, ःािधकृत अधिकारी के आदेश कऱ अपील ःािधकारी ःािधकारा पुि होने तक या उसके ःािधकारा वःेरणा से कारकावाई ःार भ करने कऱ कालाविध कऱ समाि तक, इसमऱ से जो भी पूवकातर हो, धारा 52-क के अधीन यथािवहीत अभरिा मऱ बनी रहेगी।

1(7) जहाँ मामले कऱ अधिकाहरता रखने वाला ःािधकृत अधिकारी, अभलहण मऱ या अऱ वेषण मऱ वयं अऱ तवकािलत है, वहाँ अगला उल्ल च ःािधकारी इस धारा के अधीन कायकावाहिय के संचालन के िलए उसी ःेणी के ढकसी अऱ य अधिकारी को मामला अऱ तहरत कर सकेगा।"

2(नवीन धारा 52 क, ख, ग, का अऱ तः थापन) - मूल अनिअधिनयम मऱ धारा 52 के पऱ चात् िन निलिखत धाराये अऱ तः थापित कऱ जावऱ अथाकात् :

1. म.ः. अधि. ल. 7 वषका 2010 ःािधकारा जोड़ा गया।

2. म.ः. अधि. ल. 25 वषका 1983 ःािधकारा धारा 52, क, ख, ग का अऱ तः थापन।

धारा 52-क. ःािधकृत अधिकारी के आदेश के िवऱ अपील - ःािधकृत अधिकारी के आदेश से ियथत कोई ियि, आदेश ढकये जाने कऱ तारीख से तीस ढदन के भीतर या यढद ऐसे आदेश स बऱ धी तः य (Fact) कऱ संसूचना उसे नहल दी गई हो, ऐसे आदेश कऱ जानकारी होने कऱ तारीख से तीस ढदन के भीतर उस वन वृ त के वन संरिा को (िजसमऱ वन उपज अभलहीत कऱ गई हो) (िजसे इसमऱ इसके पऱ चात् "अपीलीय अधिकारी" के नाम से िनंदका ट है) को िलिखत मऱ अपील, ऐसे फामका मऱ तथा ऐसी फऱस के साथ जो िविहत कऱ गई है, कर सकेगा और उसके साथ अधहरण (Confiscation) आदेश कऱ माणित ःाित संल न कऱ जावेगी।

पु टीकरण

(1) इस उपधारा मऱ तीस ढदन कऱ कालाविध कऱ गणना करने मऱ वह समय अपवकाजकात (Excluded) कर ढदया जायेगा जो आदेश कऱ ःािधकारा त करने के िलये अपेिात रहा हो।

(2) उपरो त धारा 1 मऱ वकाकात "अपीलीय अधिकारी" जब कोई अपील ःािधकारा तुत न हो, तब ःािधकृत अधिकारी के आदेश के आदेश ःािधकारा त ढकये जाने कऱ तारीख से 30 ढदन के अऱ दर 'ठ वःेरणा' (Suo-moto) से कायकावाही कर सकेगा और उसकऱ सूचना, अभलहण करने वाले अधिकारी को, तथा ऐसे

ठकसी अ३ य ३ यि□ को, िजसका ठक अपीलीय अधिकारी कऽ राय मऽ, अभिहरण के आदेश से
 ०२भाविता होना संभा३ य है, दे सकेगा या अपील के ीापन ०२ात होने कऽ दशा मऽ वह अपील कऽ
 सूचना उन ३ यि□य□ को देगा और मामले के अभिलेख मंगा सकेगा:

पर३ तु अपील कऽ औपचाहरक सूचना, यथापूर्व□ त अपीलाथट, अभिहरण करने वाले अधिकारी, और
 ०२ितकूलतः ०२भाविता होने वाले ठक३ हल३ यि□य□ मऽ से उनको ढदया जाना आवं यक नहल होगा जो
 सूचना का अध० यजन (Waive) कर दऽ या िज३ हऽ अपील सुनवाई कऽ तारीख 'अपीलीय अधिकारी'
 ँनःारा अ३ य रीति से सूचित कर दी जावे।

- (3) अपील ०२ाधिकारी, अपील कऽ वं ०२ेरणा से कऽ जाने वाली काय३वाही के बारे मऽ ०२ाधिकृत
 अधिकारी को सूचना िलिखत मऽ देगा।
- (4) अपील ०२ाधिकारी, अधिहरण, कऽ गई िवषय-वं तु कऽ अभिरंा (Custody), पहरंण
 (Practitioner) या ३ ययन (Disposal) (यडद आवं यक हो) के िलए अ३ तहरम आदेश कर सकेगा जैसे
 ठक उस मामले मऽ पहरंथित मऽ३ याय संगत और उचित होते ह□।
- (5) 'अपील अधिकारी' मामले कऽ ०२कृति या अ३ तग३त जहलता□ को ॥ यान मऽ रखते शए अपील के
 पंकार□ को, उनका ०२ितिनिध० व उनके अपने-अपने िविध ३ यवसािय□ (Legal
 Practitioner) ँनःारा ढकये जाने अनुीा दे सकेगा।
- (6) अपील कऽ या 'वं ०२ेरणा' से कऽ जाने वाली काय३वाही कऽ सुनवाई के िलये िनयत कऽ गई तारीख को
 या ऐसी तारीख को जो सुनवाई ँथिगत कऽ जाने के पं चात् िनि त कऽ गई हो, अपील अधिकारी,
 अभिलेख का पहरशीलन करेगा, और यडद अपील के पंकार ँ वयं उपिंथत ह□ तो उनकऽ सुनवाई करेगा या
 स० यक् ३प से ०२ाधिकृत अधिकारी के आदेश कऽ पुि० करने, उसे उलटने (Reversal) या उसे उपा३ तहरत
 (Modify) करने का आदेश पाहरत करने कऽ काय३वाही करेगा :

पर३ तु यडद कोई अ३ तहरम आदेश पाहरत करने के पूर्व३, अलील ०२ाधिकारी, अपील या वं ०२ेरणा
 से कऽ गई काय३वाही के उचित िनण३य के िलये आवं यक समझता है तो अितहर□ त जाँच या तो ँ
 वयं करेगा या ०२ाधिकृत अधिकारी से करावेगा, और ठकसी ऐसे तः य का, जो िवचाराथ३ हो, ०२ा□
 यान या खल३ डन करने के िलये, पंकार□, को शपथ प० फाइल करने को अनुीात कर सकेगा और
 तः य□ का ०२माण शपथ (Affidavits) ँनःारा ढदये जाने कऽ अनुीा दे सकेगा।

(7) अपीलीय अधिकारी पाहण्यात्मक ं वस्व (Consequential nature) के ऐसे ओदश पाहृत कर सकेगा जैसे वह आवं यक समझे।

(8) अंतिम आदेश, या पाठ्यक्रमिक ंवर्ष आदेश केंद्रित अनुपालन के अथवा अपील अधिकारी के आदेश के अनुकूल अथवा समुचित आदेश पाठ्यक्रम करने के लिए "अधिकृत अधिकारी" को भेजी जावेगी।

1.

म.उ. अध. ८. 7 वर्ष 2010-11 द्वारा जोड़ा गया।

धारा 52. ख. अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन 3 यायालय के समीच पुनरीक्षण 52-ख-

(1) अपील का कोई भी पं०कार, जो अपील अधिकारी द्वारा पाठ्यरत ठकये गये अलतम आदेश से या पाठ्यरणात्मक वरूप आदेश से यथत हो, उस आदेश के, िजसके िवषय आर्ोप ठकया जाना र्दिसत है, तीस ठदन के भीतर, सेशन 3 यायालय को पुनरीर्ण के िलये याचिका र्दुत कर सकेगा िजसके सेशन

खण्ड के भीतर अधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

पट्टीकरण - इस उपधारा के अधीन तीस ठदन कऽकालाविध कऽ संगणना करने मऽ, वह समय अपवर्जनात ठकया जावेगा जो अपील अधिकारी के आदेश कऽरमाणिता रिति अभिऽात करने के िलये अपेिऽत रहा हो।

(2) सेशन 3 यायालय, अपील अधिकारी ~~उत्तर~~ द्वारा पाठ्यतः ढकये आदेश कऽ पुर्ण कर सकेगा, या उसे उपट सकेगा या उसे उपाऽ तऽरत कर सकेगा।

(3) पुनरीक्षण मऽ पाहरत ढकये गये आदेश कऽ ुतियाँ अपील अधिकारी तथा ुताधिकृत अधिकारी को

अनुपालन हेतु, या ऐसे अतिहरण त ओदश पाहरत करने हेतु या ऐसी अतिहरण त कायबलवाही करने हेतु भेजी जावेगी जैसी कऽ यायालय ँनदऽशित कऽ जावे।

(4) इस धारा के अधीन ठकसी पुनरीर्ण को ळहण करने, उसकऱ सुनवाई करने और उसका िविनित करने के िलये, सेशन 3 यायालय, यथाशय उ3 हत शिष का ेरयोग करेगा और ेरऱया का अनुसरण करेगा िजसका ठक ेरयोग और अनुसरण वह दऱ उड ेरऱया संिहता (Criminal Procedure Code 1973) (1974 का 2) के अधीन ठकसी पुनरीर्ण का ळहण करने, उसकऱ सुनवाई करने और उसका िविनं चय करने के समय करता है।

(5) दण्ड अधिनियम, 1973 (1974 का 2) में अंतर्गत प्रावधानों के तहत कसौती की बातें होती हैं।
भी, इस धारा के अधीन पाठ्यक्रम दिया गया सेशन 3 याचिका का आदेश अंतिम होगा और उसे कसौती
याचिका के समक्ष नगद नहीं देकर जायेगा।

(2) उपधारा (1) मं कऽ गई कोई बात धारा (61) के अधीन 3 यावृत (Saved) शिख को ०2 भांिवत नहल करेगी।

ਛੋਟੀ ਪਾਠੀ

23 / 66

661 (म.०.२.)।

हटो पणी - (1) 0ी क3 हैयालाल पु॒ जानकडलाल ँाथण िनवासी से3 धवा का ऽक ऽ. MHB 59958दनांक 24.2.85 को ज० त थआ। इस ज० ती कड सूचना धारा 52(4) क अ3 तग॒णात से3 धवा िंथत मिजं॒ट को दी गई। 0ी क3 हैयालाल ने धारा 451 द.०.सं. के तहत ऽक को सुपुद॒णा नामे पर देने हेतु 3 यायालय से3 धवा म॒ आवेदन ऽदया जो ०२ करण ऽ. 63/85 दज॒णा थआ। यह आवेदन 3 यायाधीश महोदय के आदेश ऽदनांक 2.5.85 ऽ॒ऱा ख॒रज थआ।

इस आदेश के िव॒ उ३ ह॒ ने उ॒ च 3 यायालय, बे३ च इ३ दौर म॒ हरवीजन िपटीशन दज॒णा ऽकया जो ०२ करण ऽ. Cr. R/105/85 दज॒णा थआ। इस हरवीजन िपटीशन म॒ धारा 451 C-PC के अ३ तग॒णात ऽक को सुपु॒णादामे पर देने के अित॒र त यह भी िनवेदन ऽकया ऽक ऽक म॒ सागौन इमारती लकड़ी थी जो म.०.२. वनोपज ३ यापार (िविनमयन) अधिनयम, 1669 से िनयि॒त है तथा वह इस िनयम म॒ घोषित specified forest produce पर उसकड धारा 22 के अनुसार भारतीय वन अधिनयम, 1927 या अ३ य िनयम लागू नह॒ होते।

उ॒ च 3 यायालय ने अने फैसले ऽद. 11.4.86 म॒ िनण॒य ऽदया ऽक य॒िप सागौन इमारती लकड़ी िविन॒श॒णा ट वनोपज है, ले॒कन केवल उस स॒ ब३ ध म॒ ही अ३ य िनयम नह॒ लगते िजनका ०२ावधान म.०.२. वनोपज ३ यापार (िविनमयन) अधिनयम 1969 म॒ है तथा धारा 52(ग) इस पर लागू होता और हरवीजन िपटीशन खा॒रज थआ।

वन अपराध ०२करण॒ म॒ राजसात ऽकये गये वाहन॒ के शासकडय उपयोग/िव॒य के िलये ०२ॽया :

म॒ य॒ देश शासन, वन िवभाग, भोपाल के प॒. 239/4573/10/2/91 ऽदनांक 10 जनवरी 1992 के ऽ॒ऱा वन अधिनयम॒ के अ३ तग॒णात राजसात थए वाहन॒ के शासकडय उपयोग म॒ लेने, अथवा िव॒य करने हेतु िन॒ न ०२ॽया िनधा॒रत कड है, तथा :

भ. व. अ. 1927, म. ०.२. वनोपज (३ यापार-िविनमयन) अधिनयम 1969, म. ०.२. ते३ दू प० ता (३ यापार िविनमयन) अधिनयम 1964 एवं म.०.२. वनोपज अभिवहन (गमन) िनयम 1961 के अ३ तग॒णात अवैध वनोपज के प॒रवहन म॒ िल० त वाहन राजसात करने के अधिकार वन अधिका॒रय को ऽदये गये ह., इन ०२ावधान॒ के अ३ तग॒णात जो भी वाहन राजसात ऽकये जाते ह. उनके शासकडय उपयोग अथवा िनवत॒ण के स॒ ब३ ध म॒ रा३ य शासन ऽ॒ऱा िन॒ नानुसार ०२ॽया िनधा॒रत कड जाती है :

राजसात शुदा वाहन जैसे कार, ऽक आॽद, यॽद िवभागीय काय॒णा के उपयु॒ त ह॒ तो स॒ बि३धत वन म॒ डला॒धिकारी वाहन के समं॒ त िववरण उपल॒ ध कराते थए उ॒ त वाहन के शासकडय उपयोग म॒ लाने के िलए, शासन से अनुमित हेतु, ०२ं ताव मु.व.सं. (संरं॒ण) मु.व.सं. (उ० पादन) के मा॒ यम से ०२ं तुत कर॒गे। िजन वाहन॒ को शासकडय उपयोग म॒ लाया जाता है उसके स॒ ब३ ध म॒ वाहन का िनमा॒ण वष॒णा, उ॒ त वाहन के ऽ॒ऱा आज तक

तय कऽ दूरी, वाहन कऽ वतऱ्णमान िंथित आऽद के स॒ ब३ ध मऽ मोटर वाहन िनरी॒क (Motor Vehicle Inspector) या अ३ य ऽकसी ॒ािधकृत अधिकारी का ॒माण प्ु॒करण के साथ शासन को ॒तुत ऽकया जावेगा।

(2) यऽद राजसात श्रुआ वाहन शासकऽय उपयोग हेतु अनुपयु॒ त पाया जाता है तो उसका िनवतऱ्णन; िन॒ नानुसार ऽकया जावेगा :

(क) ॒०० येक वन वृ० त से राजसात शुदा वाहन॒ के अवरोध मू५ य िनधाऱ्णरत करने हेतु िन॒ नानुसार सिमित का गठन ऽकया जावेगा :

(अ) स॒ बि३धत वन वृ० त के वन संर॒क अ॒ यी॒,

(ब) िजस वर म॒ डल के अ३ तगऱ्णत वाहन

राजसात ऽकये गये है उनको छोड़कर

अ३ य ऽकसी दो वन म॒ डल॒ के वन

म॒ डलािधकारी सद॑ य

(स) वन म॒ डलािधकारी, िजसके ी॒े॒

के वाहन राजसात ऽकये गये ह. सद॑ य सिचव

(द) लोक िनमाऱ्ण िवभाग (ई. ए॒ ड एम)

या ःसंचाई िवभाग (E & M) के ॒ितिनिध सद॑ य

(कम से कम कायऱ्णपालन य३॒ी ं तर के ह॒)

उपरो॒ त सिमित, वाहन का अवरोध मू५ य िनधाऱ्णरण करने मऽ अ३ य मु॒ के साथ साथ वाहन का िनमाऱ्ण वषऱ्ण, वाहन का मूल मू५ य, वतऱ्णमान मऽ नये वाहन के मू५ य एवं वाहन कऽ वतऱ्णमान िंथित का भी ॒ यान रखेगी।

(ख) वन म॒ डलािधकारी (िजसके ी॒े॒ मऽ वाहन राजसात ऽकया गया है) ःऱा आव॑ यक ॒ सार ॒ चार उपरा३ त सील ब३ द िनिवदा के मा॒ यम से िनिवदा बुलवाई जावेगी।

(ग) अवरोध मू५ य से अधिक ऑफर ॒ा॒ त होने पर िव॒य कऽ वीकृत देने हेतु वन म॒ डलािधकारी ही स॒म ह॒गे। यऽद दो बार िनिवदा के ॒यास होने के प॑ चात् भी अवरोध मू५ य से कम रा॒िश कऽ िनिवदा ॒ा॒ त हो तो 10% तक कम रा॒िश कऽ वीकृ॒त देने हेतु वन संर॒क स॒म ह॒गे। यऽद 10% से कम मू५ य कऽ िनिवदा ॒ा॒ त हो तो िव॒य मु॒ य वन संर॒क (संर॒ण) ःऱा ं वीकृत ऽकया जावेगा।

(घ) िनिवदा पूरी करने के ॒ऽऽया, ॒क के राजसात के आदेश पाऱरत होने के ऽदनांक से, चार माह के अ३ दर पूरी कऽजावेगी।

उप सिचव
म.०. शासन

शासन कऽ अधिसूचना

- (1) म.०. शासन वन विभाग कऽ अधिसूचना ८. 2998/दस/3/83 दनांक 24-10-83 से धारा 52 संशोधित के अ३ तगभगत रा३ य शासन ने सहायक वन संरक्षक को '०.०. अधिकृत अधिकारी' नियुक्त ठकया है।
- (2) म.०. शासन वन विभाग कऽ अधिसूचना ८. 1808/दस/3/83 दनांक 11-5-84 जो राजपू. 11-5-84 के पृ. 1523 पर ०.०. काशित शई के अ३ तगभगत रा३ य शासन ने उप वन संरक्षक तथा विशेष कतभगत य अधिकारी को धारा 52 (संशोधित) के अ३ तगभगत '०.०. अधिकृत अधिकारी' नियुक्त ठकया है।
- (3) धारा 52 म३ 52A, 52B तथा 52C म॥ य.०. देश रा३ य संशोधन अधिनियम ८. 25/1983 द्वारा जोड़ी गई और 1 नवंबर 1983 से ०.०. भावी कऽ गई।

३ यायालय के निणभगत के उरण

- (1) वन अधिकारी कऽ अभिग्रहण और गिरफ्तारी कऽ धारा 52 के अ३ दर शि० उस दशा म३ कायभगवाही कऽ जाने के लिए ०.०. अधिकृत करती है जब वन अधिकारी को यह वि० वास करने का कारण हो ठक वन स० ब३ धी अपराध ठकया गया है। यह ॥ यान देने यो० य है ठक ०.०. अधिकारी न केवल वन उपज जिसके स० ब३ ध म३ अपराध ठकया गया है उसको अभिग्रहीत (Seize) करने शि० रखता है बि०क उन औजार (Tools), नाव (boats) गाडि (Carts) या पशु जानवर को भी जो अपराध करने म३ योग म३ लाये गये ह. - उ३ ह३ भी अभिग्रहीत कर सकता है। वन-अधिकारी को ऐसे ३ पि० को बिना वारं ३ गिरफ्तार करने कऽ भी शि० है जिसके वि० यह यु० यु० त स३ देह (reasonable suspicion) मौजूद है ठक उसका ऐसे वन-अपराध से स० ब३ ध है ठक जिसके सजा एक माह के कारावास तक हो सकती है यह धारा 64 म३ उपबिधित ठकया गया है - अयो॥ या० साद वि. ० टेट म. ०. - 1978 (1) म.०. वी.

नोट 491 (जि० टस जी.पी. सं३ (०ी गु० ०.०. स३ न सं३ - म. ०. हाईकोर्टभगत)

- (2) धारा 52 - ० लास 121 फारे० ट मै३ युअल हा३ यूम 1 - इमारती लकड़ी का अभिग्रहण-०.०. अधिकारी पर ०.०. माण भार है ठक वह िस० करे ठक अवैध साधन द्वारा ३ पि० इमारती लकड़ी के क३ जेदार बने ह. - य३द यह तः य िस० नह३ होता है तो इमारती लकड़ी छोड़ने के यो० य होगी - (जि० टस गोलवलकर-मिस. पिपीशन नं. 38/1958 निणटत दनांक - 18.11.1959 (म॥ य.०. देश हाईकोर्टभगत) ;

- (3) अधिहरण करने का आदेश (order of confiscation) ठीक निर० त ठकया गया - सेश३ स जज ने ३र३ हीजनल को दो आधार पर मंजूर कऽ जिसे हाईकोर्टभगत म.०. के जि० टस ३ ही.डी. ० यानी ने उचित ठहराया। सेश३ स जज का

निर्णय का पहला आधार यह था कि क3 सरवेटर फारेण्ट-अपीलीय अधिकारी ने याचिका तौर पर मिंटू का अयोग्य ठकये बिना आदेश पाइरत ठकया और इस तः य कऽ अनदेखी कऽ ठक या खदान संरिक्त वन मऽ थी? हर3 हीजनल कोर्ट सेश3 स जज इस निर्णय पर पश्चिचे ठक सवअ न बर 121/1 रकवा 8.25 है। टेयर का पं० हरण पोडे3 ट को ठदया गया था और यह सामग्री हरकाड पर उपलब्ध नहल है जिससे यह दखशक्त हो सके ठक यह भूमि संरिक्त वन मऽ शामिल कऽ गई थी जो न शा पेश था है उससे यह दखशक्त नहल होता ठक सवअ न बर 267 का कोई क पाटमै3 ट (भाग) था जो संरिक्त वन मऽ समाविष्ट है। इस आधार पर सेशन जज का फैसला उचित है - (डिवजनल फारेण्ट आफऽसर वि. गोरधन लाल - 1986 (II) म. अ. वी. नोट 182 जिंटस 3 ही. डी. यानी म. अ. हाईकोर्ट)

(4) धारा 52 (2) के अधीन हरपोट - अभिग्रहीत स पिक के स ब3 ध मऽ अभिग्रहण करने वाला अधिकारी अाधिकृत अधिकारी यथाशीघ्र ही अभिग्रहण के बारे मऽ हरपोट करेगा। यठद दाखिल क कायवाही तुर3 त आरंभ करने का मत हो तो विचारण कऽ अधिकाइरता रखने वाले मिजंटे को ऐसे अभिग्रहण कऽ हरपोट कऽ जायेगी। अभिग्रहण करने के समय तथा हरपोट करने के समय के बीच अ3 तर थोड़ा रहना चाहिये हत या महीने नहल बीतना चाहिये - (कमलेश कुमार हरवंश लाल छावड़ा वि. ठं टे ट म.

अ. - 1985 म. अ. ला. ज. 72 = ए. आय. आर. 1985 म. अ. 130 जिंटस मुले तथा जिंटस यानी);

(5) म॥ यदेश सरकार द्वारा धारा 52 तथा 55 मऽ ठकया गया संशोधन पूर्वगामी (भूतल) (Retrospective) नहल है अथात् संशोधन ठदनांक से पूर्व अभावी नहल है। संशोधित धारा 52(3) मऽ धारा 52(बी) के अधीन क3 सरवेटर फारेण्ट के आदेश के विषय स कोर्ट मऽ निगरानी (पुनरीक्षण-Revision) का अवधान है। धारा 52-सी के अधीन कोर्ट कऽ अधिकाइरता पर उस दशा मऽ रोक लगाई गई है जब वन अपराध काइरत करने मऽ अयोग्य मऽ लाये गये वनोपज या वाहन के बारे मऽ डिवीजनल फारेण्ट आफऽसर ने कोर्ट को यह इकुला कर दी हो ठक उनके अधिहरण (Confiscation) कऽ कायवाही अारंभ कऽ गई है - धारा 55 (संशोधित) के अधीन मिजंटे द्वारा अधिहरण का आदेश धारा 52(2) लगायत 52 सी के अ॥ यधीन (Subject to) रहेगा और धारा 54 के अधीन स पिक के ययन (disposal) का आदेश मिजंटे द्वारा ठदया जाना तभी संभव है जब अधिहरण कऽ कायवाही कऽ जाने कऽ कोई इकुला वन मऽ डलाधिकारी कऽ ओर से कोर्ट को नहल मिली हो - (अहमद जी वि. ठं टे ट म. अ. - 1985 JIJ 482 = 1985 म. अ. ला. ज. 243 = AIR 1986 म. अ. 1-जिंटस सी. पी. सेन तथा जिंटस अवं थी - (म. अ. हाईकोर्ट)

(6) धारा 52 म. अ. हाईकोर्ट के कूट परीक्षण का अवसर देने के लिए मामला लौटाया - एै तर तथा ङाली के अधिहरण (Confiscation) का आदेश था। हरइव फारेण्ट मऽ एक एै तर तथा ङाली को चैक ठकया गया और 290 ताजे बाँस और 9 ताजी बिलयाँ उनमऽ लदान कऽ गई पाई गई। एै तर को धरमदास चमकार द्वारा चलाया जा रहा

था। ए० टर के साथ ०मिकगण थे जि० ह० ने बताया ०क ये वनोपज ०रझव० फारे० ट से काटी गई है। नॉन ए० लीकै
 ट के कहने पर संगवही के आरि०त जंगल से काट कर सेमरा गांव ले जाई जा रही थी। म०यवर के पास ए०ंजिट पास नह
 था, इसिलये वनोपज को अभि०हीत ०कया गया हैर केस रिज० टर ०आ। म०यवर शो काज नो०टस पर जवाब आया ०क
 ए० टर ए०ली च००का० त उफ० रामवल का है जिसे उसने ही ०संघरोड़ी रोड के िलए पानी लाने के िलए लगाया गया
 था। धरमदास इस ए० टर का ० लीनर होना जवाब म० बताया गया। 1 अ००ैल 1984को काम समा० त होने पर ए०क
 धरमदास क० देख रेख म० छोड़ा गया था। जवाब के अनुसार ये बांस िन० तार के िलए सगुना, फददू िगरधारी, स० पत, श०
 भू, दारोनी, धरमदास ० लीनर क० परमीशन पर ले जा रहे थे। उ० ह० ने बांस तथा बि०लयां अपनी होने या उनके कहने पर काटे
 जाने के तः य से इ० कार ०कया। यह जवाब नामंजूर ०कया गया और अपराध धारा 52 सह प०ठत धारा 5 तथा 12 वन उपज ३
 यापार िविनयमन अधिनियम 1969 के अधीन ०कया जाना पाया गया। ए० टर ए०ली के अधिहरण (Confiscation)का
 आदेश ०दया गया। क० सरवेटर फारे० ट शहडोल (म० य०देश) के यहाँ अपील क० गई जो 16.08.1984 को खा०रज ०ई।
 अति०र ० त सेश० स कोट० के यहाँ ०र० हीजन क० या०चिका ००० तुत क० गई। जि०सम० यह िविनि त ०कया गया
 ०क अभियोजन ने यह सा०बित नह००कया ०क जि०स जगह से अभि०हण (Seizure) ०कया गया वह जगह आरि०त वन थी।
 मौ०खिक सा० य इस बारे म०काफ० नह० है तथा अभि०यु० तजन को वन अधिका०रय० ने जो गवाहान के कथन िलये उन पर
 कूट परी०ण (Cross examination)का अवसर नह००दया गया जो कानून के िवपरीत है उ० ह० ने िवचारण तथा अपील
 कोट० के िनण०य० को र० ०कया और ए० टर/ए०ली लौटाये जाने का आदेश ०दया गया। म० य०देश हाईकोट०
 म००० टेट म. ००. क० ओर से मामला प०००ने पर जि०टस गुलाब सी. गु० ता ने मानपुर D.F.O. को मामला लौटाते ०ए अभि०यु०
 त जन को गवाहान पर कूट परी०ण करने का अवसर देने के प० चात् कानून के अनुसार िनण०य० देने के िनद०श के साथ
 आदेश पा०रत ०कया। (०० टेट म. ००. िव. हीरालाल पटेल - 1993 FLT (समरी) 15 म. ००.)
 हाईकोट०, (जि०टस गुलाब सी. गु० ता (म.००.))।

(7) धारा 52, 52A तथा 52B के अधीन अधिहरण का आदेश - दुखी ३ पि० अ० थायी ३ यादेश (Temporary Injunction) के िलए ००ाथ०ना कर सकती है।

अ० थायी ३ यादेश के िलए मामले क० सुनवाई करते समय ३ यायालय को गुणागुण (on merits) पर मामले को
 नह०विचार म० लेना चा०हिये। अ० थायी ३ यादेश क० काय०वाही पूरक काय०वाही (Supplemental proceedings) होती है
 जि०सम० मूल मामले को ००ेस नह००कया जाता है। िसिवल ०००या संहिता क० धारा 94 (सी.पी.सी.) पूरक काय०वाही
 के िवषय म००० प० ट है धारा 94० लाज सी म००३ यायालय क० शि० अ० थायी ३ यादेश क० मंजूरी के बारे म० है। ३ यायालय
 जि०सके सम०० अधिका०रता का ००० न उठाया जाये उसे अ० त०रम आदेश जारी करने क० शि० है िबना इसके ०क पहले

अधिकाहरता पर विचार ठकया जाए। जब तक ठक अधिकाहरता का ठक न नकारा ठक न निणटत ठकया जावे तब तक ठकाथिमक टिकसे 3 यायालय को मामले से संबंधित कानून स ठक मत सम ठक त काय ठक एवं ठकसी काय ठकवाही को करने का अधिकार है - (ठकीतपाल ठसंह वि. ठ टेट म. ठ. 1988 ज.ला.ज. 549 = AIR 1989 NOC 207 (जिंस्टस ए. के. दुबे - म. ठ. हाईकोट ठक))

(8) धारा 52(2) तथा 54 - स ठक पिठु का 3 ययन - (disposal of property) इस काय ठकवाही म ठ अितम आदेश के अ यधीन बने रहकर अ तठरम 3 ययन का आदेश ठदया जा सकता है। बाद म ठ जो अितम (Final order) आदेश 3 यायालय का होगा उसके अनुसार अ तठरम आदेश ठभावित रहेगा। श ठ बीर अली वि. ठ टेट म. ठ. - 1986 ज. ला. ज. 469 = 1987 म. ठ. लॉ.

ज. 57 जिंस्टस 3 ही. डी. ठ यानी म. ठ. हाईकोट ठक)

(9) धारा 52-C द ठक ठक ठकया संहिता 1973 क धारा 451 तथा 457-वन अपराध काठरत करने म ठ किथत ठप से ठकयोग ठकये गये, अधहरण ठकये जाने वाले (of vehicle to be confiscated) यान क सुपुद ठकगी के आवेदन को मिजंटे नामंजूर कर ठदया। उस आदेश के वि ठक ठक हीजन हाईकोट ठक म ठ क गई जिंस्टस के.एल. इसरानी म. ठ. हाईकोट ठक ने ठरषीनाठसंह वि ठक टेट म. ठ. - 1992 F.L.T. 109 (म. ठ.) म ठ यह करार ठदया ठक जब ठक पुलिस ठक ठक नह ठ बि ठक र ठज अधिकारी ठक ठक अभ ठहीत (Seized) ठकया गया और उसे मिजंटे के सामने पेश नह ठकया गया तथा उस ठक के स ठक ब ठक म ठ धारा 52 फारे ठ ट ए ठ 1927 क आक ठक ठक होती है तब मिजंटे का अधिकारी उस ठक को अ तठरम अभर ठक म ठ ठदये जाने के बारे म ठ समा ठ त हो जाता है उसके अधिकार के बाहर क बात हो जाती है (बाबूलाल लोधी वि. ठ टेट म. ठ. 1987 म. ठ. ला. ज. 316 = 1987 ज. ला. ज. 423; तथा क ठैयाला वि. ठ टेट - 1988 ज. ला. ज. 94 अनुसठरत) - (मामले के तः य ये ठे ठक फारे ठ ट ठिडपाट ठकमे ठ ने एक ठक को 35 प ठर ले जाते ठए 8.12.1990 के ज ठ (Seize) ठकया था ठक ठ तु फारे ठ ट वि ठक क ठक ठक ठक म ठ ठक आवेदक ले भागने म ठ सफल हो गया। फारे ठ ट ठिडपाट ठकमे ठ ने इस बारे म ठ पुलिस ठ ठेशन रायसेन म ठ ठरपोट ठक दज ठक कराई, पुलिस ने केस धारा 353, तथा 186 सह पठठ धारा 34 (IPC) के रिजं ठर ठकया और बाद म ठ ठक चोरी होने के बारे म ठ धारा 379 (IPC) और जोड़ दी गई। अभयु ठ तो क जमानत 23.12.90 को ली गई और 25-12-90 को ठक ज ठ ठकया गया तथा चालान 26-12-90 को CJM रायसेन के सम ठकया गया। उसी ठदन आवेदक ने ठक के सुपुद ठकगी म ठ देने हेतु आवेदन धारा 451, 457 (CrPC) म ठ पेश ठकया। फारे ठ ट र ठज आठफसर ने एक आवेदन CJM को पेश ठकया ठिजसम ठ यह बातया गया ठक आवेदक के वि ठक फारे ठ ट ए ठ 1927 क धारा 26 म ठ केस रिजं ठक ठक है और ठक No. MPD 9007 वन अपराध से संबंधित है वन अधिकारी न यह भी ठिनेवेदन ठकया ठक धारा 52 फारे ठ ट ए ठ के अधीन वि ठक ठक 3 यायालय, ठक ठिमनल कोट ठक को इस

मामले मॄ आवेदन धारा 451, 457, CrPC के तहत विचार करने कऽ अधिकाऱता नहऱ है। अतएव ँायल कोर्टन ने ँक आवेदक को सुपुदऱगी मॄदये जाने का आवेदन िनरं त कर दया। सेशऽ सज के समींऱ हीजन िपटीशन फायल कऽ गई वह भी नामंजूर शई, उसके बाद आवेदक ने ऱरट िपटीशन नं. M.P. No. 473/1991 फाइल कऽ जो मंजूर होकर मिजंटे को यह िनदऱश दया गया ँक आवेदक के आवेदन पर ताजा िविनं चय (Fresh decision) इस ऽ यायालय ँऱा दनांक 21-3-91 मॄदये गए observations के ँकाश मॄ िलया जावे ँकऽ तु CJM रायसेन ने दुबार िविनं चय मॄ भी आवेदक कऽ सुपुदऱगी मॄदये जाने कऽ अजट नामंजूर कर दी। उसके िवऱ हाईकोर्टन मॄ पुनः ऱरऽ हीजन पेश कऽ गई थी।

इस ऱरऽ हीजन मॄ हाईकोर्टन के समीं यह भी तकऱंऽ तुत ँकया गया था ँक रेट िपटीशन मॄ हाईकोर्टन ने जो िनदऱश दये थे उससे आवेदक को सुपुदऱगी मॄ लेने के अधिकार अऱजऱत शए - इस तकऱ के िविनं चय मॄ पैरा 9, 10 मॄ 1992 FLT 109 (112) मॄजिंटस के.एल. इसरानी ने कहा ँक -

(1) Proceeding for embracing a right acquired or accured (2) and a legal proceeding for acquisition of a right इन दोन मॄ अऽ तर है, पहला िनिहत अधिकारी रींऽत है ँकऽ तु मेरी राय मॄ इस कोर्टन ँऱा ऱरट ऱरटीशन मॄदया िनदऱश ँक िविधक कायऱवाही सुपुदऱगी मॄ हीकल Vehicle लेने कऽ जाय - वह Saved असुरींऽत नहऱ है जबँक कोर्टन को फोरं ट विभाग से नोऱस और डिऱला िमल चुकऽ ँक वन अपराध के ँयोग से ऽ हीकल सऱ बिऽधत है इसिलये मिजंटे को आवेदक कऽ सुपुदऱगी मॄदये जाने बाबत आवेदन सुनते और िविनं चय कऽ अधिकाऱता नहऱ है (1990 MPLJ 188 = JLJ 249) (डौलूमल वि. ँं टेड म.ऱ. डीबी हाईकोर्टन म.ऱ.)

(10) ए.पी. ँीवां तव वि. ँं टेड म.ऱ. - 1990FLT 325 मॄ यऱदेश हाईकोर्टन - (जिंटस गुलाब सी. गुऽ ता- मॄ यऱदेश) धारा 319 तथा 482 CrPC) तथा धारा 420, 467 तथा 468-(IPC)- धारा 482 (CrPC) के अधीन आवेदन कऽ गा ता-विरले मामल मॄ शिऱयोग उस दशा मॄ जब िववशकारी पऱरिंथितयां शिऱयोग के िलए मौजूद हऱ अऽ यथा 482 CrPC के तहत हं तींेप नहऱँकया जा सकता।

मामले के संींऽ त तः य ये ह.ँक 15-1-1980 को धारा 379 (IPC) के अपराध के िलए ऱरपोटन दजऱन कराई गई। यह पुलिस ँं टेशन कऱडागांव मॄऱितऱथट नऱ बर 2, 3 तथा एक मृत िवनोद कुमार जो अब मर गया है - के नाम सिहत दजऱन शई। उसमॄ कहा गया ँक जंगल कऽ लकड़ी लॉट नऱ बर 996/1022 बेईमानी से अभियु त ँऱा फजट डाऱ यूमशट के आधार पर हटाई गई। पुलिस ने अपराध 420/467/468 (IPC) के अपराध कऽ चाजऱन शीट (चालान) ँथम ँेणी ऽ याियक मिजंटे जगदलपुर मॄ पेश कऽ, जब मामले मॄ चाजऱन लगाने के ँं न पर मिजंटे ने विचार ँकया तब आवसेदक कऽ भी ँं तता (involvement) ँं तुत

चालान के अपराध मश होना २तीत शई और मिजंटे ने धारा 319 (CrPC) के अधीन आवेदक को भी अभियुक्त (अपराधकता) कडोणी मश शामिल ठकये जाने और समन ठकये जाने का ओदश पाहरत ठकया। ओदश ठदनांक 29-11-1986 से दुखी होकर आवेदक ने मय देश हाईकोर्ट मश धारा 482 (CrPC) के अधीन हाईकोर्ट कड विशेषाधिकार कड शिष्य के अधीन मिजंटे द्वारा उड हश अभियुक्त त बनाये जाने के आदेश को िनरं त ठकया जाने का िनवेदन ठकया। जिंटेस गुलाब सी. गुड ता ने इस मामले मश धारा 482 CrPC कड शिष्य ठकन अवं था मश योग कड जा सकती ह. उनका इस मामले मश मौजूद होना नहल पाया और करार ठदया ठक २ाथिमक दिकमश मिजंटे ने हरकाड चालान आठद देखकर आवेदक के िवस मामला बनाना पाकर उड हश अभियुक्त त मश जोड़े जाने और समन ठकये जाने का ओदश ठदया है जो ठीक है इस ं तर पर उस ओदश मश कोई हं तौप धारा 482 CrPC के अधीन नहल ठकया जा सकता। इस मामले मश हाईकोर्ट ने िन न २कार से केस पर िवचार ठकया -

(1) जोगिडर संह िव. ं टेड पंजाब - AIR 179 SC 339, मश सुंीम कोर्ट लॉ कमीशन कड हरपोट (डमांक 41) के २काश मश िवचार करके िविनि त ठकया ठक यह सभी ड यायालय को लागू है, धारा 319 के अधीन ड यायालय को यह शि दी गई है ठक वह ऐसे ड यि/ड यिष्य के िवस जो मामले मश अभियुक्त त नहल बनाये गये ह. ठकड तु िजनके िवस िवचारण के दौरान अपराध मश अभिउं त होने कड पयाता त सां य है (against whom there appears sufficient evidence during trial, indicating his involvement in the offence as an accused) अड य अभियुक्त के साथ िवचारण ठकया जाने के िलए िनदश ठदया जा सकता है (हरीशंकर ड यास िव. ं टेड म. २. 1991 (1) म. २. वी. नो. 116) मश िभड न मत है)

जिंटेस गुलाब सी. गुड ता मय देश ने इस मामले मश सुंीम कोर्ट के उधृत केस मश शू द "Evidence" (सां य) का िनवचन ठकया। उनके अभमत मश धारा 319(1) CrPC मश शू द "Evidence" से अभिंय िवचारण के दौरान हरकाड कड गई केवल - 'evidence' नहल है बिड धारा 169 तथा 170 CrPC जो मिजंटे के समं मामले भेजने कडं टेज है उसमश भी शू द - 'evidence' योग ठकया गया है जो दशाता है ठक अपराध के अड वेषण के दौरान जो सामूी इकूी कड गई वह भी 'सां य' होना मानी गई है - (ए.पी. डीवां तव िव. ं टेड म. २. 1990 (1) म. २. वी. नो. 218) सुंीम कोर्ट ने रघुवंश दुबे िव. ं टेड िबहार मश अपनाये गये दिकोण का अनुमोदन ही - (AIR 1967 SC 1167) कड पुिही जोगिडर संह िव. ं टेड पंजाब AIR 1979 SC 339 मश भी है (अण दुबे िव. ं टेड म. २. 1991 CrLJ. 840 (844-845) मश कड है।

(11) ं टेड म. २. िव. राकेश कुमार - 194(1) MPJR 368 जिंटेस एस. के. दुबे, (डमिनल हरु हीजन नं. 191/1990 िनणत ठदनांक 14-6-1994 वलियर ब. च);

इस मामले के संदर्भ में तब से इस प्रकार है कि पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी) में यह देश को यह इलाका मिलने पर एक एक नंबर UTP 6276- अं सी बैग तथै पं ता-वन उपज लांजिट पार (पहरवहन परवाना) मिले बिना ले जा रहा है। पुलिस ने एक को 15-8-1990 (12.30 p.m.) पर Seize अभिग्रहण कर लिया। सीजर मेमो बनाया और मायवर राकेश को कं टडी मं लिया। एक केस धारा 379 (IPC) तथा मं यह देश तथै पं ता (यापार विनयम) अधिनियम, 1964 क धारा 5, 7 तथा 8 के अधीन पिछोर पुलिस द्वारा रिजं टर ठकया गया जो लाइम नं. 139/1990 पर कायम आ।

एक ज त करने के बाद पुलिस पिछोर (जिला शिवपुरी - म. र.) ने रज आठफसर शिवपुरी (म. र.) को इलाका दी एक वन अधिनियम के तहत वन अपराध ठकया गया है अतएव वह एक के अधिहरण (Confiscation) क कायवाही करे। इस इलाका के साथ F.I.R. तथा Seizure Memo क रिलिफ भेजी गई। डि टी डिवीजनल फारे ट ऑफसर शिवपुरी म. र. ने 20-8-1990 को चीफ जुडीशियल मिजं ट शिवपुरी (म. र.) को इलाका क एक सी ड रॉपट के वन अपराध मं योग ठकये जाने के कारण अधिहरण क कायवाही (Confiscation proceedings) रं भ क जा रही है - सी ड रॉपट एक No. UTP 6276 तथा 80 बै स तथै पं ता है।

राकेश कुमार हरं पांडे को अधिहरण क कायवाही के रं भ करने का नोटस ठकया गया लेकिन वह 1-10-90 के नोटस के बावजूद नियत ठकनांक 15-10-90 तक उपिंथत नहल। इसिले उपवन म डलाधिकारी ने एक पीीय कायवाही क और अपराध धारा 41 तथा 52 फारे ट ए ट, 1927 तथा धारा 5 म. र. तथै पं ता यापार (विनयम) अधिनियम, 1964 होने का साबित पाया।

इसी बीच रंथम रंणी मिजं ट पिछोर (शिवपुरी) के सम रं राकेश कुमार ने धारा 451 तथा 457 (CrPC) के अधीन अभिग्रहीत एक को सुपुदगी (custody) मं देने का आवेदन पेश ठकया। रज आठफसर क हरपोट के बाद हरं पांडे का आवेदन नामंजूर ठकया गया क य एक धारा 52 भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन अभिग्रहीत (seized) ठकया गया था। 3 यायिक मिजं ट रंथम रंणी पिछोर (जिला शिवपुरी म. र.) ने यह आदेश भी ठकया एक एक को कं टडी मं देने क यायालय को अधिकाहरता (Jurisdiction) नहल है। रंथम रंणी मिजं ट ने रज आठफसर पिछोर (शिवपुरी) को एक लेटर जारी ठकया एक अभिग्रहीत एक धारा 379 (IPC) के मामले मं भी केस रॉपट है इसिले उसके निग्नय तक ज त रॉपट को डिं पोज ऑफ नहल ठकया जावे।

इस आदेश से दुखी होकर हरं पांडे ट ने सेश स कोर्ट के सम रं हर हीजन पेश क। सेश स जज ने हर हीजन मंजूर करते ए यह समुि क (Observed) ठक यह शंकां पद है एक एक अधिहरण ठकये जाने यो य है या नहल और इस प्रकार निदश ठकया एक हरं पांडे ट को एक सुपुदगी मं Rs. 50,000 पचास हजार रुपये के बंध प पर ठकया जावे। इस आदेश के वि रं ट म. र.

ने हाईकोर्ट मंथ वॉलियर ब.च मंथरु हीजन पेश कऽ िजसमंथ जिंटस एस.के. दुबे ने िन. निलिखत िविनं चय ठकया :

(A) वन अपराध को कहरत करने मंथ वन उपज तथा ३ हीकल अधिग्रहीत (Seized) कऽ जाती है और अभिहरण कऽकायग्राही (Proceedings for Confiscation) ेअर. भ कऽ जाती है िजसकऽ डिफ़ला फारेंट ए. ट 1927 कऽ धारा 52(4) के अधीन अधिहरण कऽ कायग्राही के बारे मंथ अपराध का िवचाराधिकार रखने वाले मिजंटे एनोरा ेअर. त कऽ जाती है, तब कोई भी 3 यायालय 66 यूनल या ेअधिकारी-धारा 52, 52A तथा 52-B मंथ िनंदरु ट ठकसी को भी यह अधिकार नहल रहेगा ठक वह ेअं नाधीन ेअपटट के क ु जे, िडले ु हरी, िडं पोजल या िडं ी यूशन के बारे मंथ कोई आदेश दं। पैरा 5-[1994(1) MPJR 368];

(B) धारा 451 दं ु ड ेअऽया संहिता के अधीन अभिग्रहीत ेअपटट के िडं पोजल, (३ यय-िनराकरण) या िनपटारे के स. ब3 ध मंथ - मंथ यंदेश रा3 य वन अधिनियम मंथ धारा 52 अ3 तः ं थापित कऽ गई। अतः धारा 52C (सी) कऽ दंसे मिजंटे कऽअधिकाहरता समां त हो गई है (The jurisdiction of the Magistrate to make any order with regard to disposal etc. of the orders seized property under Section 451, CrPC is ousted in view of Section 52-C, inserted in the Forest Act (1) MPJR 368 (S.K. Duey, J)

(C) वन अपराध के िलये यह पेनट कोड या अ3 य ठकसी अधिनियम के अधीन अपराध कऽ साथ अपराध मंथ पुलिस आठफसर एनोरा 6 के सीजर (Seizer) धारा 52(1) के अधीन अधिहरण (Confiscation) कऽ कायग्राही के ेअर. भ कऽ जाने कऽडिफ़ला के पं चात् इस 3 यायालय कऽ राय मंथ कोई फकं नहल पड़ेगा और स. बि3धत मिजंटे कऽ धारा 451 तथा 457 तथा 457 CrPC के ेअवधान के अधीन अभिग्रहीत िवषय वं तु के स. ब3 ध मंथ अ3 तहरम या अि3तम अभिर्ा का आदेश पाहरत करने के िलए कायग्राही कऽ अधिकाहरता समां त रहेगी (will stand ousted)। वह ३ यि िजसके िव ु कायग्राही ेअर. भ कऽ है - उसे ेअधिकृत अधिकारी को इस बात का समाधान (तुं) करना होगा ठक इस ेअकार अभिग्रहीत कऽ गई स. पि ु अधिहरण ठकये जाने (Confiscation) कऽ दायी नहल है यठद अधिहरण ठकये जाने का आदेश ठदया जाता है तो ऐसे ३ यि को अपील के उपचार का और उसके बाद ु हीजन सेश3 स कोट मंथ करने का उपाय करना चाहिये जहाँ धारा 52-C(सी) के अधीन अधिकाहरता ेअदान कऽ गई है - Para 11-1994 MPJR 368 (at page 372-373) (मंथ यंदेश) (जिंटस एस. के. दुबे);

इसकऽ पुंमंथ अ3 य पूव ु के ुलंग मंथ यंदेश तथा अ3 य िनंदरु ट ठकये गये ह. -

(अ) क3 हैयालाल िव. ं टेट म. ेअ. - 1988 ज. ला. 94 -क फारेंट ट आठफसर एनोरा सीज ३ आ तथा कोट मंथ मंथ पेश नहल ठकया गया था। अधिहरण कऽ कायग्राही कऽ डिफ़ला धारा 52(4) के अधीन वन िवभाग ने मिजंटे को दी थी उस डिफ़ला धारा 52(4) के अधीन वन िवभाग ने मिजंटे कऽ अधिकाहरता सी3 ड ेअपटट के िडं पोजल करनेकेआदेश देने कऽ समां त हो जाती है।

(आ) हरषीनाथ ऋसंह वि. ँ टेट म. ०२. - 1992 म. ०२. ला. ज. 159 - केस पुलिस मं धारा 353 तथा 186

सहपठत धारा 34 (IPC) के साथ रिजं टर श्रुआ था, फारेण्ट विभाग ने ढक को सीज (Seize) ढकया था -

क३ हैयालाल केस - 1988 JLJ 94 तथा बाबूलाल लोधी वि. ँ टेट म. ०२. 1987 JLJ 423 का अनुसरण, करते

श्रुए डीबी म. ०२. हाईकोर्टने धारा 52-C के अधीन मिजंटे कऽ अधिकाहरता, सी३ ड ०२ापट२ के

िडं पोजन के स॒ ब३ ध मं वज्जनात मानी।

(इ) रंज फारेण्ट आढफसर वि. ढक रोडीलाल 1987 Cr. L.J. 1314 अधिकाहरता का वज्जान केवल धारा 52-

B(2) (IF Act) के तहत तब नहल रहता जब सेश३ स कोर्टने ह्रीजन कऽ सुनवाई करता है और अधहरण के आदेश के विरुद्ध कऽ गई अपील खाहरज कऽ जाती है।

(ई) टेट म. ०२. वि. कुंअर लाल - 1994 (I) म. ०२. वी. नोट 48 - िजसमंटे टर-लाली को प० थरु के

Slabs के साथ फारेण्ट आफऽसर ने सीज ढकया था और इकुला CJM को दी थी। धारा 457 CrPC का आवेदन

मिजंटे ने खाहरज कर ढदया था लेढकन सेश३ स कोर्टने ह्रीजन मंजूर कर ली थी उसके विरुद्ध

हाईकोर्टने म. ०२. ने आदेश ढदया ढक धारा 52, 52-A, 52-B और 52-C फारेण्ट ए० ट (म.०२. रा३ य

संशोधन) के देखने से सेश३ स, जज ढदया गया आदेश िब५ कुल अवैध है (is patently illegal);

(उ) अशोक कुमार वि. ँ टेट म॥ य०देश-ढमिनल ह्रीजन नं. 59/1989 िनण२त ढद. 13.4.1994) म. ०२.

हाईकोर्टने (Unreported case) मं यही अभमत ०२कट ढकया गया है।

(ऊ) Distinguished Cases - (I) भगवान भाई वि. वन म॥ डल अधिकारी - 1995 म. ०२. वी. नोट 44;(2) ँ टेट

म. ०२. वि. बंशीलाल 1991 म. ०२. वी. नोट 118०३ नाधीन मामले मं इसिलये लागू नहल होते ह॥ य० ढक इन

दोन० मामल० मं अधहरण (Confiscation) कऽ कायनावाही नहल०र॒ भ कऽ गई थी और इस बारे मं कोई

इकुला अधिकाहरता से संबंढित ३ यायिक मिजंटे को नहल दी गई थी।

(12) धारा 52-ए-अपील-अधहरण (Confiscation) के आदेश से दुखी ३ यि० - अपील - आदेश ढदये जाने कऽ

तारीख से या आदेश स॒ ब३ धी तः य कऽ संसूचना िमलने से जानकारी होने कऽ तारीख से तीस ढदन (thirty days) के भीतर

उस सरकल के ०२भारी वन संरं०क (अपील ०२ाधिकारी) को िजसके ००० मं वनोपज या स॒ पि० को अभ०हीत

(Seized) ढकया गया है - अपील कर सकेगा और अपील का ीापन िनयम (3) के अनु०प होगा तथा हं ताँ०हरत एवं स०

यापित ढकया जायेगा। आदेश कऽ०माणित ०२ितिलिप लगाई जायेगी तथा अपील के ीापन पर कोर्टने कऽं टा॒ प

पचास ढपये मू५ य के लगाये जाय०गे।

आदेश क९ नकल २/१० त करने मं लग्ग समय - अपील क९ च्च याद मं मुजरा ढदया जायगा - िप३ नूलाल िव.

०ीराम 1990 रा. िन. 371 पैरा 5 रे३ ह३ यू बोड ११, (िसकतर ऋसंह िव. ०३तीम ऋसंह - 1985 रा. िन. 430)

आदेश कऽ संसूचना (जानकारी) से अपील कऽ याद िगनी जायेगी और मानी जायगी - रामदीप िव. िगरधारी -

1987स. िन. 2401, िडवीजनल फारेँ ट आऱफसर पूवऱ बँ तर िव. इ३ दर ःसंह - 1973 स. िन. 578.

आदेश के विषय वं तु (तः य) कऽ जानकारी होना चाहिये, पाठ्य होने कऽ जानकारी काफऽ नहल है -

(बस३ त ५संह िव. ं टेट - (1972 रा. िन. 428 पैरा 4, तथा 6) छोटेलाल िव. म. ०. रा३ य 1988 रा. िन. 13, केशरी

वि. झ/बू- 1990 रा. नि. 2373 याय से इ३ कार नहल होगा,

(मोहरःसंह वि. जसवंत ःसंह - 1980 रा. वि. 16)

अपील का अधिकार - कानून मंजूर अधिकार (Vested right) है और कानून द्वारा सृजित (created by

Law) - कानूनी अधिकार (Statutory right) है इसे अ३ यथा नहॢ छीना जा सकता - छोगालाल वि. म. ०३. रा३ य 1994 रा. िन.

388 (जिंटस आर. ितवारी म. ०. हाईकोर्ट), (सीताराम िव. म. ०. रा३ य 1979 रा. िन. 509 पैरा 7 फुल ब.च हाईकोर्ट)

म. ३.) वि.

महाराजा मा० त० ज० ड० सिंह जू देव िव. किम० नर ऑफ ए० सपे३ डीचर टै० स - 1982 ज. ला. ज. 249 हाईकोर्ट०);

अपील मूल आदेश के विरुद्ध होगी -

आदेश अधिकांशतरिह त हो उसे िनरं त करना कतकन य है - (बाबूलाल िव. छोट लाल - 1975 797 पैरा 25

फुलब.च हाईकोट७५१)

कानूनी अधिकारी या हल यूनाइटेड किंगडम द्वारा पाठित आदेश यह युक्ति त त क संगत (Reasoned order) या

आयापक (Speaking order) नहलदया गया है तो वह िनरं त ढकये जाने योगय हो जाता है - अनल कुमार िव. अपीली

अथाहरटी - 1987 रा. िन. 185 पैरा 4 हाईकोर्ट ॥ म. ॱ. 1976 JLJ 293 फुल ब.च हाईकोर्ट ॥ म. ॱ. 1984 रा. िन. 398 पैरा

4, 7, 8 (AIR 1977 SC 112)

म. ँ. वन (अपील का फामह्ण) िनयम 1988

म. ँ. शासन, वन विभाग - अधिसूचना क्र. 18-3-88-X-3 दिनांक 30-11-88 भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र.

XVI वर्ष 1927) क\$ धारा 52 उपधारा (क) के उपखण्ड (4) तथा धारा 52(क)के उपखण्ड (1) के अंतर्गत 2 द०

त शि० य० का उपयोग म० लाते थे। ए० रा० य० शासन िन० न िनयम बनाता है अथा० न० :

(1) संिँज्ज त नाम, िवं तार तथा लागू होने कऽ ितिथ :

(1) ये नियम "मण् य ँ देश वन (अपील का फामफण) नियम 1988" कहलावशुगे।

(2) इनका विवठं तार सः पूणफण मण् य ँ देश पर है।

(3) ये नियम उस ितिथ से लागू हण्गे जो राऽ य शासन ँनः मण् य ँ देश राजपः मण् अधिसूचित कऽ जावे।

नोट - म. ँ. शासन वन विभाग, कऽ अधिसूचना ँ. 18-3-88-x-38दनांक 30 नवः बर,88 मण् य ँ देश वन (अपील का फामफण) नियम 1988 के नियम 1 के उपनियम (3) के अऽ तगफणत ँदः त शिण् यण् को उपयोग मण् लाते ँए राऽ य शासन 18दसः

बर

1988 वह ितिथ िनि त करता है िजस ँदन से उपरोण् त नियम लागू हण्गे।

2. पहरभाषाएं - इस नियम मण् जब तक ँक कोई बात नियम या सऽ दभफण के विपरीत न हो :

(क) "अधिनियम से ताः पयफण भारतीय वन अधिनियम 1927 (ँ. XVI वषफण 1927) िजस ँप मण् मण् य ँ देश मण् लागू है, होगा।

(ख) "अपीलीय अधिकारी" से ताः पयफण सकफणल के ँभावी वन संरण्क से है।

(ग) "ँाधिकृत अधिकारी" से ताः पयफण राऽ य शासन ँनः धारा 52 उपधारा (2) के अऽ तगफणत अधिकृत अधिकारी से है।

(घ) फामफण से ताः पयफण इस नियम के साथ संलण् न फामफण से है।

(3) (1) राजसात करने के आदेश के विवण् अपील : धारा 52(क) कऽ उपधारा (1) के अऽ तगफणत ँाधिकृत अधिकारी

ँनः पाहरत राजसात करने के आदेश के विवण्, अपील िाप मण् िनः न विवरण होना चाहिये यथा :

(क) वह िलिखत मण् होगा

(ख) अपीलकताफण के नाम व पते का उऽ लेख

(ग) उस आदेश, िजसके विवण् अपील कऽ जा रही है, के ँदनांक का उऽ लेख

(घ) अपीलकताफण को वह आदेश ँाऽ त होने के ँदनांक का उऽ लेख

(ङ.) घटना का ँ पः ट विवरण

(च) अपील के आधारण् का ँमवार उऽ लेख तकफण एवं विवरण सहित

(छ) संिण्ण त मण् चाही गई राहत का उऽ लेख

(ज) अपील आवेदन अपीलकताफण अथवा उसके अधिकृत अभकताफण ँनः िनः न फामफण मण् ँकाणित एवं हण् ताण्हरत

होना चाहिये - यथा :

म., ... ऊपर दिये अपील की अप मशहदया अपीलकताओं एतद्वारा घोषित करता हं एक अपील
मशहदया
विवरण मेरे निम्न विवरण के आधार पर सही है।

अपीलकताओं के हस्तान्तर

2. अपील का आवेदन अपील कताओं अथवा उसके अधिकृत अभिकताओं द्वारा अपीलीय अधिकारी को प्रेषित
से
(Personally) प्रेषित किया जावेगा।

3. अपील के निम्न पर पचास रुपये के कोटेशन काट प लगाये जावेंगे।

4. सचिव के राजसात करने का कायदावाही प्रारंभ करने का सूचना प्रेषित करना।

अधिनियम का धारा 52 उपधारा 4 के खण्ड (क) के अंतर्गत, अधिकृत अधिकारी, उस मिजेट को,
जिसको ज्ञात के

थान पर शेष अपराध के विचारण का अधिकार हो; सचिव के राजसात करने का कायदावाही प्रारंभ करने का
सूचना फाम
"A" मश देगा।

नोट : फाम "A" नीचे दया है।

फाम "A"

दस्तावेज

प्रेषक

.....

प्रति,

प्रयायिक दंड अधिकारी

.....

.....

(1) उस सचिव के विवरण जिसको राजसात किया जाना प्रेषित हो तथा उन परिस्थितियों का संज्ञा

त विवरण, जिसके कारण वह ज्ञात का गई हो।

(2) राजसात किये जाने के लिए प्रेषित सचिव के मालिक का पूर्ण विवरण :

(3) उस प्रेषक का नाम जिसके पास से वह सचिव ज्ञात का गई

- (4) ज० ती का ठं थान, ढदनांक एवं समय
- (5) उस अधिकारी का नाम, िजसने िवचाराधीन स० पि० ज० त कऽ।
- (6) िवचाराधीन स० पि० का अनुमांनित मू० य।
- (7) अपराध/अपराध० का िववरण िजसके कारण ज० ती कऽ गई।
- (8) िवचाराधीन स० पि० को राजसात करने कऽ काय०वाही ००र० भ करने का ढदनांक

००ाधिकृत अधिकारी के हं ताँर

ढट० पणी - Confiscation तथा forfeiture म० अ० तर है। भारतीय द० उ िवधान के अनुसार अधि०त (Confiscation) के आदेश देने के पूव०, िजसकऽ स० पि० अधिहरण कऽ जा रही है, उसको सुनवाई तथा बचाव का पू०० अवसर ढदया जाना चा०हिये। यह काय०वाही आवं यक है, ज० ती ढकसी अपराध म० जाँच के पं चात् िनमु० त हो सकती है।

धारा 53. धारा 52 के अधीन अभिगृहीत स० पि० को िनमु० त करने कऽ शि० - र०जर से अन० न पंि० वाला कोई वन अधिकारी, िजसने या िजसके अधीन० थ ने धारा 52 के अधीन कोई औजार, नाव, यान या कोई अ० य वं तु अभिगृहीत कऽ है, इस ००कार अभिगृहीत स० पि० को धारा 52 के अधीन ००ाधिकृत अधिकारी या मिजं०ट के समं०, जो उस अपराध का िजसके मं० अभि०हण ढकया गया है, िवचारण करने कऽ अधिका०रता रखता हो, जब ऐसा अपे०ित हो, पेश करने हेतु एवं अधिकारी ढ००रा यथा ००ा० किलत ऐसी स० पि० के मू० य के बराबर कऽ ऐसी रकम कऽ, ऐसे ००ा०प म०, जैसा ढक िविहत ढकया जाए, ००ितपू०त० का उसके ठं वामी ढ००रा िन० पादन करने पर उ० ह० िनमु० त कर सकेगा।"

धारा 54. तदुप०र ००ढया - ऐसी ढकसी ढरपो० कऽ ००ाि० पर मिजं०ट सब सु०विधापू० शी०ता से ऐसे उपाय करेगा जो अपराधी कऽ िगर०तारी और िवचारण तथा स० पि० का िविध के अनुसार ० ययन के िलये आवं यक हो :

०पर० तुस० पि० के ० ययन से स० बि०धत आदेश पा०रत करने के पूव० मिजं०ट यह िविनित कर०गे ढक ऐसी स० पि० के स० ब० थ म० धारा 52(4) के अ० तग०त ऐसी सूचना, इस ० यायाल०० या अ० य ० यायाल म० जो ज० त स० पि० के िवषय म० िवचारण (Try)हेतु सँ०म है, ००ा० त शई है या नह०।

धारा 55. वन-उपज, औजार आ०द कब अधिहरणीय ह०गे - (1) ऐसी सब इमारती लकड़ी या वनोपज, जो सरकार कऽस० पि० नह० है, और िजसके िवषय म० वन अपराध ढकया गया है और ऐसे वन िवषयक अपराध के करने म००यु० त सब औजार, नाव०, छकड़े और पशु अधिहरणीय ह०गे।

4(1) ऐसी समं त इमारती लकड़ी या वनोपज या दोन मं से येक दशा मं, जो सरकार कऽ सऽ पिछ नहल है और िजनके िवषय मं कोई वन अपराध ठकया गया है और समं त औजार, नावं, यान, रं से, जंजीरं, या कोई अ३ य वं तु िजनको येक दशा मं, ठकसी वन अपराध के करने मं येक योग ठकया गया है, अपराधी को ऐसे वन अपराध के िलये दोषिसं ठहराये जाने पर धारा 52, 52-क 52-ख, और 52-ग के उपब३ धं के अधीन रहते ए अधहरणीय होगी।

1. म.०. अध. ८. 7 वष 2010 ई० ई० आरा जोड़ा गया।

2. म.०. िवधान ८. 25 वष 1983 ई० ई० आरा जोड़ा गया।

3. धारा 54 के अ३ तगं त सऽ पिछ के ३ ययन को जो ०० वधान है उसमं सुपुदं नामा शांमिल है अतः एक सुपुदं नामे पर दी जा सकती है। (सांिबर अली िव. म. ०. शासन, 1987 धारा 57)

4. म.०. िवधान ८. 25 ई० ई० आरा 55(1) ०० तं थापित।

(2) ऐसा अधहरण, ऐसे अपराध के िलये िविहत ठकसी अ३ य द आ ड के अितरं त हो सकेगा।

हट० पणी (1) - यद मवेशी मांलिक अपनी मवेशी को अवैध ३प से वन मं चरवाहे के ई० ई० आरा चरवावे या ०० वेश करावे तो ऐसे मवेशी वन अधिनियम के अ३ तगं त राजसात् ठकये जा सकते हं। मवेशी अपराध के साधन है, ० यं ठक ऐसे मवेशी से अपहरण व पौधे नृ ट होते हं तथा ऐसे मवेशी को वन मं ०० वेश कराकर या उनसे चरवाकर ३ पि धारा 26 (च) का अपराध करता है अतः ऐसे मवेशी राजसात् ठकये जा सकते हं।

हट० पणी (2) - वन मं अवैध ३प मं वनोपज, या इमारती लकड़ी कऽ चोरी करने के िलए उपयोग मं आने वाले, बैल भी राजसात् ठकये जा सकते हं।

धारा 56. वन अपराध के िलये िवचारण कऽ समांि पर -उस वन उपज का ३ ययन िजसके सऽ ब३ ध मं यह अपराध आ है, जब ठकसी वन िवषयक अपराध का िवचारण समां त हो जाता है, तब वह वन उपज, िजसके सऽ ब३ ध मं ऐसे अपराध आ है, सरकार कऽ सऽ पिछ है या उसका अधहरण आ है तो वह वन अधिकारी ई० ई० आरा अपने भारसाधन (Charge) मं ली जावेगी, और ठकसी अ३ य दशा मं, उसका ऐसी रींति से ३ ययन (Disposal) ठकया जावेगा, जैसा ३ यायालय िनंदं ट करं।

धारा 57. जब अपराधी अंात है, या पाया न जा सके तब ०० टया -जब अपराधी अंात है, या पाया नहल जाता, तब यद मिजंेट का यह िनृ कषण है ठक कोई अपराध ठकया गया है, तो वह आदेश दे सकेगा ठक वह सऽ पिछ िजसके सऽ ब३ ध मं अपराध आ है, वह अधिऽत कऽ जावे और वन अधिकारी ई० ई० आरा अपने भारसाधन मं ले ली जाये या उस ३ पि को दे दी जावे िजसे मिजंेट उसका हकदार समझता है :

पर3 तु जब तब ढक ऐसी स॒ पि॒ड के अभि॒व॒हण क॒ तारीख से एक मास का अवसान न हो गया हो, या उस पर ढकसी अधिकार का दावा करने वाले ३ पि॒ड क॒, य॒द कोई हो, या ऐसे साँ य क॒, य॒द कोई हो, िजसे वह अपने दावे के समथ॒भ॒न म॒थ पेश करे, सुनवाई नह॒ हो जाती है तब तक ऐसा कोई आदेश नह॒दया जावेगा।

ि॒ट्ट पणी (1) यह धारा उस वन उपज के ३ ययन का ॒व॒धान करती है जो शासन क॒ स॒ पि॒ड नह॒ है ले॒कन उसके स॒ ब॒ ध म॒थ वन अपराध ॒आ है, ऐसी स॒ पि॒ड भी अधिहरण के यो॒ य है।

(इँा॒हिम अकबर अली ि॒व. रा॒३ य शासन व अ॒३ य (1963) (1) ढक. लॉ. ज. 664)

धारा 58. धारा 52 के अधीन अभि॒व॒हीत ि॒वन॑ वर (Perishable) स॒ पि॒ड ि॒वषयक ॒क॒दया - मिजँ॒ट॒ धारा 52 के अधीन अभि॒व॒हीत और शी॒व॒(Speedy) और ॒कृ॒ य (Natural), ी॒यशील (Decay) स॒ पि॒ड के ि॒व॒य के िलये इसम॒थ या इसके पू॒व॒अ॒ त॒व॒ ट ढकसी बात के होते ॒ए भी िनद॒श दे सकेगा और आगम॒(Sale Proceeds) को इस ॒कार बरत सकेगा, िजस ॒कार वह उस स॒ पि॒ड को बरतता य॒द बेची नह॒ गई होती।

धारा 59, धारा 55, 56, 57 के अधीन आदेश॒ क॒ अपील -वह अधिकारी िजसने धारा 52 के अधीन अभि॒व॒हण ढकया है या उसकेपदीय व॒र॒ ठ॒ म॒थ से कोई, या इस ॒कार अभि॒व॒हीत स॒ पि॒ड म॒थ ि॒हतब॒ होने का दावा करने वाला कोई ३ पि॒ड धारा 55 या 57 के अधीन पा॒रत ढकये गये ढकसी आदेश क॒ तारीख से एक मास के अ॒३ तर, उसके ि॒व॒ अपील, उस ३ यायालय म॒थ कर सकेगा िजसम॒थ ऐसे मिजँ॒ट॒ ॒द॒रा ढदये गये आदेश॒ क॒ अपील मामूली तौर पर होती है और ऐसी अपील कर पा॒रत आदेश अ॒३तम होगा।

धारा 60.(1) स॒ पि॒ड कब सरकार म॒थ ि॒निहत होगी - धारा 52 के अधीन ढकसी ॒ा॒धिकृत अधिकारी ॒द॒रा अधि॒त क॒जाने के िलये आदेशित स॒ पि॒ड धारा 52 (क) के अधीन अपील के पेश ढकये जाने पर या "॑ वे॒ेरणा" से क॒ जाने वाली काय॒वा॒हि॒य॒ के प॑ चा॒ धारा 52 (ख) के अधीन सेशन ३ यायालय के सम॒॑कये गये पुनरी॑ण क॒ काय॒वा॒हि॒य॒ के प॒रणाम के अ॒ याधीन रहते ॒ए, पुनरी॑ण क॒ काय॒वा॒ही समा॒ त हो जाने पर, सम॑ त ि॒व॒ लंगम॒(Encumbrances) से मु॒ त होकर सरकार म॒थ ि॒निहत होगी :

पर३ तु ऐसा ि॒व॒धान (Vesting) ि॒न॒ नानुसार होगा :

(क) जहाँ अपील ॒ा॒धिकारी के सम॑ कोई धारा 52 (क) के अधीन अपील करने के

अपील नह॒ क॒ जाती है या उसके ॒द॒रा वे॒ेरणा से कोई काय॒वा॒ही नह॒ क॒

िल॒ए या "॑ वे॒ेरणा" से काय॒वा॒ही करनेके िल॒ए ि॒न॒द॒ ट कालाविध का,

जाती है। अवसान हो जाने पर।

1. म.२. विधान ८. 25 वर्ष १९८३ कऽ धारा 7 द्वारा संशोधित।

(ख) जहाँ धारा 52 (क) के अधीन अपील धारा 52 के अधीन पुनरीक्षण के लिये

अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पाहरत ठकये जाते ह. ठक 3 तु धारा 52(ख) के

याचिका अं तुत करने के लिए विनिर्देश ट कालाविध का अवसान होने पर।

अधीन कोई पुनरीक्षण नहलठकया जाता।

(2) जब ठक, यथास्थित, धारा 55 या धारा 57 के अधीन ठकसी स. पिठ के अधिहरण के लिये आदेश पाहरत ठकया जा चुका है और ऐसी अपील के लिये धारा 59 द्वारा पहरसीमित कालाविध बीत गई है, और ऐसी कोई अपील नहलठक गई है, या ठक ऐसी अपील के ठकये जाने पर अपील 3 यायालय, ऐसी स. पूण १ स. पिठ या उसके ठकसी २ भाग के बारे मं ऐसे आदेश कऽ पु. करता है, तो यथा स्थित, ऐसी स. पूण १ स. पिठ या उसका ऐसा कोई २ भाग समं त वि, लंगम से मु त होकर सरकार मं निहत होगा।

धारा 61. अभिहित स. पिठ को निमु १ त करने कऽ शि कऽ यावृष्टि (Saving) - इसमं इसके पूर्व १ अ 3 तव १ ट ठकसी बात कऽ बाबत यह नहलठ समझा जायेगा ठक वह रा 3 य सरकार द्वारा इस निमित सश त अधिकारी को ऐसी स. पिठ को तुर 3 त निमु १ त करने के निदश देने से निवाहरत करती है जो धारा 52 के अ 3 तग १ त अभिहित कऽ गई हो।

हटो पणी

वन-अपराध मं २ यु त ज त ८ क को अधिकारी द्वारा समप ८ ठकए जाने के आदेश मं उ च 3 यायालय द्वारा विधिवत हं त ० प नहलठकया जा सकता है। (मोह. मद आशक वि. महारा. रा 3 य 2009 (1) C.C.S. (88)।

धारा 62. दोषपूर्ण अभिहण के लिये द १ ड - कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी तंग करने के लिये और अनाव ० यक १ से ठकसी स. पिठ का अभिहण इस बहाने से करता है ठक ऐसी अभिहित स. पिठ अधिहरणीय है, वह उस अविध के लिये कारावास से जो 2 (एक वर्ष १) तक का हो सकेगा या जुमा १ ने से जो 2 (एक हजार ० पये) तक का हो सकेगा या दोन से द १ डनीय हो सकेगा।

धारा 63. वृ ० एवं इमारती लकड़ी पर चि 3 ह के कूटकरण (Counter feiting) और विवपण (Defacing) करने और सीमा-चि 3 ह को बदलने के लिये शां ० त- जो ३ यि ठकसी लोक (Public) या ३ यि को हा ० नि पश ० चाने या ० ० त पश ० चाने या भारतीय द १ ड संहिता (1960 का 45) मं यथा - पहरभाषित सदोष (Wrongful) लाभ के आशय से -

(क) जानबूझकर ढकसी इमारती लकड़ी या खड़े वृक्ष पर लगे ढकसीऐसे चिह्न ह का कूटकरण करेगा जिसे वन अधिकारी यह उपदृष्टान्त करने के लिए प्रयोग करते ह.ढक ऐसी इमारती लकड़ी या वृक्ष सरकार कड या ढकसी यि कडस पितत है, या उसे, ढकसी यि द्वारा विधत्तः काटा या हटाया जा सकेगा, या

(ख) ढकसी वन अधिकारी या उसके िनदऱश के अ३ तगऱत ढकसी वृं या इमारती लकड़ी पर लगाये ढकसी ऐसे िच३ ह को बदलेगा, िवऱपित करेगा या िमटायेगा, या

(ग) ढकसी वन या पड़त भूमि (Waste Land) के, िजस पर इस अधिनयम के उपबं ध लागू होते ह. सीमा िच ह
को बदलेगा (Alters), सरकायेगा (Moves), नृ ट करेगा (Destroys) या िवश्रिप्त (Deface) करेगा वह कारावास से
िजसक ५ अविध 1[6 मास]से कम नहल होगी और दो वषर तक हो सकेगी या जुमांने से जो ५. 5000/- (पांच हजार
तक) या दोन से दिाडत हो सकेगा :

हटो पणी : (1) भारतीय दण्ड संहिता कड धारा 23 मथ सदोष लाभ (Wrongful gain) कड िन न पहरभाषा दी है -

"सदोष लाभ अथाज्ञात् गैर-कानूनी रूप से अज्ञात संप्रिप्त जिस पर लाभ पाने वाले व्यक्ति का कानूनी हक नहीं होता।"

(2) भारतीय दण्ड संहिता कड धारा 28 मऽ कूटकरण (Counterfeit) कड िन न पहरभाषा दी है -

"एक { यि□□IN=ारा कूटकरण ठकया गया है जब कहा जायेगा जो एक वं तु ऐसी बनाता है जो दूसरे के समऽप (Resemble) हो, और इस समऽपता से उसका उ□□ेँ य धोखा देने का हो या वह जानता हो ठक इस ०कार धोखा देने का कायऽन हो सकता है।"

2. म.उ. विधान 9 वर्ष 1965 धारा 32 द्वारा संशोधित।

1. विधान क्रमांक 7 वर्ष 2010-11 द्वारा संशोधित।

हटो पणी : (2) इस धारा के अ३ तगभूत ठकये अपराध का वन अधिकारी इलाका धारा 68 के अ३ तगभूत शमन (Compounding) नहठठकया जा सकता है।

हटो पणी : (3) इस िच3 ह से अभिे त वन भूमि क\$ बाहरी सीमा के अितहर□ त वन सीमा के अ3 दर क\$ सीमा से भी है जो यह ेदःशक्त करे या पृथक् करे ढक ढकस खंड के वृि िगराये जाने ह। जैसे काटने वाले कूप□ क\$ सीमा िच3 ह। (देखथ AIR 1943नागपुर, पृ ठ 139-140)

धारा 64. वारंट के बिना गिरफ्तारी करने का शि

- (1) ठकसी ऐसे ३ यि□ को, िजसके िव□ या युि□यु□ त स३ देह िर्वमान है ठक वह एक मास या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय ठकसी वन अपराध से स॒○□ त (Concerned) है कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी िबना ठकसी मिजँटे के आदेश□ के या िबना ठकसी वारंटे के िगरतार कर सकेगा।
- (2) इस धारा के अधीन िगरतार करने वाला हर अधिकारी िबना ठकसी अनावँ यक िवल॒ ब के और ब३ धप्पु पर िनमुण्ण□ त करने स॒ ब३ धी अधिनियम के उपब३ ध□ के अधीन रहते णए िगरतार ठकये ३ यि□ को ऐसे मिजँटे के, िजसे इस मामले म३ अधिकाइरता ॒○ा॒ त है, के समँ○ या िनकटतम पुलिस ठं टेशन के भारसाधक अधिकारी के पास ले जावेगा या भेजेगा।
- (3) इस धारा ठकसी बात क३ बाबत यह नहए समझा जावेगा ठक वह ऐसे कायण्ण के िलए जो अ॥ याय 4 के अधीन अपराध ह., तब तक ठक धारा 30 के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा कायण्ण॒तिष□ न कर ढदया हो।

(1) ढट॒ पणी - यॢद कोई ॒ ला३ टेशन वाचर ठकसी ३ यि□ को संदिँत वन म३ िनिष□ वँ○ काटते देखता है, तो उसको वँ○क३ रँ○ा ठक िनिम॒ त उस ३ यि□ को पकड़ना पड़ेगा तथा यह माना जावेगा ठक ॒ ला३ टेशन वाउचर भा.व.अ. क३ धारा 2(2) के अ३ तगण्णत "वन अधिकारी" है।

नोट : ॒ ला३ टेशन वाचर के क३ जे से छूट भागना धारा 224 IPC के अ३ तगण्णत अपराध है, साथ ही ॒ ला३ टेशन वायर को चोट पञ्चाना धारा 332 भा. व. द. िव. के अ३ तगण्णत अराध है।

(अ३ दुल अजीज िव. यूनिनयन टेरीटरी िपुरा 1963(1) CRI LJ 558)

धारा 65. ठकसी िगरतार ३ यि□ को ब३ धप्पु पर िनमुण्ण□ त करने क३ शि□ : वन ै○ेपल (Forest ranger) से अिन॒ न पंि□ को कोई वन अधिकारी िजसने या िजसके अधीनं थ ने, धारा 64 के उपब३ ध□ के अधीन ठकसी ३ यि□ को िगरतार ठकया है, ऐसे ३ यि□ को उसके ढरारे यह ब३ धप्पु िन॒ पाॢदत ठकये जाने पर िनमुण्ण□ त कर सकेगा ठक यॢद या जब ऐसी अपेँ○ा क३ जावेगी, तो और तब म. मामले के मारे म३ अधिकाइरता ॒○ा॒ त मिजँटे के समँ○ या िनकटतम पुलिस ठं टेशन के भारसाधक अधिकारी के समँ○उपिँथत हो जाऊँगा।

धारा 66. अपराध□ का ठकया जाना िनवाइरत करने क३ शि□ - हर वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी ठकसी वन िवषयक अपराध के ठकये जाना को िनवाइरत करेगा और उसे िनवाइरत (Prevent) करने के ॒○योजन□ के िलये हँ तँेप कर सकेगा।

धारा 66-क. अपराध का ॒○य॒ न या दु॒○ेरण - कोई ३ यि□, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए िनयम□ के ठक३ हए उपब३ ध□ का उ॒ लंघन करने का ॒○य॒ न करेगा या उसके उ॒ लंघन करने का दु॒○ेरण करेगा, उसके बारे म३ यह समझा जाएगा ठक उसने ऐसे उपबंध□ या िनयम□ का उ॒ लंघन ठकया है।"

धारा 67. अपराध का सिंौत विचारण (Summary Trial) करने कऱ शि - िजला मिजैेट या राऱ य सरकार ँऱा िनिम त विशेषतया सश त कोई ँथम वगऱ मिजैेट, दऱ ड ँऱया संहिता, 1898 (1898 का 5)के अधीन ँकसी ँसे वन विषयक अपराध का सिंौत ततः विचारण कर सकेगा जो 2(एक वषऱ) से अनिधक कारावास या 2(एक हजार ँपये) से अनिधक जुमाऱने से या दोन से दऱ डनीय है।

1. म.ँ. विधान ँ. 7 वषऱ 2010ँऱा संशोधित ।

2. म.ँ. विधान ँ. 9 वषऱ 1965ँऱा संशोधित ।

धारा 68. अपराध का ँशमन करने कऱ शि - राऱ य सरकार, राजपू मऱ अधिसूचना ँऱा ँकसी वन अधिकारी को शिँदान कर सकेगी ँक वह -

- 1(क) ँकसी ँसे ३ यि से, िजसके विऱ या युिऱु त सऱ देह विमान है ँक उसने धारा 62 या धारा 63 मऱविनंदऱ ट अपराध से िभऱ न कोई वन अपराध ँकया है, उस अपराध के िलए, िजसके बारे मऱ यह सऱ देह है ँक उसने ँसा अपराध ँकया है, ँतितकर के ँप मऱ कोई धनरािश ँतितगृहीत करे; और
- 1(ख) जब कोई सऱ पिऱ अधहरण ँकए जाने के दािय वधीन होने के कारण अधगृहीत कर ली गई है, तब समुचित ँाधिकारी ँऱा अधहरण का आदेश पाऱरत ँकए जाने के पूवऱ ँसे अधिकारी ँऱा यथा ँा किलत उसके मूऱ य का संदाय कर ँदए जाने पर, उस सऱ पिऱ को िनमु त करे।
- 1(2) ँसे अधिकारी को, यथािठित ँसी धनरािश या ँसे मूऱ य, या दोन का संदाय ँकए जाने पर, संदिध ३ यि को, यऱद वह अभरौा मऱ है, उऱ मोचित कर ँदया जाएगा, और अभगृहीत कऱ गई सऱ पिऱ, यऱद कोई हो, िनयुऱ त कर दी जाएगी तथा ँसे ३ यि या ँसी सऱ पिऱ के विऱ आगे कोई कायऱवाही नहऱ कऱ जाएगी।
- 1(3) कोई भी वन अधिकारी ँस धारा के अधीन तब तक सश त नहऱ होगा जब तक ँक वह रऱजर कऱ पंि से अिनऱ पंिका वन अधिकारी नहऱ है, और उपधारा (1) के खऱ ड (क) के अधीन ँतितकर के ँप मऱऱतितगृहीत धन कऱ रािश ँकसी भी मामले मऱ वन उपज के मूऱ य के दो गुने से कम नहऱ होगी :
परऱ तु ँसी वन उपज के मामले मऱ िजसके संबंध मऱ कोई अपराध ँकया गया है, और जो सरकार कऱ सऱ पिऱ नहऱ है या ँसी वन उपज के मामले मऱ िजसका मूऱ य एक हजार ँपये से कम है तथा यऱद अपराधी ने ँथम बार अपराध ँकया है, तो संऱदध ३ यि को उऱ मोचित ँकया जा सकेगा और अभगृहीत कऱ गई सऱ पिऱ, (वन उपज से िभऱ न), यऱद कोई है, दस हजार ँपये कऱ रािश के संदाय पर या अभगृहीत सऱ पिऱ के मूऱ य

पर, जो भी कम हो, निम्नलिखित त कड़ा जा सकेगी, अभिगृहीत वनर उपज केवल तभी निम्नलिखित त कड़ा जा सकेगी जब वह यथास्थित सरकार कड़ा सके पिछ नहल है या जब उसके मूँ य का संदाय कर ढदया जाता है।"

22. रा3 य शासन धारा 68 के अ3 तगढ़ात वन अपराध का शमन (Compound) करने के िलये िन न अधिकाइरय को अधिकृत करती है -

(i) समं त कले टर, एंटां अजं टश्ट किमं नर और तहसीलदार।

(ii) समं त वन संरंंक, उप वन संरंंक, सहायक वन संरंंक, अित. सहायक वन संरंंक, तथा वन ेपाल िजनका मासिक वेतन 100/-०. से कम न हो तथा उसकड़ा सेवा वन ेपाल के ३प मश दस वषढ़ा से कम न हो।

पर3 तु :

(अ) अधिनियम कड़ा धारा 79 के अधीन अपराध सके स ब3 ध मश अधिकार का उपयोग केवल कले टर, वन संरंंक या वन म डल के ेभारी ही कर सकशगे।

(ब) वन ेपाल अधिकार का उपयोग तब ही कर पावशगे जब उनको वन संरंंक िन नारा इस हेतु िवशेष ३प से अधिकृत ढकया जावे।

(2) इस ेकार ेतिकर के ३प मश िनधाढ़ात रािश पुनरींण मश िन नानुसार अधिकाइरय िन नारा घटाई जा सकेगी -

(अ) िजला यं िन नारा, यढद िनियम कड़ा उपधारा (i) मश िनधाढ़ात करने वाला अधिकारी पद मश िजला यं से िन न ह।

(ब) वन संरंंक िन नारा, यढद रािश का िनधाढ़ात करने वाला अधिकारी वन म डल का ेभारी अधिकारी हो।

(स) वन म डल के ेभारी अधिकारी िन नारा यढद रािश का िनधाढ़ात उस अधिकारी िन नारा ढकया गया हो जो उसके अधीन हो।

ढट० पणी (1) ऐसे वनअपराध िजसमश आइरंंत वन मश अवैध ३प से वृं कटाई का आरोप हो तो वन अधिकारी, जो रा3 य शासन िन नारा ेभारिधकृत हो, ऐसे अपराध का राजीनामा कर सकता है तथा लकिडय का बाजार मूँ य वसूल कर सकता है - (देखश म. े. लॉ जनरल 1957 पृ० ठ 622 वीर ःसंह गौड़ िव० म. े. शासन)

1. म.े. िवधान ८. 7 वषढ़ा 2010 िन नारा संशोिधत ।

2. फारें ट मे3 युअल के अ॥ याय XV, पैरा 80 नोढटढफकेशन नं. 161-910-XV ढद. 15.2.32 ।

धारा 69. यह उपधारा एक वन उपज सरकार कऽ है - जब एक इस अधिनियम के अधीन कऽ गई कायफऽावाही मऽ या इस अधिनियम मऽ या इस अधिनियम के अधीन एकये गये एकसी कायफऽा के पहरणामऽ वऽप ऐसा ेऽ न उठता है एक या वन उपज सरकार कऽ है या नहऽ, जब तक एक ेऽितकूल साऽिबत न कर ऽदया जावे, यह उपधारणा कऽ जायेगी एक यह सरकार कऽ सऽ पिऽ है।

अ॥ याय 10

पशु अितचार

धारा 70 पशु अितचार अधिनयम, 1871 का लागू होना - ढकसी आरिँत वन मः या ढकसी संरिँत वन के ढकसी ंभाग मः, जो िविध पूवक (Lawfully) चरागाह के िलये बः द ढकया गया है, अितचार करने वाले पशु को, पशु अितचार िनयम 1871(1871 का 1) धारा 11 के अथक मः लोक बागान (Public Plantation) को नुकसान करने वाला पशु समझा जावेगा और ढकसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा अभिहीत (Seized) और पहरब (Impound) ढकया जस सकेगा।

धारा 71. इस िनयम के अधीन िनधाभाहृत जुमाफाना को बदलने क\$ शिा - रा3 य सरकार राजप्ू मऽ अधिसूचना 177/रा िनदश दे सकेगी ःक पशु अितचार अधिनयम, 1871 (1871 का 1) क\$ धारा 12 के िनयत जुमाफाने के बदले इस अधिनयम क\$ धारा 70 के अधीन पहरबा हर पशु के िलये ऐसा जुमाफाना उऱहीत (Levied) ःकया जावेगा जैसा वह ठीक समझती है ःक3 तू वह िन निलिखत से अधिक नहः होगा -

- 1(i) ०_20 येक हाथी के िलये एक हजार अपये

- 1(ii) ०२० एक ऊँट के िलये दो सौ पचास ापये

- 1(iii) z_0 एक भ.स के लिये एक सौ प्रपया

- 1(iv) ०३० येक घोड़ा, खं सी टनट्ट एक सौ अपया

बछेड़ा, बछेड़ी, खल्लू चर, सांग, बैल, गाय या बछड़ी (Heifer)

- 1(iv) ०२० येक बछड़े (call) गधा सुअर, मेढ़े, मेटी, मेमने, बकरी या उसके मेमने पचास रुपये

नोट - परतु पहरबता कऽ कालाविध के दौरान ऐसे पशु के रखरखाव का खचका वन मडुलाधिकारी

₹ द्वारा जमा होने के अतिरिक्त त नियत क\$ गई ंचिलत दर पर वसूलीय होगा।

नोट - पशु अितचार िनयम अलग पढरिशु ट मउठदया है।

1. म.उ. विधान ८. 7 वर्ष 2010-11 द्वारा संशोधित ।

अ॥ याय ११

वन अधिकाइरय के स॒ ब३ ध म॑

धारा 72. रा३ य सरकार वन अधिकाइरय के कितपय शि॒याँ विनिहत कर सक॑गी -

(1) रा३ य सरकार ढकसी वन अधिकारी म॑ िन॒ निलिखत सब शि॒याँ या उनम॑ से कोई शि॒ विनिहत कर सकेगा, अथा॑त् -

(क) ढकसी भूमि पर जाने और उसका सव॑ण, सीमांकन या न॒ शा तैयार करने क॑ शि॒ ।

(ख) सा॒ि॒य को हा॒जिर होने के िलये और द॑ तावेज॒ (Documents) एवं सारवान् (Material) व॑ तु॒ को पेश करने के िलये िववश करने वाल िसिवल ३ यायालय क॑ शि॒ ।

(ग) द॒ ड ॒ ढया स॒हिता (1988) के अधीन तलाश वार॒ ट िनकालने क॑ शि॒ और

(घ) वन िवषयक अपराध॒ क॑ जाँच करने और ऐसी जाँच के दौरान सा॑ य लेने और उसे अभिलिखत करने क॑ शि॒ ।

(2) उपधारा (1) के ख॒ ड (घ) के अधीन अभिलिखत कोई सा॑ य मिज॑ट के सामने प॑ चा॒वत॒

विचारण म॑वा होगा य॑द वह अभियु॒ त ३ यि॒ क॑ उपि॑थित म॑ िलया गया हो।

धारा 72 के अ३ तग॑त बने िनयम - (नोटी॑फकेशन नं. 1126॑द. 22-11-1911)

रा३ य शासन सम॑ त वन अधिकाइरय को जो वन म॒ डल के ॒भार म॑ है, और सम॑ त सहायक वन संर॑क को, (िज३ ह॒ने फारे॑ ट कोड क॑ धारा 40 म॑ िनधा॑त वन िविध क॑ परी॑ा पास कर ली है) धारा 72 के अ३ तग॑त सम॑ त अधिकार उनके ॒भाग-ि॒ म॑ उपयोग करने हेतु अधिकृत करती है। साथ ही सम॑ त प॒रि॒ अधिकारी एवं सहायक प॒रि॒ अधिकारी िज३ ह॑ वन अपराध॒ क॑ जाँच हेतु अधिकृत ढकया गया है, सा॒ि॒य को हा॒जिर होने के िलये समन जारी करने हेतु अधिकृत करती है।

सा॑ य को भोजन ३ यय (Diet money) का भुगतान - वन अधिकाइरय॒ ारा क॑ जा रही वन अपराध॒ क॑ जाँच म॑उपि॑थत होने वाले सा॑ य क॑ वन-म॒ डलाधिकारी ारा भोजन ३ यय का भुगतान ॑थानीय ३ यायालय॒ म॑चिलत दर से, या िजला॒ यि॒ ारा िनधा॑त दर पर कर सकता है।

ढट॒ पणी (1) धारा 72 के अ३ तग॑त वन अधिकारी ारा अभियु॒ त के सम॑ तथा उसका ॒तिपरी॑ण का अवसर ॒दान करने के बाद िलये गये सा॑ य, दि॒ डक ॒करण के िलये मह॑ वपूण॑ सा॑ य है जो द॒ डाधिकारी के सम॑योग ढकये जा सकते ह॑ ।

(ज.लॉ.जन॑ल 1960॑ट॒ पणी 160, स३ जन ॒संहि॒व. म. ॒. रा३ य)

(2) ऐसे वन अधिकाइरय को िज३ ह॑ धारा 72 के अ३ तग॑त ॒ाधिकृत ढकया गया हो, जाँच पड़ताल, के अधिकार ह॑. तथा बयान शपथ पर िलिपब॒ करने का अधिकार है।

(3) इस धारा के अ३ तगभ्णत रा३ य शासन ँनारा ँाधिकृत वन अधिकाइरय॥ को ३ यवहार ँडया संहिता, 1908 तथा अब ३ यवहार ँडया संशोधन अधिनियम, 1976 के अ३ तगभ्णत ३ यवहार ३ यायाधीश के वे अधिकार समावि३ ट ढकये गये ह. जो ३ यवहार ँडया संहिता के अ३ तगभ्णत सांिीय॥ को आॢत करने तथा लेख ँं तुत करने का है तथा अ३ य त० समय ँावधान सिमिलत है।

धारा 73. वन अधिकाइरय॥ को लोक सेवक समझा जावेगा - सभी वन अधिकाइरय॥ को भारतीय दल्ल ड विधान संहिता (1860 का 45) के अ३ तगभ्णत लोक सेवक समझा जायेगा।

धारा 74 स॥वपूवभ्णक ढकये गये काय॥ के िलये पइरूाण -

इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये िनयम॥ या ढकसे गये आदेश॥ के अधीन सद्भावनापूवभ्णक कड गई या 2इस ँकार कड जान॥ सेछोड़ दी गई ढकसी बात के िलये ढकसी लोक सेवक के िव॥ कोई वाद, अभयोजन या अ३ य िविधक कायभ्णवाही नहल होगी।

ढट० पणी - (1) सद्भावनापूवभ्णक कड पइरभाषा भातीय दल्ल ड विधान, 1860 कड धारा 52 म॥ दी है। िजसके अ३ तगभ्णत कोई बात "सद्भावनापूवभ्णक " कड गई या िव॥ वास कड गई नहल कही जाती यढद वह स॥ यक् ११ यान के िबना कड गई या िव॥ वास कड गई हो।

(2) ए.आई.आर. 1960 उड़ीसा 151(163) पर यह ँतिपाढदत ढकया है ढक "सद्भावनापूवभ्णक" कायभ्ण का िवचार अभयु॥ त कड िंथित तथा ढकन पइरिंथितय॥ म॥ उसने कायभ्णढकया है उसके स॥ ब३ ध म॥ देखा जाना चािहए।

ढट० पणी

वन अपराध म॥३ यायालय ँनारा उसका संीान िलए जाने पर इस धारा के ँावधान ँयो३ यनीय ह.।
(योगेश िव. योगे३ंगल. िव. म.०. रा३ य वगल. 2013(1) म.०.लॉ.ज. 498 (खंडपीठ म.०. = 2013 (1) म.०.वी.नो. 172 (खंडपीठ म.०.)).।

धारा 75. वन अधिकारी ३ यापार नहल कर॥गे - रा३ य सरकार कड िलिखत अनुीरि के िबना कोई वन अधिकारी, मािलक या अभक० ताभ्ण के ३प म॥ इमारती लकड़ी या अ३ य वन उपज का ३ यापार नहल करेगा, या ढकसी वन के प॥े (Lease) म॥ या वन के ठेके म॥ िहतब॥ नहल होगा या बनेगा चाहे वे उन रा३ य ँेे० के, िजिन पर यह िनयम िनं ताइरत होता है, अ३ दर हो या बाहर हो।

धारा 76. िनयम बनाने कड अितइर॥ त शि॥याँ - रा३ य िन॥ निलिखत के िलये िनयम बना सक॥गी -

(क) इस अधिनियम के अधीन ठकसी वन अधिकारी को शिफ्ट या कंट्रोल यंत्र को निहित व सीमित करने के लिये।

(ख) इस अधिनियम के अधीन जुमाफाना और अधिहरण के आगमन मश से अधिकांश और सूचना देने वाले पुराने कार का विनियमन करने के लिये।

(ग) सरकार के वृक्ष और इमारती लकड़ी का जो क्लायवेट प्रिय कड भूमि मश उगे जाए ह. या उनके अधिनियम मश है, के संरक्षण पुनरोपादन, और प्रयोजन करने के लिये, और

(ग-क) इस अधिनियम कड धारा 53 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निमुक्त त ठकए जाने के लिए दी जाने वाली प्रतिभूति का प्रमाण विहित करने के लिए,

(ग-ख) इस अधिनियम कड धारा 80-ए कड उपधारा (3) के अधीन वन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध रात्र य शासन को या इस निमित्त त रात्र य शासन द्वारा प्रमाणित ऐसे पदाधिकारी को अपील करने कड कालाविध और रीति विहित करने के लिए,

(घ) साधारणतः इस अधिनियम के उपबन्ध को प्रमाणित करने के लिये।

धारा 76. के अंतर्गत बने नियम - अधिसूचना 130-130-484-XV-8द. 31.1.281. 624-625-341-XV-8द. 12-6-28 एवं 1. 78-XV-8द. 12-6-29

(धारा 76 (क) एवं (ख) के अंतर्गत)

(1) समस्त वन संरक्षक, समस्त कलेक्टर, असिस्टेंट टैक्स कमिशनर, उप वन संरक्षक, सहायक वन संरक्षक, अतिरिक्त सहायक वन संरक्षक (अब सहायक वन संरक्षक) (चाहे वे प्रबेशन (Probation) हों या अत्र यथा) तहसीलदार, वन इंस्पेक्टर, उप वन इंस्पेक्टर, वनपाल, वनरक्षक, (चाहे वे अत्र थाई नियुक्ति पर हों, या अत्र थाई) को इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त त कार्यान्वयन करने एवं अधिनियम मश्रुत वन अधिकांश के अधिकार का उपयोग करने हेतु नियुक्त त ठकया जाता है।

1.

मश य प्रदेश अधिनियम 9, वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

2. म. प्र. विधान 1. 25 वर्ष 1983 द्वारा पुनः संशोधित।

(2) निम्न तालिका मश्रुत कॉलम मश्रुत अधिकारी उनके आगे कॉलम 2 एवं 3 मश्रुत दशांक्ये अधिकार का उपयोग

करशे :

अधिकारी का वर्ग

धारा

अधिकार का संक्षेप त उ, लेख

(1) (2)

(3)

(1) समस्त उपवन संरक्षक तथा सहायक वन

21

आरिक्त वन कड अधिसूचना के प्रांत तरण

संरंिक जब वे वन म डल के ेभार मशहो।

26(1) (c) ऐसी अविध (Season) कऽ अधिसूचना जारी करना जब

वन मश आग जलाना ेतिब न हो।

45 (2) बहती शई (Drift timber) लकड़ी के िडपो घोषित करना।

46 ब हती शई लकड़ी के दावेदार को सूचना देना।

47 बहती लकड़ी के दाव को िनपटाना।

50 बहती लकड़ी के स ब 3 ध मश भुगतान लेना।

61 ज त स पिड को छोड़ने के िनदश देना।

83 (a) शासकऽय बकाया धन कऽ वसूली के िलये वनोपज का बेचना।

80 'A' आरित एवं संरित वन कऽ भूमि पर से अवैध क जेदार

(2) समं त िजला यी (Collectors), उप वन 26 (2) धारा 26 (1) मश ेतिबिधत काय कऽ अनुमित

देना। संरंक, सहायक िजलाधीश (Asstt. (a)

Collector) उप-िजलाधीश (Dy

Collectors) सहायक वन संरंक, उप

वन म डलाधिकारी, तहसीलदार, वन

ेपाल, पडरिे अधिकारी, तथा

उप

वन ेपाल तथा वनपाल जब वे वन

संरंक िवशेष, ाप से

अधिकृत ह।

(3) 41, 62 म. े. ािजट े 1961 कऽ धारा 14 के अधीन

िडपो थापित करना जहाँ वनोपज परीेण, हैमर लगाने एवं

वसूल होने यो य रकम का िनधाकरण करने हेतु ले

जाई जावेगी। म. े. ािजट (फारे ट ेोूज)

(Device) के रिजेंेशन का सटटफकेट देना।

52-(A) धारा 52(3) के अधीन ेाधिकृत अधिकारी िवशेष पाडरत

आदेश पर अपील या Suo-moto कायवाही करना।

(4) समं त वन संरंक, वन म डलाधिकारी, 41 म. े. ािजट (फारे ट ेोूज) े 1961 कऽ

धारा 4(1) उप वन म डलाधिकारी, या उपरो त 42 (A)

तथा उसके ेावधान के अ 3 तग शासन कऽ वनोपज अधिकाय िवशेष िलिखत मश अधिकृत

(जो 8कसी ३ पि क\$ न हो) के पहरवहन के लिये लांजिट

३ पि।

पास जारी करना।

(5) समं त उप वन संरंक, वन संरंक या 72 (a) अपने-अपने ०३भार ००े मश -

उप वनम डलाधिकारी जि३ हने शासन

(1) 8कसी जमीन पर ०३वेश करने, उसका

सवण,

३३३ारा निधाहरत विभागीय परींा मश'वन

सीमांकन करने या उसका न शा बनाना।

विध क\$ परींा पास क\$ हो।

(2) सां य क\$

उपिंथित एवं अभिलेख क\$ ०३ं तुित के

लिए विवश करने।

(6) समं त वन ००ेपाल, पहरं००े अधिकारी,

72 (b) सांय को बुनाने हेतु समन जारी करने

का अधिकार।

उप वन ००ेपाल या िपरं००े सहायक,

जि३ हश वन अपराध क\$ जाँच हेतु अधिकृत

8कया गया हो।

(7) समं त उप वन संरंक, वन

83 (1)

शासन क\$ बकाया राशि क\$ वसूली के लिये वनोपज

क, जे म डलाधिकारी, सहायक वन संरंक,

मश लेना।

उप वन म डलाधिकारी, वन ००ेपाल,

पहरं००े अधिकारी, या वन संरंक ३३३ारा

विशेष ३प से अधिकृत पहरं००े सहायक।

(8) कोई पुलिस वन या राजं व अधिकारी।

41

म. ०३. लांजिट (फारेट ० ०३ो३ूज) ३ल, 1961 क\$

धारा 24

के अ३ तगगत

42

वनोपज को परींण के लिये रोकना। (9) 1. उप वन म डलाधिकारी (०३ाधिकृत

52

(3) धारा 52 के अ३ तगगत ज० त वनोपज, वाहन, नाव, रं स को अधिकारी)।

राजसात् करना (confiscate)

2. वन म डलाधिकारी

(10) समं त रेटेड एवं चराई पास जारी करने

26 (2) a

आरिंत वन मश धारा 26(1) का ख ड (घ), (च),

(छ) मश

वाले वशडर।

वजगत काय क\$ अनुमित

देना।

धारा 76 (घ) के अ३ तगगत बने नियम - अधिसूचना ६. 11268दनांक 27-11-1911 एवं 2118दनांक 12-3-1912 :

(फारेट ० मै३ युअल पैरा 77 उधृत)

(1) वन अपराध कऽ जाँच पहरौंठे अधिकारी या उस पहरौंठे सहायक के द्वारा कऽ जावेगी जिसे वन माली डलाधिकारी ने इस हेतु अधिकृत ठकया हो।

साथ ही पहरौंठे सहायक द्वारा उसके ठं वयं के पकड़े करण कऽ जाँच तब तक नहल कऽ जावेगी जब ऐसा करने का विशेष, कारण न हो तथा उसे उस पहरौंठे अधिकारी द्वारा अनुमित दी हो जिसका वह मातहत है।

(2) जाँच समाप्त होने पर आगे ठकसी अधिकारी द्वारा, बिना वन माली डलाधिकारी कऽ पूर्वज्ञा वीकृति के, जाँच नहल कऽ जावेगी तथा ऐसी जाँच वन ाँठेपाल से अनन्य अधिकारी को नहल सपि जावेगी। यऽद वन ाँठेपाल उपलब्ध न हो तो पहरौंठे अधिकारी को दी जावेगी। यऽद अपराध, हरपोटका कऽ तारीख से तीन माह पूर्वका घटत आ हो, तो ऐसी जाँच वन माली डलाधिकारी द्वारा ठं वयं ही कऽ जावेगी।

(3) वन रोक, अपराध का पता लगने के 48 घंटे मऽ अपराध कऽ हरपोटका समीपं थ पहरौंठे सहायक या पहरौंठे अधिकारी को (जि३ ह३३ल (1) मऽ जाँच हेतु अधिकृत ठकया गया है) देगा।

(4) अपराध कऽ सूचना ाँठे त होने पर, पहरौंठे अधिकारी या पहरौंठे सहायक, जितनी जऽ दी संभव हो, यऽद वन पहरौंठे अधिकारी है तो अधिकतम एक माह तथा पहरौंठे सहायक है तो अधिकतम 15ऽदवस मऽ जाँच पूर्णकरेगा। जाँच पूर्ण करेगा। जाँच जहाँ अपराध घटत आ है, या पकड़ा गया है उस ठं थल या अ३ य उसके पास सुविधाजनक ठं थल पर कऽ जावेगी। यऽद आवं यक हो तो अ३ य ठं थल पर भी जाँच कऽ जा सकेगी यऽद अपराधी का उपिंथत रहना आवं यक न हो। पर जाँच अधिकारी तीन ऽदन मऽ पूरी होना चाहिए लेकन यह वन माली डलाधिकारी का अधिकार है ठक जाँच हेतु स३ तोषऽद कारण दशाकाने पर आठ ऽदवस तक अविध मऽ वृि कर दऽ। अविध समाप्त होने पर जाँच ाँठेवेदन, ३ल 7 या 8 मऽ दशाकाने अनुसार जाँच कायकावाही (Proceeding) के साथ ाँठे तुत कर दी जावे।

(5) इन िनयम के अ३ तगकानत जाँच करने वाला ाँठे येक अधिकारी, अपराध कऽ सूचना ाँठे त होने कऽ ितिथ से ाँठेकरण कऽ कायकावाही "केस डायरी" मऽ रखेगा। वह उस डायरी मऽ िनन बातऽ उऽ लेख करेगा :

- (1) समय व ऽदनांक जब सूचना आई।
- (2) जाँच के िलये जहाँ गये वह ठं थल का नाम व वहाँ कऽ गई कायकावाही।
- (3) साँ य को बुलाने एवं कथन लेने का िववरण।
- (4) अपराधी का कथन।
- (5) अ३ य कायकावाही का िववरण, जो ठक जैसे ठं थल िनरींण आऽद।

- (5) जाँच पूर्ण करने कऽ तिथि अंकित करेगा वह साँ यऽ के कथन लेगा तथा अपराधी का कथन लेखबऽ करेगा व उसके हँ ताँर करायेगा तथा यह ँ पऽ ट करेगा ठक अपराधी ँकरण मऽ राजीनामा करना चाहता है या नहऽकेवल िनयम (6) कऽ िंथित को छोड़कर जाँच पूर्ण होने पर ठकसी ३ यिऽ को रोका नहऽ जावेगा।
- (6) सामाऽ यतः अधिनियम कऽ धारा 64 के अऽ तगऽत ठकसी ३ यिऽ को तब तक िगरऽतार नहऽकया जावेगा जब तक उसका रहने का िनि त ढठकाना हो या भागने कऽ आशंका न हो। िगरऽतार ३ यिऽ को तऽ काल मिजँटेट के सऽ मुख ँऽ तुत ठकया जावेगा या िबना िवलऽ ब ठकये पुलिस मऽदया जावेगा।
- (7) (अ) यऽद जाँच अधिकारी को ँकरण का अभिसंधान (Compound) करने कऽ शिऽ है तो वह ँकरण का अभिसंधान करेगा तथा ितिपूऽतऽ कऽ रकम िनिअवऽ य देगा।

त करेगा, ठकऽ तु कायऽवाही कऽ सूचना वन मऽ डलाधिकारी को

- (8) यऽद जाँच अधिकारी ँकरण के अभिसंधान हेतु अधिकृत नहऽ है, या अपराधी ने राजीनामा देने से इंकार ठकया है, या उपिंथत होने से इंकार ठकया है, या िनयम (4) मऽ िनधाऽरत अविध मऽ जाँच पूर्ण नहऽ करवाई है तो वह ँकरण मय कायऽवाही के िवरण के, अपने से वऽरऽ ठ अधिकारी के माऽ यम से वन मऽ डलाधिकारी को ँऽ तुत करेगा। जाँच ढरपोटऽ के ँऽ त होने पर वन मऽ डलाधिकारी आवऽ यक आदेश दऽगे। जाँच पूर्ण न होने पर आगे जाँच हेतु आदेश दऽगे। लेऽकन यऽद जाँच मऽ सात ठदन से अधिक समय लगेगा तो इसका ँऽतिवेदन िडऽ टी किमँ नर (िजलाधीश) को भेजा जावेगा।

केवल जब कोई ३ यिऽ िनयम 6 के अऽ तगऽत िगरऽतार ठकया गया हो, को छोड़कर ठकसी ँकरण का ३ यायालय मऽचालान, िबना वन मऽ डलाधिकारी के आदेश, नहऽकया जावेगा। चालान हेतु पऽ३ यायाधीश को िलखा जावेगा तथा िनधाऽरत चालान फामऽ लगाया जावेगा। इसी ँकार िनयम 6 मऽ िगरऽतार ३ यिऽ का भी चालान बनाया जावेगा।

पैरा 77 (ब) िवभागीय आदेश ८. 1012-E-1968दनांक 27-4-28 ।

केस डायरी के िलये िनऽ न फामऽऽयुऽ त हऽगे :

अंऽी	िशऽूल IX	89
िहऽ दी	"	99

समँ त अधिकारी जो ँकरण का अभिसंधान करऽगे "फारेँ ट केस रिजँ टर" मऽ िवरण रखऽगे। यह रिजँ टर

िशऽूल IX के फामऽ पर होगा। इस रिजँ टर के िनऽ न िवरण हऽगे :

- (1) अनुक्रम (Serial Number)
- (2) अपराध होने का पी.ओ.आर. नंबर तथा ठेकांक
- (3) रिपोर्ट होने का या शिकायत या पता लगाने का ठेकांक।
- (4) अपराधी का नाम, पिता का नाम, निवास-स्थान एवं अपराधी का सामाजिक स्थिति।
- (5) चोरी के अकरण मश वनोपज का मूल्य या वन हानि के अकरण मश हानि का मूल्य यांकन।
- (6) जाँच का संविधान त विवरण व पाठ्य आदेश।
- (7) अधिकारी के हस्ताक्षर।

यदि एक अकरण के निष्कर्ष पर निष्कर्ष अधिकारी के ठेकांकत हस्ताक्षर होंगे।

यह रिजिस्टर वन मंत्रालय द्वारा जारी एक जनवरी, अक्टूबर, जुलाई व अक्टूबर क\$15 तारीख को जिले के कलेक्टर को उपस्थित ठेका जावेगा।

नोट : राजबाड़े समित के अतिवेदन पर शासन ने इस रिजिस्टर को कलेक्टर को उपस्थित करने क\$ आवश्यकता समाप्त क\$।

(फारेन टैक्स युअल पैरा 77(a) के अंतर्गत)

तदनुसार)

धारा 77. नियम के भंग के लिये शर्तियाँ - इस अधिनियम के अधीन ठेका नियम को, जिसके उल्लंघन के लिये कोई विशेष शर्त उपबिधत नहल है, भंग करने वाले व्यक्ति को ऐसी अविध के कारावास से जो छह मास तक का होगा और जुमाने से जो पचास हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

धारा 78. नियम को अविध का बल उत्पन्न होना - इन नियम के अधीन राज सरकार द्वारा बनाये नियम राजपत्र मश अकाशित ठेका जावगे और तदुपलर, जहाँ तक वे इस अधिनियम से सुसंगत ह., वहाँ तक वे इस प्रकार अभावशाली होंगे मानो वे इसमश अधिनियमत अए ह.।

1. वन अधिनियम 7 वर्ष 2010 द्वारा संशोधित।

2. वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 द्वारा संशोधित।

अध्याय 12

अक\$ण (Miscellaneous)

s)

धारा 79. वन अधिकाइरय एवं पुलिस अधिकाइरय को सहायता देने को आब ३ यि - (1) हर ऐसा ३ यि, जो ठकसी आरिंत या संरिंत वन मंठकसी अधिकार का ेयुग करता है, या जो ऐसे वन से, ठकसी वन उपज को लेने या इमारती लकड़ी काटने और हटाने या उसमंठ ढोर चराने के िलये अनुीत है, और हर ३ यि जो ऐसे वन मंठकसी ऐसे ३ यि द्वारा िनयोिजित है, और

ऐसे वन के समीप थ ठकसी ढाम का हर ३ यि जो सरकार द्वारा िनयोिजित है या जो समुदाय ेयुत कऽ जाने वाली सेवा के िलये सरकार से उपलिध्याँ पाता है, ऐसी जानकारी, जो ठकसी वन िवषयक अपराध के ठकये जाने के आशय कऽ उसके पास है, िनकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी को अनावं यक िवल ब के िबना, देने के िलये आब होगा, और

(क) ऐसे वन मंठ वन अि को, िजसके बारे मंठ उसे िान या जानकारी हो बुझाने के िलये,

(ख) ऐसे वन के समीं य मंठकसी अि को, िजसके बारे मंठ उसे िान या जानकारी है, अपनी शि के अनुसार ठक हल वैध साधन द्वारा, ऐसे वन मंठ फैल जाने से रोकने के िलए,

तुरंत कायवाही करेगा चाहे उसे ठकसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसी अपेी कऽ गई हो या नहल, और

(ग) ऐसे वन मंठ वन िवषयक अपराध रोकने, और

(घ) जब ठक यह िव वास करने का कारण है ठक ऐसे वन मंठ ऐसा कोई अपराध ठकया गया है तब अपराधी का पता लगाने और उसको िगरतार कराने मंठ उसकऽ सहायता माँगने वाले ठकसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी कऽ सहायता करेगा।

(2) कोई ३ यि, जो ऐसा करने के िलये आब होते शए भी िबना ठकसी िविधपूण ेयुत हेतु (Law full excuse) िजसे सािबत करने का भार उसको होगा :

(क) उपधारा, (1) द्वारा अपेीत जानकारी िनकटतम वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, को अनावं यक िवल ब के िबना नहल देगा,

(ख) ठकसी आरिंत या संरिंत वन मंठ वन अि (Forest fire) के बुझाने के िलये उपधारा (1) द्वारा यथा- अपेीत कायवाही नहल करता।

(ग) ऐसा वन के सामं य मंठ कऽ ठकसी अि को ऐसा वन मंठ फैलने से नहल रोकेगा जैसा ठक उपधारा (1) से अपेीत है, या

(घ) ऐसे वन मंठकसी अपराध का ठकया जाना रोकने मंठ, या उस दशा मंठ, िजससे ठक यह िव वास करने का कारण है ठक ऐसे वन मंठ ऐसा अपराध शआ है, अपराधी का पता लगाने और उसे िगरतार करने मंठ उसकऽ सहायता माँगी जाने पर ठकसी वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी कऽ मदद नहल

करेगा, वह ऐसी अविध को कारावास जो (छः मास) तक कऽ हो सकेगा और जुमाने से जो (एक हजार रुपये) एक का हो सकेगा, या दोन से, द डनीय होगा।

हटो पणी - धारा 79 इस धारा के अधीन वन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी को वन अपराध रोकने मऽ सहयोग दान करने कऽ यवऽ था है। ऐसी ही यवऽ था भारतीय द ड डया संहिता, 1973 कऽ धारा 37 मऽ है तथा सहायता न देने वाले यि के विध धारा 187 का अपराध माना गया है।

धारा 80 उन वन का डध जो सरकार एवं अ य यि कऽ संयु त स पिड है -

(1) यद सरकार और कोई यि डकसी वन या पड़त (Waste) भूमि मऽ, या उसकऽ पूरी उपज या उसके डकसी भाग मऽ संयु त िहतब है तो रा य सरकार या तो :

(क) उसमऽ ऐसे यि को, उसके िहत के िलये लेखा देते शए, ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज का डध अपने हाथ मऽ ले लेगी, या

1.

वन अधिनियम 9 वर्ष 1965 ारा संशोधित।

(ख) इस डकार संयु ततः िहतब यि ारा वह पड़त भूमि या उपज का डध करने के िलये ऐसे िविनयम जारी कर सकेगी जैसे वह उसके डध और उसमऽ के सब िकार के िहत मऽ आवऽ यक समझती है।

(2) जब डक उपधारा (1) के ख ड (ख) के अधीन सरकार डकसी वन या पड़त भूमि या उपज का डध अपने हाथ मऽ लेती है, तो वह राजपू मऽ अधिसूचना ारा यह घोषित कर सकेगी डक ऐसे वन, पड़त भूमि या उपज पर अ या य 2 या अ या य 4 मऽ अ तवऽ ट कोई उपब ड उन पर लागू हगे और तदुपऽर ऐसे उपबंध तनुसार लागू हगे।

धारा 80 (अ) अनिधकृत ाप आरित या संरित वन कऽ भूमि पर क जा रखने के िलये शाित -

(1) ऐसे ित कऽ भूमि जो धारा 20 या 29 के अधीन आरित या संरित वन है के डकसी भूख ड पर कोई यि अनिधकृत ाप से क जा करता है या क जे मऽ रखता है, जैसा भी हो, इस अधिनियम के अनतगऽत उसके विध अ य कोई कायऽवाही जो क जा सकती है, पर ितकूल डभाव डाले िबना, वन अधिकारी, जो वन म डलाधिकारी के पद से िन न हो, के आदेश ारा, संित ाप से (Summarily), बेदखल (Ejected) डकया जा सकता है और उस पर खड़ी फसल, या भवन, या अ य जो उस भूमि पर बनाया हो (Constructed), यद अभयु त ारा, वन म डलाधिकारी ारा िनयत अविध मऽ नहऽ हटाई जावे, तो ऐसी िथित मऽ वे सभी राजसात् (Forfeiture) यो य ह. :

पर३ तु ऐसे बेदखली आदेश, उपरो३ त उपधारा के अ३ तग३णत, जब तक पा३रत नह३कये जाव३गे तब तक ३क ऐसे ३३ ता३वत बेदखली ३कये जाने वाले ३ यि३ को, समु३चित कारण बतलाये जाने का अवसर ३दान न ३कया गया है ३क उपरो३ त आदेश ३ य३ न पा३रत ३कये जाव३गे?

(2) ऐसी स३ पि३, जो राजसात् क३ गई हो, का ३ ययन (Disposal) वन अधिकारी के आदेशानुसार होगा। ३कसी

भी फसल, भवन या अ३ य िनमा३ण काय३ण, जो भूमि को मूल ि३थित म३ लाने के िलये हटाये जाव३गे, उसक सम३ त ३ यय उस ३ यि३ से धारा 82 के अ३ तग३णत ३दये ३वावधान से वसूली यो३ य होगा।

(3) कोई ३ यि३, जो वन अधिकारी क३ उपधारा (1) के अ३ तग३णत पा३रत आदेश से अस३ तु३ ट है, व ऐसी री३त या समयाविध म३ (जो िनि३ चत क३ गई हो) रा३ य शासन या रा३ य शासन ३३३ारा ३वा३धकृत अ३ य अधिकारी के सम३३ अपील कर सकता है और उ३ त अधिकारी का आदेश, उ३ त अपील के िनण३णय के अ३ यधीन रहते ३ए अ३तम होगा।

(4) इस धारा के ३वावधान, उन ३३३े३ तथा उन ितिथय३ से ३वृ३ त ह३गे, जैसा ३क रा३ य शासन िविन३द३ण ट करे। अलग-अलग ितिथय३ िनधा३णरत क३ जा सकती ह३।

म. ३. शासन सूचना ३. 11658/X/65 रा३ य शासन धारा 80(अ) क३ उपधारा (3) के अ३ तग३णत 'उपसिचवत म३ य ३देश शासन' को अपील अधिकारी िनयु३ त करता है।

म. ३. शासन अधिसूचना ३. 6342/X/66३द. 24-6-66 ३३३ारा शासन िबलासपुर िजले म३ धारा 80(अ) के ३वावधान लागू होने क३ ितिथ 1 जुलाई, 1966 िनयत करता है।

म. ३. शासन अधिसूचना ३. 5322/X/67३द. 14-6-67 जो म३ य३देश राजपू३द. 20-3-67 (असाधारण)

पृ३ ठ 640 पर ३का३शित म३ य ३देश शासन िन३ न िजल३ म३ धारा 80(अ) क३ उपधारा (4)

म३३द३ त शि३य३ के उपयोग म३ लाते ३ए ३दनांक 20-3-1967 से उ३ त धारा के ३वावधान लागू करता है।

(राजपू३द. 16-6-67 पृ३ ठ 1814)

(1) *पूव३ िनमा३ (2) *सीधी (3) *सरगुजा (4) *सीहोर (5) *रायगढ़ (6) *दुग३ण (7) *ब३ तर (8) *सागर (9)

*जबलपुर (10) *बालाघाट (11) *दमोह (12) *म३ डला (13) *सिखनी (14) *नर३संहपुर (15) *रायसेन (16) *छि३

दवाडा (17) *होशंगाबाद (18) *बतूल (19) *शजापुर (20) *राजगढ़ (21) *वि३दशा (22) *वा३लियर (23) *भि३ ड

(24) *शिवपुरी (25) *मुरैना (26) *गुना (27) *दितया (28) *इ३ दौर (29) *उ३ जैन (30) *देवास (31) *धार (32) *सतना

(33) *रतलाम (34) *पि मी िनमा३ (35) *म३ दसौर (36) *रीवा (37) *प३ ना (38) *सतना (39) *शहडोल (40)

*छतरपुर (41) *टीकमगढ़ (42) *रायपुर।

वन विधान ८. 9 वर्ष 1965 कऽ धारा 17 से धारा 80 अ जोड़ी गई ।

हटो पणी धारा 80-(A) (1)

(1) धारा 80 (A) के अधीन बेदखली होने वाला ेे धारा 20 या 29 के अधीन आरिंत या संरिंत वन होना चाहिये।

(2) अनाधिकृत कृ जा करना या कृ जा बनाये रखना

(1) अनाधिकृत रूप से कृ जा करना - वां यांश मशु यि को ेार भ मश ही कृ जा विवाहदत भिम पर करने का कोई अधिकार नहल होता है वह जबरदं ती कृ जा करता है, उसके पास कोई परिमट, लायसेंस, पंा या कोई ेाधिकार ढकसी ेकार का नहल होता है और वह उसके बावजूद कृ जा बिना ढकसी ेाधिकार के कर लेता है ;

(2) अनाधिकृत रूप से कृ जा बनाये रखता है या कृ जे मश बना रहता है - इस वां यांश का अथ ेयह हो सकता है ढक यि का ऐसी भूमि का भले ही ेार भ मश कृ जा ेाधिकृत रहा हो लेढकन कानून (IF Act) या उसके अधीन बनाये गये िनयम के उपबं ध के अधीन ढकसी यि को ढकसी भूमि पर कृ जा रखने का अधिकार समां त हो जाता है तो वह कानूनी रूप से अधिकार कऽ समां हो जाना कहा जाता है और विविध के अधीन कृ जे को अधिकार समां त होने के बावजूद यि विवाहदत ें नाधीन भूमि पर अनाधिकृत रूप से कृ जा बनाये रखता है अथा ेत् भूमि पर कृ जे मश बना रहता है तो वह धारा 80(1) के अधीन बेदखली के यो य हो जाता है।

(3) बिडग मश फनटचर आढद रखा हो या अं य सामान रखा हो उसे समपत नहलढकया जा सकता उसके forfeit करने का अधिकार नहल है - Marandmal Vs. State of M.P. 1981/MPLJ/Note 55=1981 (II) MPWN 118=1981 RN 349 RN 349 पैरा 3 हाईकोट ेन (म. े.)

(4) कृ जा अनाधिकृत (unauthorised) होना चाहिये - महाराज ःसंह वि. ँ टेट म. े. - 1979 रा. िन. 82, देवीःसंह वि. ँ टेट म. े. 1979 रा. िन. 355 (पैरा 4)

(5) केउं सरकार के ँ वािमं व कऽ भूमि पर जो पि लक ेेिमसेज (Eviction of unauthorised occupants Act 1971) एं ट 1971 मश आती है उसकऽ धारा 5 के अधीन (Estate Officer) स पदाधिकारी ही बेदखली कऽ काय ेवाही कर सकता है। उस एं ट कऽ धारा 15 मश अं य कोट ेन कऽ अधिकाइरता व ेज ेत है - (े भूनाथ वि.

बोड ेन रेउ हउ यू - 1980 MPLJ 522 = 1980 JIJ 620 डीबी हाईकोट ेन म. े.)

नोटिस शो-काज ठं पट होना चाहिए - बाबूलाल वि. ठं टेट म. ०२. 1983RN 27 पैरा 2 रे३ ह३ यू बोड३ म. ०२.

आरि३त वन एवं संरि३त वन भूमि म३ लै३ ड रे. को. म. ०२. क३ धारा 248(1) तथा धारा 1(2) के अनुसार काय३वाही नह३क३ जा सकती। केवल धारा 80(1)(IF Act) के अधीन ही काय३वाही बदखली क३ जा सकेगी - भगवान दास वि. ठं टेट म. ०२. 1981रा. िन. 243(V.P.Sheth M.BR)

आरि३त वन एवं संरि३त वन तथा अ३ाधिकृत क३ जा साबित करने का ०२भार-रा३ य सरकार पर है - अजीजु३ ला खान वि. ठं टेट म. ०२. 1980 रा. िन. 308 (308) पैरा 3, 4 अजु३ी वि. ठं टेट म. ०२. 1983 NR 86 रे. वो. सौभाग वि. ठं टेट म. ०२. 1979 रा. िन. 428 पैरा 6 (रे. बोड३)

धारा 80 (IF Act) - गवन३मे३ ट और अ३ य३ यि३ क३ संयु३ त स३ पि३ म३ संयु३ त ३प से वन, पड़त भूमि या उपज म३हितब३ता होने पर धारा 80(1) के अधीन गवन३मे३ ट ०२ब३ ध को अपने क३ जे म३ धारा के ०२ावधान३ का पालन करते ३ए ले सकती है और धारा 80 (2) (IF Act) के अधीन अ३ याय II तथा IV के ०२ावधान लागू कर सकती है अ३ याय II तथा IV (IF Act) के लागू कर ३दये जाने पर आपि३कता३ क३ जेदार को आपि३ करने का और अधिकार३ के विनि३ चय कराने का माग३ उनम३ बताये ०२ावधान३ के अधीन खुल जाता है। अ३ याय II म३ आरि३त वन का स३ ब३ ध है तथा अ३ याय IV म३ संरि३त वन का स३ ब३ ध है।

िसिवल कोट३ म३ हम के आधार पर यह ठं थापित करने क३ ०२ाथ३ना क३ जा सकती है ३क विवा३दत भूमि वन भूमि या पड़त भूमि नह३ है और वादी का वैधानिक अधिकार है - (नब३दा ०२साद वि. म. ०२. रा३ य 1990 रा. िन. 388- पैरा 3 हाईकोट३ म. ०२.)

रे३ ह३ यू-पटवारी कागजात म३ विवा३दत भूमि "आरि३त वन" दज३ है। इस भूमि पर म. ०२. ले३ ड रे३ ह३३ यू कोड, 1959 लागू नह३ होगा। ँजनंदन ३संह वि. ठं टेट म. ०२. - 1983 - रा. िन. 95 पैरा 7 रे. बोड३; म. ०२. धारा 80 (अ) के अ३ तग३त अपील

िनियम 80 अ के वि३ा अपील (िनियम)

म३ य ०२देश शासन अधिसूचना ६. 7356/X/65 ३दनांक 26-6-65 : रा३ य शासन धारा 80 (अ) क३ उपधारा

(3)३३रा ०२द० त शि३य३ को उपयोग करते ३ए िन३ न िनियम बनाता है :

(1) इस िनियम म३ अधिनियम से ता० पय३ भारतीय वन अधिनियम, 1927 (वष३1927 के (16) से है।

(2) कोई३ यि३, वन अधिकारी ३३रा धारा 80 (अ) क३ उपधारा (1) के अ३ तग३त पा३रत आदेश क३ सूचना ०२ा३ त होने पर, 60३दवस के भीतर अपील कर सकता है।

(3) ०२० येक अपील िन३ न री३त म३ होनी चाहिये :

(क) वह लिखित मं हो।

(ख) उसमें अपीलार्थ का नाम व पता हो।

(ग) यह विशुट विवरण हो कि कस तिथि के आदेश के विरुद्ध अपील कइ गई है।

(घ) अपीलार्थ को आदेश कइ सूचना कस तिथि को र्जात शई।

(ङ.) विशुट तः य का विवरण।

(च) अपील करने का कारण व आधार सुसंगत व सिलसिलेवार दज्गल हो।

(छ) कस बात कइ आ र्जि कइ मांग कइ गई का समावेश हो।

(ज) निनुानुसार अपीलार्थ या उसके अधिकृत एजेट द्वारा हं तर्जित एवं सो यापित हो :

म. (अपीलार्थ), एतद् द्वारा यह घोषणा करता हं कि उपरोक्त अपील र्पाप मं अंकित और ऊपर जो बात र्दक्षित कइ गई ह., मेरी र्पिगत जानकारी एवं विरं वास से सही है।

हं तर्जित

- (4) अपील का र्पापन, जिस आदेश के विरुद्ध कया गया हो, उसकइ अभिरमाणिता र्जितिलिप के साथ संलग्न न होना चाहिये, बशतः अपीलीय अधिकारी को सउ तुट कर दे कि कौन से अल्ले कारण से उसने अभिरमाणिता र्जित र्जं तुत नहल कइ है और अपीलार्थ को, अपीलीय अधिकारी के आदेश कइ र्जित देने हेतु यथा-समय जो शु, क/अभिलेख/अपील अधिकारी नि त करे, र्जं तुत करना होगा।
- (5) अपील का र्पापन या तो अपीलार्थ द्वारा या उसके अधिकृत एजेट द्वारा रं वयं अपीलीय अधिकारी को र्जं तुत करना चाहिये या डाक द्वारा र्जेषित करना चाहिये।

नोट - उपसिचव, म. र्ज. शासन, वन विभाग अपील अधिकारी मनोनीत कये गये ह।

(अध. 1. 11685-C-65 कद. 19-11-65 राजपुठद. 19-11-65 पृठ 1587 पर र्जकाशित)

धारा 81. ऐसी सेवा करने मं असफलता जिसके लिये सरकारी वन कइ उपज के कसी अंग का उपयोग कया जाता है - यक कोई र्पि, कसी ऐसे वन कइ उपज को या वन उपज के कसी भाग को, जिस पर सरकार का सल पिठक अधिकार है या उसकइ हकदार है, का अंश इस शतक पर हकदार है कि ऐसे वन मं सल बिधत सेवा, सल यक् र्प से करता रहेगा, तो सउ य सरकार का समाधान कर देने वाले र्प मं यह तः य र्जमाणिता हो जाने कइ दशा मं कि वह अब ऐसी सेवा नहल कर रहा है, ऐसी अंश अधहरणीय हो जावेगा :

पर 3 तु जब रा 3 य सरकार द्वारा, स० यक् ३५ से नियुक् त अधिकारी द्वारा हकदार ३ यि० क\$, और ऐसे सां य क\$ (यह कोई हो) जिसे वह सेवा के स० यक् ३५ मंठकये जाने के ०२माण ठं व ३५ ०२ं तुत करे, सुनवाई न करे, तब तक ऐसे अंश का अधिहरण नहल होगा।

हट ० पणी-धारा 81

1. इस धारा मं वन उपज सरकारी स० पिछया सरकारी हकदारी मं कोई भाग/अंश या िहं सा ठकसी ३ यि० को सेवाएँ देने के एवज मं (बदले मं) (in consideration) मं ०२तिफल ठं व ३५ ठदया जाता है और ऐसा ३ यि० सेवाएँ आगे नहल देता है तो रा 3 य सरकार, सेवाएँ न देने पर, उस ३ यि० के वन उपज मं हक के अंश या भाग को अधिहृत (confiscate) कर सकती है।
2. ठक 3 तु ऐसी अधिहरण क\$ कायफवाही के पूर्वफ स० बिधत हकदार ३ यि० को कारण बता० नोहटस देकर उसे पृ० टीकरण देने का तथा सेवायं यथावत जारी होने के ०२माण मं सां य देने का अवसर देकर सुनवाई करना होगी।
3. सहज 3 याय का िस०ा 3 त है ठक जिस कायफवाही से ३ यि० के स० पिछ स० ब 3 धी अधिकार पर ०२तिकूल ०२भाव पड़ता है उस कायफवाही मं उसे कारण बता० नोहटस देकर जवाबदेही का एवं सां य का युि०यु० त अवसर देकर सुनवाई क\$ जाना चाहिये और ०२ाधिकारी को उसके जवाब एवं सां य पर विचार करके उपयु० त 3 यायोचित िन० कषफ िनकालना चाहिये। रा 3 य सरकार या ०२ाधिकारी को यह समाधान या संतुि० कर लेना होगी ठक सेवायं अपेि०त आगे नहल दी गई ह। उनका पालन नहलठकया गया है और यह समाधान/संतुि० 3 यायोचित जांच से ही होगी।

धारा 82. शासन को देय, बकाया रािश क\$ वसूली - अथफद (Fines) के अतिहर० त सभी रािशयाँ जो इस अधिनयम के अ 3 तगफत रा 3 य शासन को देय ह०, या उसके अधीन बनाये गये ठकसी िनयम के अ 3 तगफत या इमारती लकड़ी के या अ 3 य वनोपज के ठेके के कारण या इमारती लकड़ी या अ 3 य वन उपज के स० ब 3 ध मं ठकसी संविदा के कारण, िजसमं संविदा भंग के कारण वसूली यो० य रकम शािमल है, या संविदा के र० करने के फलं व ३५, या इमारती लकड़ी के विदय स० ब 3 धी नोहटस क\$ शतफ के अ 3 तगफत, अ 3 य वनोपज क\$ नीलामी द्वारा या िनिवदा आमंण जो ठक वन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी क\$ गई हो, और समं त ितिपूतफ (Compensation) जो इस अधिनयम द्वारा रा 3 य शासन को ०२दान ठकया जाना हो यहद िनि त समय मं नहल पटाई जावे तो वह त० समय ०२भावशील विधान के अ 3 तगफत इस ०२कार वसूल ठकये जा सकंगे जैसे यह रािश राजं व क\$ बकाया रािश हो।

हटो पणी (1) धारा 82 के अधीन यद्द कोई ठेकेदार ने वन विभाग से कोई वनोपज का ठेका लिया है तथा बयाने कऽ रकम जमा कराई है, ठेकेदार द्वारा शेष रकम न पटाने के कारण, दोबारा नीलाम मऽ पिहले से कम मू५ य ोत त होने पर, ऐसी हांन कऽ रांश बकाया भू-आगम के ऽप मऽ वसूल नहऽ कऽ जा सकती। ऐसी रांश ३ यवहारवाद मऽ वसूल होगी।

(देखऽ AIR 1967 सु०ीम कोटऽन 203, 206, 207) जबलपुर लॉ जनऽल 1970 हटो पणी ८. 82)

हटो पणी (2) यद्द रा३ य शासन के अधिकारी वनोपज कऽ िबऽ करते ह. तो उस मू५ य पर देय िवऽय कर कऽ रांश भूराजं व के सऽ य वसूली यो य है।

(देखऽ - ओरय३ ट पेपर िम. िव. म. ०५. रा३ य, म. ०५. लॉ जनऽल 1971, पृ० ठ 514)

हटो पणी (3) धारा 82 मऽ म॥ य ०देश संशोधन (८. 9, वषऽन 1965) के अ३ तगऽनत वनोपज के नीलाम होने पर, शत के उ५ लंघन के फलं वऽप, पुनः नीलाम होने पर यद्द कम रांश ०५ त होती है; तो वह धारा 82 के अ३ तगऽनत वसूली यो य है। (M.P.L.J. 1980, 465 P.B.)

हटो पणी (4) उपवन मऽ डलाधिकाऽरय को बकाया रांश कऽ वसूली कऽ शि - अधिसूचना ८. 7-21 सात-सा. 7- 78 दनांक 19 जुलाई, 1979 - म. ०५. भू-राजं व संहिता, 1959 (८. 20 वषऽन 1959) कऽ धारा 25 कऽ उपधारा (1) द्वारा ०द० त शि य को ०योग मऽ लाते ऽए रा३ य सरकार एतद् द्वारा रा३ य के समं त उपवन मऽ डलाधिकारी को वे शि य ०दान करती ह. जो ऽक उ त संहिता कऽ धारा 146 तथा 147 द्वारा ऽकसी तहसीलदार को ०दाय कऽ गई ह., और यह िनदऽश देती है ऽक वे इस ०कार ०द० त कऽ गई शि अपनी-अपनी अधिकाऽरता के ०भार िे (Jurisdiction) मऽ ऐसे बकाया धन कऽ वसूली हेतु ०यु त हगी जो ऽक -

- (1) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (८. 16, वषऽन 1927) कऽ धारा 82 के अधीन भूराजं व कऽ बकाया के तौर पर वसूली यो य रांश और
- (2) रा३ य सरकार के वन विभाग के ऐसे कोई अनुदान, अनुब३ ध, प०ा (Leases) या संविदा के

अधीन शोध हो िजसमऽ यह उपब३ ध हो ऽक वह (धन) उस रीति से वसूली यो य है जैसे भू-राजं व कऽ बकाया के तौर रांश वसूल कऽ जाती है।

1. म.०५. विधान ८. 9 वषऽन 1965 कऽ धारा 18 द्वारा ०रितं थापित ।

हटो पणी (5) अभिसंधान ऽकये गये ०करण मऽ बकाया रांश कऽ वसूली - जब वन विभाग धारा 68 के अ३ तगऽनत राजीनामा लेता है, तो ०करण मऽ आयद कऽ गई रकम, धारा 82 के अनतगऽनत भू-राजं व के बकाया के समान वसूल कऽ जा सकती है।

धारा 83. ऐसे धन के लिये वन उपज का धारणाधिकार (Lien)

(1) जब ठकसी वन उपज के सब धन या उसके लिये कोई राशि देय है, तब ऐसी उपज पर उसका वसूली का प्रथम भार है ऐसा समझा जावेगा, और जब तक ऐसी राशि चुका नहीं जावे, तब तक के लिये, वन अधिकारी ऐसी वन उपज, अपने कर्ज ले सकेगा।

(2) जब यह राशि शीघ्र (Due) होती है, तब चुका नहल दी जाती है, तो वन अधिकारी द्वारा ऐसी उपज का लोक नीलाम (Public auction) द्वारा विवलय ठकया जा सकेगा, और विवलय के आगम को प्रथमतः ऐसी बकाया राशि को चुकाने मःठकया जावेगा।

(3) यःद कोई धन उत बकाया राशि, चुकाने पर अतिशेष रहे, उसके लिये यःद हकदार यि द्वारा विवलय कःतारीख से दो माह के भीतर, दावा नहलठकया जाता तो वह सरकार को समपःत (Forfeited) हो जावःगी।

हःटः पणी (1) - यह धारा वन अधिकाःरय को (1) वनोपज कः जः ती (2) तथा उसके विवलय के अधिकार देती है, ठेकेदार द्वारा ठकः त न पटाना वन िनिवदा कः शत का बड़ा उः लंघन है तथा इस उः लंघन के लिये कटाई व ढुलाई का कायःण रोक जा सकता है तथा िनयम 29 के अः तगःणत वन संरःक द्वारा िनिवदा समाः त कः जा सकती है तथा ऐसी िनिवदा कः समाःि पर ठेका िःोः (Contract area) मः अवशेष वनोपज शासन कः सः पिट हो जाती है।

(म. ः. शासन वि. सरदार बूटासंह राजनाः दगांव, 1972 MPLJ 392, AIR 1972 MP 116)

हःटः पणी (2) - धारा 82 एवं 83 एक दूसरे के पूरक ह. तथा बकाया वसूली हेतु दोनः विधयाँ कायाःणःवत कः जा सकती ह.। (AIR 1980 All 100 & 213)

धारा 84. इस अधिनयम के अधीन अपेःित भूमि के लिये यह समझा जावेगा ठक उसका आवः यकता भू-अजःण अधिनयम (1994 का 1) के अधीन लोक ःयोजन के लिये ह. -जब कभी राः य सरकार को ऐसा ःतीत होता है ठक इस अधिनयम के ःयोजन मः, ठकसी ःयोजन के लिये कोई भूमि अपेःित है तो ऐसी भिम के बारे मः यह समझा जावेगा ठक भूमि अजःण अधिनयम, 1894, कः धारा (4) के अथःण के अः दर उसका लोक ःयोजन के लिये आवः यकता है।

धारा 85. बः धपः के अधीन शीघ्र य शिंतय कः वसूली - जब कोई यि, इस अधिनयम के ठकसी अनुबः ध के अनुसार या उसके अधीन बनाये गये ठकसी िनयम के अनुपालन मःठकसी बः धपः (Bond) या िलिखत (Instrument) द्वारा ःसंविदा (Binds) करता है ठक वह उसके सेवक या उसके अभकः ताःण ठकसी कायःण को नहल करःगे, तब भारतीय संविदा अधिनयम, 1872 (1872 का 9) कः धारा 74 मःठकसी बात के होते ःए भी ऐसे बः धपः या िलिखत मः जो राशि उनका शत के भंग होने कः दशा मःदी जाने वाली राशि के ःप मः वःणःणत है, ऐसे भंग होने कः दशा मः उस समं त राशि को ऐसे वसूल ठकया जा सकेगा मानः वह राशि भू-राजं व कः बकाया है।

धारा 85-क. के३००ीय सरकार के अधिकार के िलये ३ यावृि - इस अधिनियम कऽ कोई बात ढकसी रा३ य सरकार को उस रा३ य के बाहर कऽ स॒ पि॒ के स॒ ब३ ध म३ कोई आदेश देने या कोई काय॒ करने के िलये स॒ पृ॒ त सरकार कऽ स॒ मित के िबना के३००ीय सरकार या अ३ य रा३ य सरकार के ढक३ ह॒ अधिकार पर अ३ यथा ॒ कूल ॒ भाव डालने के िलये ॒ ाधिकृत नह॒ करेगी।

यह धारा रा॒पित के एडो॒ टेसन आड॒र, 1950 (Adoption Order, 1950)॒ ारा ॒ तं थापित

धारा 86. िनरसन

६ट॒ पणी - इस धारा के अ३ तग॒त अनुसूची म३ बनाये गये िवधान के िनरसन बतलाया गया है तथा यह धारा िनरसन संशोधन अधिनियम, 1984 (िवधान ८, वष॒ 1984) कऽ धारा 2 के अ३ तग॒त बनाई गई अनुसूची के साथ िनरं त कर दी गई है।

म॒ य॒ देश वन सुर॒ ा पा॒रतोषित िनयम 2004

1. संि॒ त नाम, िवं तार, लागू होना :

- (1) ये िनयम वन सुर॒ ा पा॒रतोषित िनयम 2004 कहलाव३गे।
- (2) ये पूरे म॒ य॒ देश रा३ य म३ लागू ह॒गे।
- (3) ये िनयम, इनके म॒.॒. रा३ य प॒ म३ काशन कऽ ितिथ से लागू ह॒गे।

2. प॒रभाषाएं : इन िनयम म३, जब तक स३ द॒ म३ अ३ यथा आपेि॒ त न हो :

- (a) अधिनियम से ता॒ पय॒ भारतीय वन अधिनियम 1927 (XVI वष॒ है 1927)
- (b) 'वन संर॒क' से ता॒ पय॒ वह अधिकारी फोरे॒ ट सरकर का ॒ भारी अधिकारी हो या रा३ य सरकार

॒ ारा

घोषित अ३ य अधिकारी जो उसके समक॒ घोषित ढकया गया हो।

- (c) वन म॒ डलाधिकारी से ता॒ पय॒ वह अधिकारी है जो वनम॒ डल के ॒ भार म३ हो।
- (d) 'अ३ य वं तु' से ता॒ पय॒ वाहन, औजार, पशु, हिथयार, टू॒ स आ॒द है जो वन अपराध का॒रत करने म३ उपयोग म३ लाये गये हो।

इन िनयम म३ जो श॒ द तथा अभ॒ यि॒ योग म३ लाई गई है ले॒कन उनको प॒रभाषित नह॒कया है, उसका वही अथ॒

होगा जो उसके लिये अधिनियम मंजूर किया गया हो।

3. पाहरतोषिक :

(1) वन अपराध मंजूर त अपराधी को, 3 यायालय द्वारा दोषिसंभलके जाने पर, या वन अधिकारी

द्वारा

संशमन करने पर, वन मंजूर डलाधिकारी उस 3 यिं या 3 यिंयं को, जिं हने वन अपराध का पता

लगाने, या अपराधी को पकड़ने या अपराधी को दोषिसंभल कराने या वन उपज तथा अं य वं तु

राजसात करने मंजूर असामां य, सहायता कं हो तथा राजसात कं वं तु का मू, य 25000/- के

आसपास या अधिक हो, तो वन मंजूर डलाधिकारी उसको पाहरतोषिक दे सकता है। पाहरतोषिक कं

रांश संकरण मंजूरानं त तंतिपूतंन से अधिक नहल होगी।

(2) पाहरतोषिक कं रांश 10,000/- या अधिक हो तो वन संरंभक कं पूवंन अनुमित ली जावेगी।

(3) पाहरतोषिक वन विभाग मंजूर उपवन मंजूर डलाधिकारी तथा पुलिस मंजूर उपजला अधींभक से उं च अधिकारी को देय नहल है।

(4) वीकृत अधिकारी : पाहरतोषिक कं रांश वन मंजूर डलाधिकारी ं वीकृत कर सकते है।

(5) पाहरतोषिक कं रांश कं वसूली यंद पुरं कार देने के पं चात् अपराधी अपील मंजूर दोषमुं त हो जाता

है तो पुरं कार कं रांश कं वसूली नहल होगी। जब तक संकरण मंजूर कोई धोखाधड़ी न कं गई हो।

(6) पाहरतोषिक गोपनीय होगा तथा वन विभाग कं गुं त निंध' से ं वीकृत कया जावेगा। तथा सूचना

दाता का नाम गुं त रखा जावेगा। उसका 3 यायालय मंजूर परींभ नहल होगा वन मंजूर डलाधिकारी

कांभटं जेट मद से यह रांश भुगतान कर सकते हं।

(7) इन नियमं के लागू होने पर इससे सं बिंभत, इस विषय के पूवंन के समं त नियम समां त हो जावंगे,

लेकन इन

समां त नियमं के अं तगंनत कं गई कायंनवाही को इन नियमं के अं तगंनत कं गई कायंनवाही माना जावेगा।

अंध. 25.10.2004-X-38दनांक 5 अगं त 2005

पहरतोषिक नियम (3) का संवधान वन संाणियं का शिकार या ऐसी वनोपज जिसका मू, य निंधाकरण

करना संभव न

हो पर लागू नहल होगा।

1. ये िनयम म.०. राजपू असाधारण ढदनांक 30.10.04 के पृ ठ 998 पर ०कािशत।

